सूर्योदय 5:54 सूर्यास्त 6:52

आज का तापमान

शिमला	17.2 न्यू	24.5 अधि
धर्मशाला	17.2 न्यू	30.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	77,656
निफ्टी	24,334

सोना 1,62,000 चांदी 2,43,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 26 अगस्त 2026 | 10 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 121, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज

पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, वाटर कैनन चली, टीआरई-4 एग्जाम में बदलाव की मांग

एजेंसी, पटना। बिहार में सरकारी भर्तियों को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। पटना के गर्दनीबाग में 18 अगस्त से धरने पर बैठे छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन (एबीएसयू) के छात्र नेता अमन गुट के नेतृत्व में निकले इस मार्च को रोकने के लिए प्रशासन ने जेपी गोलंबर पर भारी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की थी।

मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेपी गोलंबर पर लगाए गए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और डाकबंगला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और तनातनी की स्थिति उत्पन्न हो गई। गांधी मैदान से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गर्दनीबाग में पिछले कई दिनों से धरना दे रहे छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को छात्रों ने धरना स्थल से मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च शुरू किया। प्रशासन ने पहले ही जेपी गोलंबर सहित प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी। छात्र जैसे ही जेपी गोलंबर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति बन गई।

पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी रहीं। प्रदर्शन के कारण पटना के कई प्रमुख मार्गों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और यातायात भी प्रभावित होने की सूचना है। आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांग बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट करना है।

100% डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग

छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को बार-बार अलग-अलग परीक्षाओं में शामिल नहीं होना पड़े। उनका तर्क है कि इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी होने के साथ अभ्यर्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक दबाव भी पड़ता है। इसके साथ ही छात्र टीआरई-4 भर्ती प्रक्रिया में नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और परीक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक प्रमुख मांग बिहार की सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत डोमिसाइल नीति लागू करने की भी है। छात्रों का कहना है कि राज्य की सरकारी नौकरियों में बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छात्रों ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) से संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं में भी बदलाव की मांग उठाई है। इनमें संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला वेटेज समाप्त करने की मांग शामिल है।

31 अगस्त को नौसेना में शामिल होगा डाइविंग सपोर्ट वेसल 'निपुण'

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) 'निपुण' को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इसके शामिल होने से नौसेना की गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के भीतर सहायता और सबमरीन रेस्क्यू क्षमताओं में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन एवं निर्मित 'निपुण' भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आउटफिटिंग व समुद्री परीक्षणों के बाद इसे 30 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। यह अत्याधुनिक डाइविंग सिस्टम, अंडरवाटर इंटरवेंशन व मेडिकल सपोर्ट सुविधाओं से लैस है। जहाज में आधुनिक नेविगेशन, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट व सटीक स्टेशन कीपिंग सिस्टम भी मौजूद हैं। इसकी मदद से गोताखोर मुश्किल समुद्री परिस्थितियों में सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे।

हरियाणा के तालाबों में ट्रीटमेंट के बाद ही जाएगा पानी : सीएम सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण तालाबों को स्वच्छ, सुंदर व उपयोगी बनाने के लिए अब गंदे पानी की सीधी एंट्री रोकने का एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तालाबों में पहुंचने वाले पानी का जरूरी प्री-ट्रीटमेंट व वैज्ञानिक उपचार सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश के 20,100 तालाबों में से 320 के नवीनीकरण-सौंदर्यीकरण का काम जल्द पूरा करने और 467 नए तालाबों पर काम शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालाबों के सौंदर्यीकरण के साथ इनके आसपास ग्रामीणों के लिए बेहतर सुविधाएं भी विकसित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन गांवों में नई योगशालाएं बनाना प्रस्तावित हैं, वहां तालाबों के आसपास शेड आदि लगाकर योगशालाएं बनाई जाएं व ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। इससे ग्रामीण इन स्थानों पर नियमित रूप से आएंगे और तालाबों की देखभाल में भी रुचि लेंगे।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 20,100 तालाब हैं, जिनमें 19,219 ग्रामीण और 881 शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें से जो तालाब प्रदूषित एवं ओवरफ्लोइंग हैं, उनपर खासा फोकस किया जा रहा है। गांवों के ग्रे और ब्लैक वाटर को ट्रीट करने पर भी रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए तालाब से बाहर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथवा एसटीपी की व्यवस्था की जा सकती है। गांव या पंचायत की जमीन का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है।

न्यूज शॉर्ट्स

राहुल-खड़गे की मोदी को चिट्ठी जाति जनगणना के सवाल बदलें

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जाति जनगणना में जातियों के नाम दर्ज करने और डेटा जुटाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर लिखकर जनगणना में पूछे जाने वाले सवाल बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले राजनीतिक दलों, विशेषज्ञों और जनता से सलाह ली जानी चाहिए। जनगणना के सवालों में पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं होने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इससे देश में ओबीसी आबादी का सही आंकड़ा सामने आने में परेशानी हो सकती है। तेलंगाना और बिहार जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है।

जम्मू-कश्मीर में तीन संदिग्ध गिरफ्तार

एजेंसी, शोपियां। सुरक्षाबलों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में नाका-चेकिंग के दौरान तीन संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और पांच पोस्टर बरामद किए। पोस्टर पर कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन (एचएम) के निशान थे। एक अधिकारी ने बताया कि नाका-चैकिंग के दौरान इन तीनों को पकड़ा। तीनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। इनकी पहचान जुनैद अहमद डार, आमिर यूसुफ और जुनैद मुजफ्फर के तौर पर हुई है। सभी कुलगाम के हैं। आगे की जांच चल रही है।

फर्जी आईटीसी मामले में ईडी की छापेमारी में 3.6 करोड़ की नकदी बरामद

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) मामले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नौ ठिकानों पर छापेमारी के दौरान अब तक 3.6 करोड़ नकद बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और फरीदाबाद में सोमवार से जारी कार्रवाई के बाद सभी परिसरों को सील कर दिया गया है। ईडी ने कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और रजिस्टर भी जब्त किए हैं। मामला जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर फर्जी चालान और ई-वे बिल के जरिए बिना माल की वास्तविक आवाजाही के आईटीसी बनाने और पास करने का आरोप है। जीएसटी अधिकारियों ने 9.63 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी लेने और 10.28 करोड़ रुपए पास करने की पुष्टि की है।

फ्रांस में 117 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आया टॉरनेडो, 41 लोग घायल

एजेंसी, पेरिस। फ्रांस के एक गांव में 117 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से टॉरनेडो आया। इसमें 41 लोग घायल हुए और सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टॉरनेडो से सबसे ज्यादा नुकसान करीब 1,000 आबादी वाले पोमास गांव में हुआ। अधिकारियों के मुताबिक, यहां करीब 300 घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ घरों की छतें पूरी तरह उड़ गईं। परिवहन मंत्री फिलिपे तबारो ने बताया कि ट्रेनें लेट हुईं, सड़कें बंद करनी पड़ीं व हवाई अड्डों पर देरी और उड़ानें रद्द हुईं। देश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के कई इलाकों में तूफान को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। देश के उत्तर में स्थित पेरिस के एयरपोर्ट पर भी देरी और उड़ानें रद्द होने की जानकारी दी गई।

बांके बिहारी मंदिर का चढ़ावा भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि मंदिर में दान किया गया एक-एक पैसा भगवान के खजाने में जमा होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट या दान पेटियों के जरिए ये राशि सीधे मंदिर के खाते में जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मंदिर के खजाने में जमा होने से पहले चढ़ावे की राशि पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मंदिर की प्रबंधन समिति को चढ़ावा हासिल करने और उसके हिसाब के लिए एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य गड़बड़ियों को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रकार के चढ़ावे का उचित ढंग से हिसाब रखा जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंदिर में दिया गया दान भगवान के लिए है।

टीएमसी के 20 बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों को अयोग्य करार देने की मांग पर सुनवाई करते हुए 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। याचिका तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर की है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि वे लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पेश होंगे। मेहता ने कहा कि उन्हें निर्देश मिले हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए हैं। याचिका में बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही पर फैसले में हो रही देरी को चुनौती दी गई है।

पुलवामा में आतंकियों के दो सहयोगी गिरफ्तार

एजेंसी, पुलवामा। सुरक्षाबलों ने मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया। राजपोरा के सीबी नाथ इलाके के यारवान जंगल में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 12 राउंड गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस अधिकारी के अनुसार, खुफिया सूचना के आधार पर पुलवामा पुलिस ने सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 183 बटालियन के साथ मिलकर अभियान चलाया। तलाशी के दौरान संयुक्त टीम ने दो संदिग्धों को जंगल से गांव की ओर आते देखा और उन्हें पकड़ लिया। उनकी पहचान लतीफ अहमद दीदार और एजाज अहमद बाजाद के रूप में हुई। राजपोरा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री रेखा ने निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के साथ की बैठक

स्वच्छ पर्यावरण व सतत विकास दिल्ली की आवश्यकताएं : रेखा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों एवं निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों एवं निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर ग्रैप के दौरान निर्माण गतिविधियों से जुड़ी उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास दोनों दिल्ली की आवश्यकताएं हैं। सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान पर कार्य करेंगे, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावी हों और रोजगार एवं विकास की गति भी बनी रहे। मंत्री सिरसा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को आगे ले जाने और आने वाले समय के लिए बेहतर दिल्ली कैसे तैयार करें, इस पर विस्तार से बैठक में चर्चा हुई। ग्रैप के दौरान निर्माण कार्यों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों पर भी विचार-विमर्श हुआ और प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन बना कर निर्माण सेक्टर की रफ्तार ने का प्रयास कर रही है।

पंजाब में चीनी की कोई कमी नहीं, स्टॉक और आपूर्ति पर पूरी नजर : मुख्यमंत्री मान

एजेंसी, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है और पंजाब सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए चीनी के भंडारण, बिक्री और आपूर्ति पर लगातार नजर रख रही है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आवश्यक वस्तु की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब के पास पहले से ही चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर समय आवश्यक स्टॉक बना रहे। चीनी हर घर के लिए एक आवश्यक वस्तु है और इसकी उपलब्धता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कृत्रिम कमी पैदा करने या जमाखोरी करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को चीनी की उपलब्धता को लेकर लोगों में किसी भी तरह की घबराहट या गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

◆ **कहा- कृत्रिम कमी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं**

अग्निवीर योजना बंद करने की मांग, सीएम बोले- पीएम को लिखूंगा पत्र

हिमाचल के युवाओं के साथ हुआ अन्याय : सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों ने अग्निवीर भर्ती योजना को बंद करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए मुख्यमंत्री से इसे केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की मांग की।

कुल्लू के पूर्व सैनिक शिवदयाल सिंह ने कहा कि अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। चार वर्ष की सेवा के बाद अधिकांश युवाओं को नौकरी छोड़नी पड़ती है और उन्हें पेंशन सहित अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलतीं। उन्होंने नियमित सेना भर्ती बहाल करने की मांग की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह अग्निवीर योजना को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे और प्रदेश के पूर्व सैनिकों की भावनाओं से केंद्र सरकार को अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना तथा हमीरपुर जिलों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। उन्होंने नियमित सेना भर्ती के पक्ष में अपना समर्थन जताते हुए कहा कि सेना में भर्ती कोटा कम होने से भी हिमाचल के युवाओं में निराशा है। उन्होंने कहा कि चार परमवीर चक्र विजेताओं की भूमि हिमाचल के वीर जवानों के साथ अग्निवीर योजना अन्यायपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है। पुलिस विभाग में 1300 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की गई है, जबकि जल्द ही एक हजार और पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूध के दाम में बढ़ोतरी जैसे कदम इसी दिशा में हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों से प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ने की अपील की। सैनिक कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने पूर्व सैनिकों को प्रदेश की धरोहर बताते हुए कहा कि सरकार उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीआरडीओ की मिसाइल तकनीक अब भारतीय कंपनियां भी कर सकेंगी तैयार

एजेंसी, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को स्वदेशी उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से भारतीय कंपनियों को उन्नत मिसाइल प्रणालियों के निर्माण में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से मिसाइल प्रणालियों के विकास को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन में बदलने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने के साथ रक्षा क्षेत्र के औद्योगिक आधार को मजबूत किया जा सकेगा। इस पहल के तहत भारतीय कंपनियां निर्धारित योग्यताओं, प्रमाणन और नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए डीआरडीओ के मानकों के अनुरूप मिसाइल सिस्टम बना सकेंगी।

◆ **राजनाथ ने स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों के तकनीक हस्तांतरण को दी मंजूरी**

इससे रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा अन्य तकनीकी साझेदारों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

सरकार का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना, घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाना और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को मजबूत करना है। मंत्रालय ने कहा कि इससे परिचालन क्षमता बढ़ाने और देश की आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को गति देने में मदद मिलेगी।

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने और आम जनता को उचित दरों पर सामान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी व मुनाफाखोरी के जरिए कृत्रिम रूप से कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग समेत संबंधित विभागों को बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता व कीमतों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी पैदा कर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिकारियों को मांग और आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा आवश्यकता के अनुसार समयबद्ध कदम उठाने को कहा गया है। धामी ने सभी जिलों के प्रशासन को नियमित रूप से बाजारों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित व प्रचलित बाजार मूल्य के साथ दुकानों व प्रतिष्ठानों में उपलब्ध स्टॉक की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा निर्धारित मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि का सीधा असर आम नागरिकों के घरेलू बजट पर पड़ता है। राज्य सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों को आपसी समन्वय से बाजार की स्थिति पर सतत निगरानी रखने तथा अनियमितता की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

◆ **कालाबाजारी, जमाखोरी मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश**

◆ **बाजारों में नियमित निरीक्षण के आदेश, स्टॉक और कीमतों की होगी जांच**

आयोजन मुख्यमंत्री ने साढ़े तीन हजार युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, साल 2017 से पहले की सरकारों पर उठाए सवाल

छह माह में एक लाख को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपेंगे : योगी

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तीन हजार 572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले साढ़े नौ सालों में उनकी सरकार प्रदेश के नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। अगले छह माह में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। योगी ने कहा कि हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब हम योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के करते हैं, तो उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उनकी प्रतिभा और उनकी ऊर्जा का लाभ पूरा प्रदेश लेता हुआ दिखाई देता है और यही पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नौ लाख 30 हजार से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है और एक भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। हमने पहले दिन से तय कर रखा है कि जो 2017 के पहले की परिपाटी थी, वह अब नहीं चलेगी। नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था, चाचा-भतीजे की जोड़ी व महाभारत का पूरा खानदान फिर वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था। नौजवान भटकता रहता था, परिणाम नहीं आता था और अंततः न्यायालय को कोर्ट में स्टे लगाना पड़ता था। हमारे युवाओं का समय बर्बाद होता था। लोग मानते थे कि ये युवा किसी लायक नहीं क्योंकि ये नौकरी नहीं प्राप्त कर रहे। गलती युवा की नहीं होती थी, गलती उन आयोगों और बोर्डों में बैठे हुए और उस समय की सरकारों के भ्रष्ट तंत्र की थी। हमने पहले दिन कहा था कि अगर ये सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है तो हम नकल माफिया की भी और विभिन्न संस्थानों में बैठे हुए माफिया की कमर को भी तोड़ेंगे और उसके आकाओं को भी जमीन-आसमान दिखाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। वह भी तीन घंटे की बिजली। इसमें क्या विकास कोई करेगा। लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं और बिजली भी फ्री में देते हैं।

◆ **कहा- साढ़े नौ साल में 9.30 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी**

यूपी अब बीमारू राज्य नहीं, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर

योगी ने कहा याद करिए यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्य था। युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था। बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था। व्यापारी माफिया से तबाह था। किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी है तो कब चोरी हो गई, उसको पता ही नहीं होता था। ये यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने जो नौ लाख 30 हजार यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है परिणाम क्या है? उससे यूपी को लाभ हुआ है। ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके अब भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेकर जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ा जरूर हो जाएगा।

बढ़ती चीनी कीमतों पर सरकार सख्त, जमाखोरी पर कसेगा शिकंजा

सरकार ने 35,600 क्विंटल मंगाई चीनी, डिपो में पर्याप्त आपूर्ति होगी सुनिश्चित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच राज्य सरकार ने जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों पर निगरानी बढ़ा दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखने के लिए उड़नदस्तों को सक्रिय कर दिया है। विभाग की टीमें थोक गोदामों, खुदरा बाजारों और प्रमुख मंडियों का निरीक्षण कर रही हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी जमाखोरी करता या उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्याज की कीमतों को लेकर मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, ऊना, शिमला और कांगड़ा समेत प्रदेश के प्रमुख बाजारों में रोजाना फुटकर दाम की निगरानी की जा रही है। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्धता का फायदा उठाकर

व्यापारी कृत्रिम कमी न पैदा करें और उपभोक्ताओं से निर्धारित या उचित कीमत से अधिक राशि न वसूलें।

त्योहारों से पहले 35,600 क्विंटल चीनी का विशेष ऑर्डर : चीनी की बढ़ती कीमतों और आगामी त्योहारों को देखते हुए सरकार ने राशन डिपो के लिए 35,600 क्विंटल चीनी का विशेष ऑर्डर किया है। यह खेप हरियाणा शुगर फेडरेशन से हिमाचल प्रदेश के थोक गोदामों तक पहुंच चुकी है और अब इसे राशन डिपो तक भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

सरकार का कहना है कि विशेष आपूर्ति का उद्देश्य राशन डिपो में चीनी का पर्याप्त कोटा बनाए रखना है, ताकि उपभोक्ताओं को बाजार में बढ़ती कीमतों का सीधा असर न झेलना पड़े। वर्तमान में बाजार में चीनी के दाम करीब 60 से 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। ऐसे में सरकारी राशन डिपो के माध्यम से सस्ती दर पर चीनी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था आम लोगों के लिए राहत दे सकती है।

उड़नदस्तों को कार्रवाई के निर्देश

खाद्य आपूर्ति विभाग के उड़नदस्ते लगातार बाजारों और गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं। प्याज और चीनी की जमाखोरी, अवैध भंडारण या निर्धारित सीमा से अधिक स्टाक मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की निगरानी विशेष रूप से उन बाजारों में बढ़ाई गई है जहां कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। सरकार का मानना है कि त्योहारों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मांग बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में समय रहते पर्याप्त स्टाक सुनिश्चित करने के साथ व्यापारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। विशेष चीनी आपूर्ति और स्टाक सीमा से सरकार ने बाजार में कृत्रिम महंगाई पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया है।

व्यापारियों के स्टाक पर भी निगरानी : सरकार ने चीनी के व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टाक की सीमा भी तय की है। कोई भी चीनी व्यापारी या डीलर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर स्टाक जमा करके बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने और कीमतें बढ़ाने की कोशिशों पर रोक लगाना है।

इसके अलावा सभी थोक डीलरों के लिए केंद्रीय खाद्य पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। उन्हें प्रत्येक शुक्रवार अपने पास उपलब्ध चीनी के मौजूदा स्टाक की जानकारी भी घोषित करनी होगी। इससे विभाग को बाजार में वास्तविक उपलब्धता का नियमित आंकड़ा मिल सकेगा और किसी भी असामान्य स्टाक पर तत्काल नजर रखी जा सकेगी।

परौर-पद्धर फोरलेन की तैयारी तेज, 5734 परिवारों पर पड़ेगा परियोजना का असर

भारतेन्दु संवाददाता,शिमला। हिमाचल प्रदेश में परौर से पद्धर तक प्रस्तावित फोरलेन परियोजना को लेकर सरकार ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में बताया कि परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी गई है। फिलहाल सड़क की अलाइनमेंट तय करने का काम शुरुआती चरण में है। परियोजना का वास्तविक स्वरूप, कार्यक्षेत्र और निर्माण शुरू होने की समय-सीमा डीपीआर तैयार होने तथा उसके स्वीकृत होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

मंत्री विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक किशोरी लाल के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि परौर से चक्की तक प्रस्तावित फोरलेन परियोजना का निर्माण पांच पैकेज में किया जाना है। इनमें से एक पैकेज का काम पूरा हो चुका है, जबकि तीन पैकेज पर निर्माण कार्य चल रहा है। एक अन्य पैकेज के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

5734 परिवार हुए प्रभावित : विक्रमादित्य सिंह ने सदन को बताया कि फोरलेन परियोजना से अब तक कुल 5734 परिवार और व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। परियोजना के विभिन्न चरणों में भूमि अधिग्रहण और निर्माण संबंधी गतिविधियों का असर स्थानीय लोगों पर पड़ा है। सरकार की ओर से परियोजना को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि परौर से पद्धर तक के प्रस्तावित मार्ग की स्थिति डीपीआर और संबंधित तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिक स्पष्ट होगी। इसके बाद ही निर्माण कार्य की दिशा और समयसीमा के संबंध में ठोस जानकारी सामने आएगी।

ऊना में निशानदेही और तक्सीम के हजारों मामले लंबित : विधानसभा में राजस्व विभाग से जुड़े सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी जानकारी दी। विधायक राकेश कालिया के सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि ऊना जिले में पिछले दो वर्षों के दौरान निशानदेही के 7511 मामलों और तक्सीम के 3746 मामलों का निपटारा किया गया है। हालांकि अभी निशानदेही के 4467 और तक्सीम के 4066 मामले लंबित हैं।

राष्ट्रगीत-राष्ट्रगान पर भाजपा की राजनीति से विधानसभा की गरिमा आहत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भाजपा पर विधानसभा की परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदन के भीतर जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से लगातार बच रही है और राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान जैसे विषयों पर राजनीति कर विधानसभा की गरिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

विनय कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा देश में अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन मामलों से भाजपा के कथित कृत्यों से जनता का ध्यान नहीं हटाया जा सकता।

उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा को हिमाचल से जुड़े मुद्दों की चिंता नहीं है और वह केवल राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। इसी कारण भाजपा विधायक सदन की कार्यवाही से लगातार दूरी बना रहे हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का सम्मान न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा बनाए रखना सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है।

जुन्गा तहसील में नंबरदारों ने अलग कक्ष सहित विभिन्न मांगें प्रशासन के समक्ष रखीं

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जुन्गा तहसील के नंबरदारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को सहायक आयुक्त राजस्व एवं तहसीलदार जुन्गा कार्तिकेय शर्मा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नंबरदारों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नंबरदार संघ के प्रतिनिधि ओम स्वरूप शर्मा ने किया।

नंबरदार संघ के प्रतिनिधियों ने तहसील कार्यालय में नंबरदारों के लिए अलग से कक्ष उपलब्ध करवाने की प्रमुख मांग रखी। ओम स्वरूप शर्मा ने कहा कि जुन्गा तहसील में प्रवास के दौरान नंबरदारों को बैठने और अपने राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में यदि तहसील कार्यालय में नंबरदारों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाती है तो उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में सुविधा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि नंबरदारों के लिए निर्धारित कक्ष में वे अपने राजस्व संबंधी कार्यों को व्यवस्थित तरीके से कर सकेंगे। इसका सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों

◆ नंबरदारों ने राजस्व कार्यों में सहभागिता और आधिकारिक पहचान पत्र जारी करने की उठाई मांग

को भी मिलेगा। ग्रामीणों को भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में नंबरदारों से संपर्क करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध होगा और उनके कार्यों का निपटारा भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

प्रतिनिधिमंडल ने भू-रजिस्ट्री, भूमि इंतकाल, निशानदेही और भूमि विभाजन सहित अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में नंबरदारों की भूमिका और सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई। नंबरदार संघ का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नंबरदार लंबे समय से राजस्व व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व निभाते आ रहे हैं। ऐसे में राजस्व कार्यों से संबंधित प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा नंबरदारों ने आधिकारिक पहचान पत्र जारी करने की मांग भी रखी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पहचान पत्र मिलने से नंबरदारों को अपने सरकारी एवं राजस्व संबंधी दायित्वों को निभाने में सुविधा होगी।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (एईएसएल) ने लॉन्च किया एंथे 2026

एंथे 2026 से मिलेगा छात्रों की प्रतिभा परखने का बड़ा अवसर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक क्षमता, तैयारी के स्तर और कमजोर क्षेत्रों को समझने का अवसर देने के उद्देश्य से आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) 2026 शुरू किया है। पिछले 16 वर्षों से आयोजित हो रही यह परीक्षा विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आकलन करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में पहचान बना चुकी है। कंपनी के अनुसार, एंथे की शुरुआत से अब तक एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि एंथे केवल छात्रवृत्ति निर्धारित करने वाली परीक्षा नहीं है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को अपनी अकादमिक क्षमता और तैयारी के स्तर को समझने में सहायता करना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी मजबूतियों के साथ-साथ उन विषयों और क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिनमें उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता है।

एंथे में विद्यार्थियों के शैक्षणिक आकलन, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी और परीक्षा के दौरान प्रदर्शन जैसे पहलुओं को एक साथ समझने का प्रयास किया जाता है। इससे विद्यार्थियों को भविष्य की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर दिशा तय करने में सहायता मिलती है।

एंथे 2026 के तहत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति दी जा सकती है। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कुल 2.5 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार भी रखे गए हैं। छात्रवृत्ति के माध्यम से विद्यार्थी आकाश के कक्षा आधारित, मिश्रित और डिजिटल कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे।

शिमला ग्रामीण कांग्रेस संगठन मजबूत करने को नई जिम्मेदारियां होंगी तय

भारतेन्दु संवाददाता,शिमला। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को प्रभावी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के प्रभारी हरिकृष्ण हिमराल ने की।

हिमराल ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करने के लिए सहकार सारथी, पार्टी प्रशिक्षण के लिए विचार प्रभारी तथा प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विचार प्रमुख नियुक्त किए जाएंगे। मीडिया से बेहतर संवाद के लिए प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट भी नियुक्त होंगे।

उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार और मजबूती में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। संगठन को समय देने वाले कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की रीढ़ बताते हुए कहा कि सभी को मिलकर पार्टी को मजबूत करना होगा।

हिमराल ने कहा कि शिमला ग्रामीण में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जुब्बल, कसुम्पटी, शिमला ग्रामीण, ठियोग, रामपुर और रोहड़ू क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ नेता संगठन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं।

फिट वाहन हटाने के बजाय वास्तविक फिटनेस जांच की उठी मांग

परमिट फैसले से भड़के टैक्सी ऑपरेटर

भारतेन्दु संवाददाता , शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय शर्मा ने शिमला के चौड़ा मैदान में टैक्सी ऑपरेटरों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण टैक्सी चालक और ऑपरेटर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। परमिट अवधि को 12 वर्ष तक सीमित करने का फैसला व्यावहारिक नहीं है और इससे हजारों ऑपरेटरों तथा उनके परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है।

विनय शर्मा ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों की मांग है कि वाहनों की आयु के बजाय उनकी वास्तविक फिटनेस और सड़क पर चलने की स्थिति को आधार बनाया जाए। यदि कोई वाहन निर्धारित सुरक्षा और फिटनेस मानकों पर खरा उतरता है तो केवल एक निश्चित अवधि पूरी होने के कारण उसे व्यवसाय से बाहर करना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मामले में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जिस सरकार की अपनी राजनीतिक फिटनेस करीब एक वर्ष बची है, वह टैक्सी वाहनों की फिटनेस तय करने में लगी हुई है। सरकार को पहले अपनी कार्यप्रणाली और जनहित के प्रति जवाबदेही पर ध्यान देना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन प्रधान राज्य है और टैक्सी व्यवसाय हजारों परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। टैक्सी ऑपरेटर पर्यटकों को परिवहन सुविधा देने के साथ प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को भी जोड़ते हैं। इसके बावजूद उन्हें लगातार नए नियमों और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि टैक्सी चालक पहले ही टैक्स, बीमा, वाहन की किस्त, ईंधन, मरम्मत और रखरखाव जैसे खर्चों से परेशान हैं। ऐसे में फिट वाहन को केवल उसकी आयु के आधार पर हटाने से उन्हें नया वाहन खरीदने के लिए भारी कर्ज लेना पड़ सकता है। इससे छोटे ऑपरेटरों की आर्थिक स्थिति और खराब होगी।

बालूगंज में खाद्य विभाग की कार्रवाई, दो क्विंटल मिठाइयां नष्ट

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग ने बालूगंज बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान चलाया। सहायक आयुक्त डॉ. विजया और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा की टीम ने विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कई स्थानों पर खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी कमियां सामने आईं। निरीक्षण के दौरान एक मिठाई प्रतिष्ठान में गुलाब जामुन की चाशनी में कॉकरोच पाए गए। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए जाने पर करीब दो क्विंटल मिठाइयों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। विभाग की कार्रवाई के बाद खाद्य व्यवसाय संचालक ने इन मिठाइयों को नष्ट किया।

विधानसभा अध्यक्ष से रूबरू हुए संजौली-करियाली स्कूलों के छात्र, संसदीय प्रणाली पर पूछे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संजौली और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करियाली, जिला शिमला के छात्र-छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विद्यार्थियों ने संसदीय प्रणाली, विधानसभा की कार्यप्रणाली और विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़े कई सवाल पूछे। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों के प्रश्नों का सिलसिलेवार जवाब देकर उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानकारी दी।

कुलदीप सिंह पठानियां ने विद्यार्थियों से बातचीत के दौरान स्वयं भी लोकतांत्रिक प्रणाली, संविधान और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे। विद्यार्थियों ने इन सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। इस संवाद के माध्यम से बच्चों को देश की संसदीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को समझने का अवसर मिला।

संसदीय व्यवस्था की दी जानकारी : विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय प्रणाली के बारे में बताया कि भारत की व्यवस्था संघीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं। देश में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारते हैं और जनता मतदान के माध्यम से उनका चुनाव करती है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा सदस्य सदन के सत्रों के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं को प्रश्नों और विभिन्न नियमों के माध्यम से उठाते हैं। सरकार इन मुद्दों का जवाब देती है। कई सदस्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होते हैं, जबकि कुछ सदस्य अपनी असहमति भी व्यक्त करते हैं।

68 विधानसभा सीटों की दी जानकारी : पठानियां ने विद्यार्थियों को बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्यों के लिए सीटों का प्रावधान है। जिस राजनीतिक दल के पास 35 या उससे अधिक सीटें होती हैं, वह सरकार बनाने की स्थिति में होता है। इसके बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शामिल करते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं।

स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया समझाई : विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया भी समझाई। उन्होंने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं।

खाद्यान्न ढुलाई के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित, 31 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक भंडारों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्नों के परिवहन एवं ढुलाई कार्य के साथ-साथ मजदूरी, लदान और उतराई से संबंधित कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है।

जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला नरेंद्र धीमान ने बताया कि भट्टाकुफर, शनान, ठियोग, नारकंडा, रामपुर, गुम्मा, जुब्बल, ननखड़ी, रोहड़ू, चिड़गांव, चौपाल, नेरवा, टिक्कर तथा डोडरा-क्वार स्थित थोक भंडारों से संबंधित उचित मूल्य की दुकानों तक घर-द्वार खाद्यान्न पहुंचाने के कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

उन्होंने बताया कि इच्छुक निविदादाता निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 31 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक अपनी निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने इच्छुक फर्मों और ठेकेदारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने का आग्रह किया है।

इसके अलावा भट्टाकुफर, शनान, ठियोग, ननखड़ी, टिक्कर, रोहड़ू, चौपाल और नेरवा स्थित थोक भंडारों में खाद्यान्न की लदान और उतराई से संबंधित मजदूरी कार्य के लिए भी ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इन निविदाओं को 31 अगस्त 2026 को शाम तीन बजे अतिरिक्त उपायुक्त, शिमला के कार्यालय में खोला जाएगा।

विभाग के अनुसार निविदा प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के ऑनलाइन निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदादाता पोर्टल पर जाकर नियम, शर्तें और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के कार्यालय में कार्यदिवस के दौरान सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

191 देशों की साइकिल यात्रा कर चुके सोमेन ने विधानसभा अध्यक्ष पठानियां से की मुलाकात

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। 191 देशों और सात महाद्वीपों में करीब दो लाख किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके वैश्विक साइकिल यात्री सोमेन देबनाथ ने मंगलवार शाम हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में हुई मुलाकात के दौरान सोमेन ने अपनी विश्व और भारत यात्रा के अनुभव साझा किए तथा अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी।

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन निवासी सोमेन देबनाथ पिछले करीब 22 वर्षों से साइकिल के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 27 मई 2004 को अपनी साहसिक यात्रा शुरू की थी। वह उत्तर कोरिया को छोड़कर लगभग पूरे विश्व की यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल विभिन्न देशों को देखना नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता फैलाना और भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार करना भी है।

सोमेन ने बताया कि उनकी यात्रा

विश्व भ्रमण के अनुभव साझा कर भारतीय संस्कृति के प्रचार का बताया उद्देश्य

के दौरान वह एचआईवी-एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। इसके साथ ही वह विदेशी नागरिकों को भारत की सांस्कृतिक विरासत और विविधता से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। विभिन्न देशों में उन्हें लोगों की जीवनशैली और भारत के प्रति उनकी रुचि को करीब से जानने का अवसर मिला।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से 2006 के बीच उन्होंने भारत के 28 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 2700 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 25 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विभिन्न राज्यपालों से भी मुलाकात की।

सोमेन ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान वह चीन में थे और संक्रमण की चपेट में आ गए थे। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। वर्तमान में वह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दोबारा यात्रा पर निकले हैं। इस अभियान को उन्होंने 'पुनर्मिलन भारत' का हिस्सा बताया। उनका उद्देश्य करीब 22 वर्ष पहले देखे भारत और वर्तमान भारत के बीच आए बदलावों को समझना है।

खेलसंवाद प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ेंगे आठ लाख से अधिक युवा, खेलों पर होगा संवाद

शिमला के तीन संस्थानों में 27 अगस्त को होगा खेलो इंडिया संवाद

भारतेन्दु संवाददाता , शिमला। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेरा युवा भारत, शिमला और माय भारत एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में 27 अगस्त को शिमला के तीन प्रमुख शिक्षण संस्थानों में खेलो इंडिया संवाद एवं युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को खेल, राष्ट्र निर्माण और युवा सहभागिता से जुड़े विषयों पर संवाद का अवसर प्रदान करना है।

कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा और सीओई राजकीय महाविद्यालय संजौली में आयोजित होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष इससे संबंधित कार्यक्रम 27 अगस्त को आयोजित किए जा रहे हैं।

युवाओं को खेल विकास पर संवाद का अवसर : खेलो इंडिया संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं, खिलाड़ियों और देश के भविष्य को एक मंच पर लाकर खेलों के विकास, युवा सहभागिता और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करना है। इसके तहत देशभर के प्रत्येक जिले में एक उत्कृष्ट संस्थान और दो महाविद्यालयों में युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

उप निदेशक, मेरा युवा भारत शिमला ने बताया कि जिले में होने वाले कार्यक्रमों में युवाओं को खेल जगत से जुड़े व्यक्तित्वों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। इससे युवा खेल क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं और अवसरों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे।

1600 स्थानों से जुड़ेंगे आठ लाख से अधिक युवा : कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन रहेगा। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री देशभर के करीब 1600 स्थानों से आठ लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। शिमला के तीनों संस्थानों में भी युवा इस संबोधन से जुड़ेंगे।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय स्तर पर युवा संवाद आयोजित किया जाएगा। इसमें माय भारत स्वयंसेवकों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच चर्चा होगी। संवाद के दौरान पिछले वर्षों में देश के खेल ढांचे में आए बदलाव, भारत में विकसित हो रहे खेल तंत्र और खेल क्षेत्र में युवाओं के लिए उपलब्ध अवसरों पर विचार साझा किए जाएंगे।

आयोजकों के अनुसार, कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उन्हें स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है।

इसके अलावा कार्यक्रम में युवाओं को खेलों में करियर बनाने की संभावनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। स्थानीय खिलाड़ियों के अनुभवों के माध्यम से प्रतिभागियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि ऐसे संवाद युवाओं को अपनी प्रतिभा पहचानने और उसे बेहतर मंच तक पहुंचाने में मदद करेंगे। कार्यक्रम में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थी खेलों के प्रति अपने विचार साझा करेंगे और खेल सुविधाओं को और बेहतर बनाने को लेकर सुझाव भी देंगे।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सड़कों के सुधार को मिलेगी गति

मानसून के बाद सड़क सुधार कार्य होंगे तेज, पीएमजीएसवाई और शहरी मार्गों के लिए धनराशि होगी उपलब्ध

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मानसून के बाद राज्यभर में सड़क सुधार और मरम्मत के कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संबंधित विभागों को अभी से तैयारियां पूरी करने और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सहित विभिन्न विभागों और संस्थाओं के अधीन आने वाली सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। बैठक में विशेष रूप से पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित उन पुरानी सड़कों की स्थिति पर चर्चा हुई, जिनकी अनुरक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है और नियमित

रखरखाव के अभाव में वे खराब हो गई हैं। ऐसी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की ओर से आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार किया गया।

मानसून के बाद तेजी से होंगे काम : मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून समाप्त होते ही प्रदेशभर में सड़क सुधार के कार्य एक साथ शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया सहित अन्य जरूरी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जाएं, ताकि बारिश समाप्त होने के बाद सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू करने में किसी तरह की देरी न हो।

उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें लोगों की आवाजाही के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में सड़कों की गुणवत्ता और उनकी नियमित देखरेख पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है।

ग्रामीण-शहरी सड़कों को बेहतर बनाने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम सड़क सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। बैठक में मानसून के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत, पुरानी सड़कों के रखरखाव, ग्रामीण संपर्क मार्गों को बेहतर बनाने और शहरी क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं को मजबूत करने सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। सरकार के इस निर्णय से पीएमजीएसवाई और स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

शहरी निकायों को भी मिलेगा बजट : बैठक में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति सुधारने को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी निकायों को सड़क मरम्मत और सुधार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इससे शहरों में खराब और क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुधार से जुड़े कार्यों में विभागीय तालमेल की कमी के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

अक्टूबर से सड़क मार्ग से करेंगे भ्रमण : मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वह अक्टूबर से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का सड़क मार्ग से भ्रमण करेंगे। इस दौरान वह सड़कों की वास्तविक स्थिति का जायजा भी लेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुधार के लिए ठोस और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरे किए जाएं।

उत्तराखंड के 13 संस्थानों में खेलो इंडिया संवाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे युवाओं से वर्चुअल संवाद

देशभर के आठ लाख युवा जुड़ेंगे, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण पर होगा संवाद

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 13 प्रमुख शिक्षण संस्थानों में 27 अगस्त को खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन रहेगा। प्रधानमंत्री देशभर के करीब 1600 स्थानों पर मौजूद आठ लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर युवाओं की खेल में भूमिका पर होगी चर्चा।

उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में युवा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस दौरान खेलों के विकास, युवा सहभागिता, नेतृत्व क्षमता और विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को पिछले 12 वर्षों में खेल क्षेत्र में हुए बदलावों और देश में विकसित हो रहे खेल पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी दी जाएगी।

राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस से जुड़े कार्यक्रम 27 अगस्त को आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया संवाद का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों और देश के भविष्य को एक मंच पर लाकर खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है।

इन 13 संस्थानों में होंगे कार्यक्रम : उत्तराखंड में राजकीय पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर, डीवीएस कॉलेज देहरादून, फीनिक्स विश्वविद्यालय रुड़की, एशियन एकेडमी पिथौरागढ़, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, पीजी कॉलेज उत्तरकाशी, पीजी कॉलेज अगस्त्यमुनि और पीजी कॉलेज जखोली में कार्यक्रम आयोजित होंगे।

स्थानीय स्तर पर भी होगा युवा संवाद : कार्यक्रम में सभी अतिथियों और युवा प्रतिभागियों की उपस्थिति सुबह 10 बजे तक सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय स्तर पर युवा संवाद आयोजित होगा।

न्यूज ब्रीफ

यूकेडी में बड़ी संख्या में युवाओं ने ग्रहण की सदस्यता

अनिल थपलियाल । उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। युवाओं ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी, पलायन और भाजपा सरकार की नीतियों से युवा वर्ग परेशान है। उन्होंने उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, रोजगार, मूल निवास और भू-कानून के मुद्दों पर यूकेडी की विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता लेने की बात कही। दल ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं की भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। यूकेडी ने युवाओं के रोजगार और पलायन रोकने का संघर्ष जारी रखने का संकल्प दोहराया।

चमोली में खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया हुई तेज, समिति गठित

भारतेंदु संवाददाता, उदित नैनवाल । जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सभागार में खान मंत्रालय की महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रक्रिया की प्रगति, सफल क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि चमोली के कर्णप्रयाग और पोखरी क्षेत्रों को नीलामी प्रक्रिया के लिए चिन्हित किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्वेषण में यहां तांबा, सीसा और जस्ता के भंडार मिले हैं। प्रस्तावित क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण के लिए राजस्व, वन, सिंचाई, भूतत्व एवं खनिकर्म तथा आपदा प्रबंधन विभागों की संयुक्त समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी ने समिति को जल्द निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि आगे की कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी की जा सके। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

रक्षाबंधन से पहले चमोली में खाद्य दुकानों की जांच तेज, तीन दुकानो को नोटिस जारी

भारतेंदु संवाददाता, उदित नैनवाल । रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए चमोली में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने गोपेश्वर, चमोली व पीपलकोटी बाजार में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, पैकेजिंग, समाप्ति तिथि और भंडारण व्यवस्था जांची। पांच दुकानों से खाद्य सामग्री के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। वहीं, तीन दुकानों में मिली समाप्ति तिथि वाली सामग्री मौके पर नष्ट कराई गई और दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान अभियान लगातार जारी रहेगा।

भूस्खलन से हरमल गांव का पैदल संपर्क मार्ग भी हुआ बाधित

भारतेंदु संवाददाता, गिरीश चंदोला। देवाल विकासखंड के दूरस्थ हरमल गांव में बरसात के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पहले से बंद है, वहीं अब भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे ग्रामीणों की आवाजाही बाधित हो गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य चोटिंग रमेश गढ़िया ने बताया कि सुयालकोट के पास भूस्खलन से देवाल-खेता मोटर मार्ग बंद है। ग्रामीण वैकल्पिक पैदल रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हरमल के पास वह भी टूट गया। इससे जरूरी सामान की आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त रास्ते की तत्काल मरम्मत, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और मोटर मार्ग का निर्माण जल्द पूरा कराने की मांग की है।

विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

भारतेंदु संवाददाता, अनिल थपलियाल । सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की अध्यक्षता में उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। महासंघ के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण रौतेला और महामंत्री प्रशांत मेहता ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याएं प्रमुखता से उठाईं। बैठक में विश्वविद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पदों पर नियुक्तियां न होने का मुद्दा उठाया गया। सचिव कार्मिक ने संबंधित विभागों को एक माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा विभाग में सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक अगले सप्ताह प्रस्तावित है।

सहसपुर में महिलाओं के हुनर को मिलेगा बाजार और रोजगार

भारतेंदु संवाददाता, अनिल थपलियाल । सहसपुर क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की है। लंबे समय से बंद सिलाई यूनिट को आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में दोबारा शुरू किया जा रहा है। केंद्र में 25 से 30 आधुनिक सिलाई मशीनें उपलब्ध हैं और संचालन की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देकर जूट बैग, स्कूल ड्रेस, कार कवर और बाइक सीट कवर जैसे उत्पाद तैयार करवाए जाएंगे। प्रशासन निजी कंपनियों से संपर्क कर महिलाओं को नियमित और थोक ऑर्डर दिलाने की योजना बना रहा है।

कैंट विधानसभा में जनसंपर्क कर राजीव महर्षि ने सुनी समस्याएं, कहा- भाजपा शासन से त्रस्त हैं लोग

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने सोमवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र के चार वार्डों में जनसंपर्क कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान द्रोणपुरी, पटेल नगर पूर्व, कांवली रोड और विजय पार्क वार्ड में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं।

जनसभाओं को संबोधित करते हुए राजीव महर्षि ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में पिछले करीब 30 वर्षों से भाजपा का कब्जा है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की कई कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था, पेयजल और बिजली की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

महर्षि ने कहा कि वर्ष 2022 में कौलागढ़ में सड़क दलदल में डूब गई थी, लेकिन आज तक उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या गंभीर बनी हुई है और सरकार उन्हें पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाई है।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में आम लोगों की समस्याओं की उचित सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी।

देहरादून को स्वच्छ बनाने की अनूठी पहल, डस्टबिन की पोशाक पहन बाजारों में उतरे निगमकर्मी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। स्वच्छ और स्वस्थ दून के लक्ष्य को साकार करने के लिए नगर निगम देहरादून की ओर से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत बाजारों में विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में निगमकर्मियों ने लोगों तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। कर्मचारी अलग-अलग रंग और प्रकार के डस्टबिन की पोशाक पहनकर बाजारों में घूम रहे हैं और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं।

निगम की टीम बाजारों में दुकानदारों, ग्राहकों और आमजन से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फेंकने की अपील कर रही है। लोगों को कूड़ा निर्धारित डस्टबिन में डालने तथा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। डस्टबिन के रूप में निगमकर्मियों की मौजूदगी बाजारों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

सुल्तानपुर में पेयजल संकट ने खोली दावों की पोल, गंदे पानी से परेशान हुए लोग

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सुल्तानपुर में जमीनी स्थिति अलग नजर आ रही है। पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने सुल्तानपुर स्थित ईदगाह पहुंचकर पानी की टंकी से हो रही पेयजल आपूर्ति का मौके पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर पानी की समस्या के बारे में जानकारी ली।

स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की टंकी से आपूर्ति होने के बावजूद क्षेत्र के अधिकांश घरों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। लोगों के अनुसार, जिन घरों में किसी तरह पानी की आपूर्ति हो रही है, वहां भी कई बार गंदा और गादयुक्त पानी आने की शिकायत सामने आ रही है। इससे लोगों को साफ पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी उन्हें लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने संबंधित विभाग और प्रशासन से समस्या का जल्द समाधान कराने की मांग की।

चार पर्वतीय जिलों में फिटनेस सुविधा बहाल वाहन मालिकों को राहत

भारतेंदु संवाददाता, अल्मोड़ा

उत्तराखंड के चार जिलों में परिवहन वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की सुविधा फिर से बहाल कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में मैनुअल फिटनेस परीक्षण की अनुमति दी है। यह सुविधा 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी।

केंद्रीय मंत्रालय के परिवहन अनुभाग के अवर सचिव परवीन कुमार ने बताया कि इन चार जिलों में परिवहन वाहनों के मैनुअल फिटनेस परीक्षण के साथ प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे। इससे वाहन मालिकों और विशेष रूप से व्यावसायिक वाहन संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें फिटनेस प्रमाणपत्र बनवाने के लिए दूसरे जिलों में जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।

राज्यपाल ने 'मुक्त ज्ञान कोष' का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को दिया डिजिटल मंच

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंगलवार को लोक भवन में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा विकसित 'मुक्त ज्ञान कोष' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी और पूरी टीम को इस पहल के लिए बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि यह मंच ज्ञान को समाज की शक्ति और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 'मुक्त ज्ञान कोष' एक डिजिटल शैक्षणिक मंच है, जिसे विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें विश्वविद्यालय की ई-पुस्तकों और अध्ययन सामग्री के साथ देश-विदेश के विश्वसनीय शैक्षणिक स्रोतों से जुड़ी सामग्री भी उपलब्ध होगी। मंच पर शिक्षकों के शोध कार्य, शोध-पत्र, शोध संबंधी आंकड़े, शोध प्रबंध और विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य ज्ञान सामग्री भी शामिल की गई है। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस मंच की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। राज्य के अनेक विद्यार्थी पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं। ऐसे में डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

यूपीईएस डिजाइन छात्रों की फिल्मों को मिले 253 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान

भारतेंदु संवाददाता, अनिल थपलियाल । यूपीईएस स्कूल ऑफ डिजाइन के छात्रों की फिल्मों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 253 मान्यताएं हासिल की हैं। इनमें 185 चयन, 39 नामांकन, 25 पुरस्कार और नौ विशेष उल्लेख शामिल हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार यह उपलब्धि छात्रों की रचनात्मकता, शोध आधारित सोच और प्रभावशाली कहानी कहने की क्षमता को दर्शाती है।

छात्रों की फिल्मों को बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ एनिमेटेड फिल्म 2025 वार्ना बुल्गारिया, इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ फैमिली एंड चिल्ड्रन्स फिल्म्स मॉस्को, शिबुया तानपेन फिल्म फेस्टिवल जापान, लिफ्ट-ऑफ ग्लोबल नेटवर्क एट पाइनवुड स्टूडियोज यूके, कुआलालंपुर इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, चियांग माई फैंटास्टिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थाईलैंड और नेवार्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर स्थान मिला।

इन फिल्मों में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता, संस्कृति एवं विरासत, मानसिक स्वास्थ्य, पौराणिक कथाओं, वृत्तचित्र कहानी, काल्पनिक कथानक और प्रयोगात्मक एनीमेशन जैसे विषयों को प्रमुखता दी गई है। छात्रों ने डिजाइन सोच, शोध, कहानी कहने और तकनीकी कौशल को रचनात्मक प्रयोगों के साथ जोड़कर अपनी फिल्मों को तैयार किया।

सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली फिल्मों में 'वेयर द स्टार्स रेस्ट' शामिल है, जिसे वेदांग नाग ने बनाया है। फिल्म को कुल 70 मान्यताएं मिलीं, जिनमें 56 चयन, नौ नामांकन, चार पुरस्कार और एक विशेष उल्लेख शामिल है। इसे 36 अंतरराष्ट्रीय चयन भी मिले। 'सेव द हिमालयाज' को 35, 'स्ट्रिंग्स' को 25, 'अ शू स्टोरी' को 20 और 'इकोज ऑफ डुगोंग' को 13 मान्यताएं मिलीं। इन पांच फिल्मों ने मिलकर 163 मान्यताएं हासिल की हैं।

पिनाऊं-बलाण मोटर मार्ग निर्माण में तेजी की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन

भारतेंदु संवाददाता, गिरीश चंदोला

विकासखंड देवाल की ग्राम पंचायत पिनाऊं, बलाण और आसपास के गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग तेज हो गई है। ग्राम पंचायत पिनाऊं के प्रधान लक्ष्मण सिंह दानू और ग्रामीणों ने थराली विधायक भूपाल राम टम्टा को ज्ञापन भेजकर बगड़ी गाड़-धूरा धाराकोट-बांक-पिनाऊं-बलाण मोटर मार्ग के निर्माण में तेजी लाने की मांग की है।

◆ 2015 से स्वीकृत सड़क का काम शुरू कराने की मांग, ग्रामीणों ने कहा- सड़क से स्वास्थ्य, शिक्षा और कारोबार को मिलेगा लाभ

ग्रामीणों के अनुसार सड़क वर्ष 2015 से स्वीकृत है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया है।

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बनने से पिनाऊं और बलाण के साथ वाण-कुलिंग, दिदिना, बांक, मुंदोली, सूया, धूराधारकोट, हरनी, ल्वाणी, ताजापुर, कांडे, देवसथली, बगड़ीगाड़ और कनोल समेत कई गांवों को लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और कारोबार संबंधी सुविधाओं के लिए मुंदोली और लोहाजंग पर निर्भर हैं। सड़क सुविधा मिलने से इन क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

ज्ञापन में मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 298/2015 के तहत सड़क के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और मामला वन विभाग व राज्य स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता बेहाल, जलभराव और बदहाल सड़कों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल

भारतेंदु संवाददाता, अनिल थपलियाल । स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों की धीमी गति और अव्यवस्थाओं के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में प्रदर्शन किया। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं युवा नेता रितेश छेत्री के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जनसमस्याओं को लेकर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी कार्यालय, कोलागढ़ को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बरसात के दौरान देहरादून के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या गंभीर बनी हुई है।

धरोहर

मुख्यमंत्री धामी ने हिलजात्रा को बताया संस्कृति की अनमोल धरोहर

बाबा गंगनाथ मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण, हिलजात्रा को मिलेगी नई पहचान

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से पिथौरागढ़ में आयोजित ऐतिहासिक हिलजात्रा महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने प्रदेशवासियों, विशेषकर पिथौरागढ़ की जनता को हिलजात्रा पर्व की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्होंने ग्राम जाखनी स्थित बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिलजात्रा उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण पर्व है। सातू-आठू पर्व और मां गौरा व भगवान महेश्वर की पूजा से जुड़ी यह परंपरा लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना का प्रतीक है।

पौराणिक मंदिरों के संरक्षण-सौंदर्यीकरण पर सरकार का जोर

मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान, संरक्षण और सौंदर्यीकरण पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा गलियारा, हरिपुर यमुना गलियारा, गोल्ज्यू, विवेकानंद और शारदा गलियारे जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नया स्वरूप दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पांच सौ वर्षों से अधिक समय से मनाया जा रहा हिलजात्रा पर्व पिथौरागढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुका है।

सोरघाटी की यह ऐतिहासिक परंपरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन, संघर्ष, साधना, कृषि और पशुपालन से जुड़े ग्रामीण जीवन की झलक भी प्रस्तुत करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिलजात्रा लोगों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों और पूर्वजों की परंपराओं से जोड़ने का काम करती है। भगवान शिव के गण लखिया भूत का आगमन इस पर्व में सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास, विरासत और विश्वास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

पर्यटन और गांवों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार पर्यटन को केवल तीर्थाटन तक सीमित नहीं रखना चाहती। विवाह पर्यटन, साहसिक पर्यटन और फिल्म निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। गांवों की खुशहाली के लिए घर-आधारित पर्यटन, लखपति दीदी और सौर स्वरोजगार योजनाएं संचालित हैं। बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की गई।

पंजाब को 509 ग्रामीण खेल मैदानों का तोहफा, नशे से दूर रहेंगे युवा

509 नए खेल मैदानों से गांवों में बढ़ेगा खेलों का उत्साह, युवाओं को नशे से दूर रखने की पहल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को पटियाला जिले के गांव देधना से 509 से अधिक आधुनिक ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राज्य में युवाओं को समर्पित किए गए ग्रामीण खेल मैदानों की कुल संख्या 734 हो गई है। सरकार का लक्ष्य गांवों में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशे से दूर रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार इस वर्ष राज्यभर में 3,100 आधुनिक ग्रामीण खेल मैदान विकसित कर रही है। इन मैदानों के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर पंजाब को स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लक्ष्य की ओर आगे ले जाया जा रहा है।

509 मैदानों से बढ़ी खेल सुविधाएं : मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण खेल मैदान योजना के पहले चरण में 255 मैदान लोगों को समर्पित किए गए थे। अब दूसरे चरण में 509 और मैदान शुरू किए गए हैं। इनमें लुधियाना के 43, मानसा के 41, संगरूर के 36, बठिंडा और पटियाला के 34-34, श्री मुक्तसर साहिब के 33 तथा अमृतसर के 32 मैदान शामिल हैं। अन्य मैदान राज्य के अलग-अलग जिलों के गांवों में बनाए गए हैं।

इन मैदानों में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और अन्य लोकप्रिय खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। खिलाड़ियों की जरूरत के अनुसार गांवों में खेल सामग्री भी दी जाएगी। जिस गांव में क्रिकेट अधिक लोकप्रिय होगा, वहां क्रिकेट किट उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

रात में भी खेल सकेंगे युवा : मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण खेल मैदानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इनमें रात के समय खेल गतिविधियों के लिए बड़ी रोशनी वाली व्यवस्था, पैदल चलने के लिए रास्ते, सुरक्षा जालियां और बच्चों के लिए झूले शामिल हैं। मैदानों के आसपास पौधे लगाकर हरित और स्वस्थ वातावरण तैयार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इन मैदानों का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को सुविधा देना नहीं, बल्कि गांवों में खेल संस्कृति को मजबूत करना भी है। बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी खेल और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इससे गांवों में आपसी भाईचारा, एकता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा।

6,000 ग्रामीण व्यायामशालाएं भी बनेंगी : भगवंत मान ने कहा कि सरकार इस वर्ष पंजाब में 6,000 ग्रामीण व्यायामशालाएं स्थापित कर रही है। इनमें से 500 का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि गांवों के युवाओं को अपने घर के नजदीक ही खेल और शारीरिक गतिविधियों की बेहतर सुविधाएं मिलें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे स्कूल और बेहतर खेल मैदान किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण खेल मैदानों को नशे के खिलाफ सरकार के अभियान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़कर उन्हें नशे से दूर रखने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2026 को खेलों और खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया है। राज्य के इतिहास में पहली बार खेलों के लिए 1,744 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा गया है।

केजरीवाल- पंजाब के चमके 19,200 स्कूल, शिक्षा व्यवस्था में आया बदलाव

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सरकारी स्कूलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने भाजपा नेतृत्व को खुली चुनौती देते हुए कहा कि गुजरात और पंजाब के 1,000-1,000 सरकारी स्कूलों की संयुक्त जांच कराई जाए, ताकि पूरे देश के सामने दोनों राज्यों की शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा लगातार पंजाब के सरकारी स्कूलों को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में भाजपा की सरकार को करीब 30 वर्ष हो चुके हैं, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को साढ़े चार साल हुए हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के स्कूलों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं की निष्पक्ष तुलना की जानी चाहिए।

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पंजाब के 1,000 स्कूलों की सूची वह उपलब्ध कराएंगे और गुजरात के 1,000 स्कूलों की सूची भाजपा दे। इसके बाद दोनों राज्यों के स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि इस प्रक्रिया में मीडिया के साथ भाजपा और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी शामिल हों, जिससे किसी तरह का विवाद न रहे।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पंजाब के स्कूलों को बदनाम करने के लिए पुराने वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वर्ष 2018 के वीडियो दिखाकर वर्तमान पंजाब सरकार के स्कूलों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने कहा कि पुरानी तस्वीरों और भ्रामक सामग्री के आधार पर मौजूदा व्यवस्था का आकलन नहीं किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में करीब 19,700 सरकारी स्कूल हैं और इनमें से 19,200 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी करीब 500 स्कूलों में सुधार का काम जारी है और अगले डेढ़ से दो वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

न्यूज ब्रीफ

लुधियाना जेल में सात मोबाइल बरामद सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। केंद्रीय जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। जेल की बैरकों में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान कैदी विकास कुमार, हवालाती जसकरण सिंह और लावारिस हालत में कुल सात मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले में पुलिस ने कैदी, हवालाती और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी दविंदर सिंह ने सहायक अधीक्षक विजय कुमार की शिकायत पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जेल परिसर में लगातार मोबाइल फोन बरामद होने के मामले सामने आ रहे हैं। इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मोबाइल जेल के भीतर कैसे पहुंचे और इनके इस्तेमाल के पीछे कौन लोग शामिल हैं।

जमीन में निवेश का झांसा देकर 16.81 करोड़ की धोखाधड़ी

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का लालच देकर 16.81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित सतपाल सचदेवा की शिकायत पर पुलिस ने अतुल मेहता और सलोनी मेहता के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि वे रियल एस्टेट की बड़ी परियोजनाओं से जुड़े हैं और उनके माध्यम से प्राइम लोकेशन पर जमीन कम कीमत में दिलाई जा सकती है। मुनाफे का लालच देकर पीड़ित से अलग-अलग किस्तों में कुल 16.81 करोड़ रुपये ले लिए गए। रकम लेने के बाद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री और दस्तावेज देने में टालमटोल शुरू कर दी। काफी समय बीतने के बावजूद न तो जमीन पीड़ित के नाम कराई गई और न ही रकम लौटाई गई। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधिकारियों ने विस्तृत जांच के बाद मामला दर्ज किया है। आरोपियों के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

मंडी फैंटनगंज में सड़क निर्माण बना मुसीबत बिखरी बजरी से राहगीर परेशान

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। सेंट्रल टाउन के सामने मंडी फैंटनगंज के पास सड़क निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। सड़क पर सीसी फ्लोरिंग के लिए बजरी और रेत का सामान बिखरा पड़ा है। मदर फ्लोर मिल चौक से प्रताप बाग की ओर जाने वाली सड़क पर जगह-जगह बजरी के ढेर लगे हैं। इससे वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बढ़ गया है और कई राहगीर चोटिल भी हो चुके हैं। आसपास रिहायशी क्षेत्र होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। लोगों ने ठेकेदार से निर्माण सामग्री सड़क से हटाकर सुरक्षित तरीके से काम करवाने की मांग की है।

लुधियाना की जगह ढंडारी कलां में रुकेंगी 14 ट्रेनें

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। अमृतसर और जालंधर सिटी से विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली शान-ए-पंजाब समेत 14 ट्रेनों का लुधियाना रेलवे स्टेशन के बजाय ढंडारी कलां रेलवे स्टेशन पर ठहराव बढ़ा दिया गया है। रेलवे के अनुसार यह व्यवस्था दिसंबर तक जारी रहेगी। ट्रेन संख्या 12054 अमृतसर-हरिद्वार और 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट का ठहराव अब 30-31 दिसंबर तक रहेगा। जालंधर सिटी-दरभंगा 22552 का ठहराव 27 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। वहीं 14616 अमृतसर-लालकुआं ट्रेन 26 दिसंबर तक ढंडारी कलां में रुकेगी। इसके अलावा 15212 अमृतसर-दरभंगा और 12204 अमृतसर-सहरसा का ठहराव 31 दिसंबर तक रहेगा। शान-ए-पंजाब 12498 अमृतसर-नई दिल्ली और 14680 अमृतसर-दिल्ली भी 31 दिसंबर तक ढंडारी कलां में रुकेंगी। 14650 अमृतसर-जयनगर का ठहराव 30 दिसंबर, जबकि 14674 अमृतसर-जयनगर का 31 दिसंबर तक रहेगा।

पंजाब में मतदाता पुनरीक्षण तेज, 12 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे मतदाता

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। नागरिकों की शिकायतों और सवालों के त्वरित समाधान के लिए राज्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ने सभी जिला शिकायत निवारण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। पुनरीक्षण के नोटिस चरण के दौरान 1950 हेल्पलाइन सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक संचालित होगी। यह व्यवस्था प्रक्रिया पूरी होने तक जारी रहेगी।

मसौदा मतदाता सूची 13 अगस्त को प्रकाशित हो चुकी है। मतदाता अपना नाम और विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब तथा निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी कार्यालयों में उपलब्ध सहायता केंद्रों से भी जानकारी ली जा सकती है।

12 सितंबर तक दावे-आपत्तियां : यदि मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, विवरण में गलती है, पता बदलना है या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करनी है तो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। दावे और आपत्तियां 13 अगस्त से 12 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। नया मत बनवाने के लिए प्रपत्र छह, नाम हटाने या आपत्ति के लिए प्रपत्र सात तथा विवरण में सुधार और पता बदलने के लिए प्रपत्र आठ का इस्तेमाल किया जाएगा।

18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, नया मत बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग एक अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे।

आठ अक्टूबर तक नोटिस चरण : पुनरीक्षण का नोटिस चरण 13 अगस्त से आठ अक्टूबर तक चलेगा। घर-घर सत्यापन के बाद ऐसे मतदाता जिनके पुराने विवरण का मिलान नहीं हो पाया है या जिनके अभिलेखों में विसंगति मिली है, उन्हें नोटिस जारी किया जा सकता है।

जेलों में नशे के आदी कैदियों के उपचार पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा पूरा ब्यौरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की जेलों में बंद नशे के आदी कैदियों के उपचार और पुनर्वास को लेकर पंजाब सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) को प्रदेश की सभी जेलों में बाह्य रोगी ओपिओइड उपचार ले रहे कैदियों का जेलवार विवरण हलफनामे के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि नशे पर निर्भर कैदियों को उपचार के दौरान दवाओं से धीरे-धीरे बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यह मामला मानसा सत्र मंडल के प्रशासनिक न्यायाधीश की रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका से जुड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार, मानसा जेल में कुल 767 कैदी बंद थे। इनमें से 530 कैदी बाह्य रोगी ओपिओइड उपचार केंद्र में पंजीकृत पाए गए। यह संख्या जेल की कुल कैदी आबादी का करीब 69 प्रतिशत है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए राज्य की सभी जेलों में नशे के आदी कैदियों की स्थिति और उनके उपचार की जानकारी मांगी है।

ब्यूप्रेनोर्फिन और नालोक्सोन से उपचार : खंडपीठ ने उपचार केंद्रों में कैदियों के पंजीकरण से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया स्पष्ट करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, चिकित्सा स्थिति के आधार पर बड़ी संख्या में नशे के आदी कैदियों को ब्यूप्रेनोर्फिन और नालोक्सोन का संयोजन दिया जा रहा है।

प्रशासनिक न्यायाधीश ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि जेल से बाहर आने के बाद कैदियों को नशामुक्ति और उपचार के लिए आगे किस प्रकार की सहायता मिलेगी। इसी को देखते हुए कोर्ट ने उपचार पूरा कर दवा बंद करने के चरण तक पहुंचने वाले कैदियों की संख्या का विवरण भी मांगा है।

मकानों में बदलाव नियमित करने की मांग, फेडरेशन ने दिल्ली नीति की तर्ज पर मांगा समाधान

चंडीगढ़ के सीएचबी मकानों में बदलाव नियमित करने की मांग, पांच लाख लोगों को राहत की उम्मीद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ आवास बोर्ड के मकानों में परिवारों की जरूरत के अनुसार किए गए बदलावों को एकमुश्त नियमित करने की मांग तेज हो गई है। चंडीगढ़ निवासी कल्याण महासंघ ने बोर्ड से व्यापक, पारदर्शी और व्यावहारिक नियमितीकरण नीति लागू करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि इस नीति से शहर में रहने वाले करीब पांच लाख लोगों को राहत मिल सकती है।

महासंघ के अनुसार चंडीगढ़ आवास बोर्ड की करीब 62 हजार से 68 हजार आवासीय इकाइयों में से 80 से 90 प्रतिशत मकानों में परिवारों की जरूरत के मुताबिक किसी न किसी तरह के बदलाव किए गए हैं। इनमें अतिरिक्त कमरे और शौचालय बनाना, बरामदे या बालकनी का उपयोग करना, आंगन को ढकना तथा घर में रोशनी, हवा और सामान रखने की सुविधा बढ़ाना शामिल है। महासंघ का कहना है कि इनमें से अधिकतर बदलाव व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिवारों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए हैं।

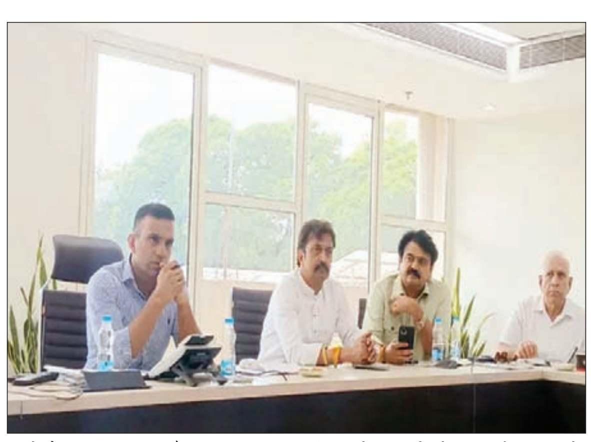

महासंघ के महासचिव डॉ. अनीश गर्ग ने कहा कि समय के साथ परिवारों का आकार बढ़ा है। बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों के लिए अतिरिक्त स्थान, निजता, सामान रखने की जगह तथा बेहतर रोशनी और हवा की आवश्यकता भी बढ़ी है। ऐसे में लोगों ने अपनी सीमित आवासीय जगह के भीतर आवश्यक बदलाव किए। कई लोगों ने उस समय लागू नियमों के अनुसार ही अपने मकानों में परिवर्तन किए थे, लेकिन बाद में नियमों में बदलाव होने के कारण वे कानूनी असमंजस में फंस गए।

महासंघ ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली की वर्ष 1999 की नियमितीकरण नीति की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी एकमुश्त नीति लागू करने का सुझाव दिया है। महासंघ के अनुसार निर्धारित मकान या भूखंड की सीमा के भीतर किए गए ऐसे बदलाव, जिनमें सरकारी अथवा साझा भूमि पर अतिक्रमण शामिल नहीं है, उन्हें उचित शुल्क और भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर नियमित किया जा सकता है।

महासंघ ने स्पष्ट किया कि सरकारी अथवा साझा भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्धारित आवासीय सीमा के भीतर परिवार की सामान्य जरूरतों के लिए किए गए बदलावों को लेकर प्रशासन को व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे लंबे समय से कानूनी अनिश्चितता का सामना कर रहे हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है।

महासंघ ने यह भी मांग की है कि मकानों में हुए पुराने उल्लंघनों को संपत्ति के हस्तांतरण और नामांतरण की प्रक्रिया से अलग रखा जाए। इससे लोगों को मकान बेचने, उपहार देने या विरासत में हस्तांतरित करने में अनिश्चितकाल तक परेशानी नहीं होगी। नियमितीकरण नीति तैयार करने में निवासी कल्याण समितियों को शामिल करने की मांग भी की गई है।

अकाली गठबंधन पर कार्यकर्ताओं का दोटूक जवाब, भाजपा ने बढ़ाई चुनावी तैयारी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं के बीच भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का दो दिवसीय पंजाब दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और जमीनी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।

दौरे के पहले दिन बीएल संतोष ने पटियाला और बठिंडा में पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठकों में भाजपा कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी राय ली गई। इस दौरान पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर सहमति नहीं जताई। कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा को अपने संगठन और जनाधार के दम पर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए।

कार्यकर्ताओं की राय सामने आने के बाद बीएल संतोष ने भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सभी

◆ अकाली दल से गठबंधन पर नहीं बनी सहमति, भाजपा ने सभी सीटों पर फुंका चुनावी बिगुल

विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार रहने पर जोर दिया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर गंभीरता से विचार कर रही है।

बीएल संतोष अपने दौरे के दूसरे दिन जालंधर, अमृतसर और लुधियाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के बीच अपनी स्थिति का भी आकलन कर रही है। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावना लंबे समय से राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है ।

लुधियाना नगर निगम सदन में चुनाव को लेकर हंगामा, दो पार्षदों में हाथापाई

चुनाव प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भिड़ंत, बैठक 15 मिनट रही स्थगित

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना

नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध समिति के दो नए सदस्यों के चुनाव को लेकर गुरु नानक देव भवन में आयोजित विशेष सदन की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। चुनाव की तारीख और मतदान की प्रक्रिया को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आमने-सामने आ गए। बहस के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद अश्वनी शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद गौरवजीत सिंह गोरा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते विवाद धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। सदन में मौजूद अन्य पार्षदों और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने दोनों को अलग किया।

हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही करीब 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बैठक शुरू होने के बाद से ही वित्त एवं अनुबंध समिति के दो सदस्यों के चुनाव की तारीख और प्रक्रिया को लेकर पक्ष और विपक्ष में मतभेद बने हुए थे। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने मांग की कि चुनाव और मतदान की प्रक्रिया मंगलवार को ही पूरी कराई जाए।

चुनाव प्रक्रिया को लेकर हुआ विवाद : बैठक के दौरान भाजपा पार्षदों की आम आदमी पार्टी के विधायक दलजीत सिंह ग्रेवाल के साथ चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान उनके पूर्व निजी सहायक और वर्तमान आप पार्षद अश्वनी शर्मा भी विवाद में शामिल हो गए। उनकी भाजपा पार्षद गौरवजीत सिंह गोरा के साथ तीखी बहस हो गई। दोनों के बीच धक्का-मुक्की शुरू होने के बाद सदन में अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर मौजूद पार्षदों और पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को अलग किया। इस घटना के बाद सदन का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। कुछ समय के लिए बैठक की कार्यवाही रोक दी गई। दोनों पक्षों के पार्षदों ने एक-दूसरे पर सदन का माहौल खराब करने के आरोप लगाए।

विपक्षी पार्षदों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय उसी दिन मतदान कराया जाना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि अदालत के निर्देश के अनुसार 25 अगस्त को वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्यों का चुनाव कराया जाना है। कांग्रेसी पार्षद गौरव भट्टी ने कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और अदालत ने चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष का आरोप था कि सत्तापक्ष के उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के कारण चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। भाजपा पार्षदों ने मांग की कि मतदान के लिए अलग से लंबी प्रक्रिया अपनाने के बजाय हाथ खड़े करवाकर वोटिंग करा दी जाए, ताकि चुनाव उसी दिन पूरा हो सके।

विपक्ष के लगातार विरोध के बीच नगर निगम प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों की जानकारी सदन में रखी। निगम सचिव विवेक वर्मा ने बताया कि निर्धारित नियमों के अनुसार शाम पांच बजे तक नामांकन पत्र लिए जा सकते हैं। नियम के मुताबिक नामांकन के बाद मतदान के लिए तीन दिन का अंतर जरूरी है। इसी आधार पर तत्काल मतदान कराना संभव नहीं बताया गया।

मेयर इंदरजीत कौर ने भी नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वित्त एवं अनुबंध समिति के दो सदस्यों का चुनाव 29 अगस्त को कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान गुप्त मतपत्र के माध्यम से होगा। इस घोषणा के बाद भी विपक्षी पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई और उसी दिन मतदान कराने की मांग दोहराई।

नगर निगम आयुक्त ओजस्वी अलंकार ने भी सदन को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार महापौर ही इस चुनाव के लिए अधिकृत चुनाव अधिकारी होंगी।

परीक्षा देते चन्नी की तस्वीर वायरल पूर्व मुख्यमंत्री ने बताई पूरी वजह

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब विश्वविद्यालय में परीक्षा देते हुए उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद उठे सवालों पर सफाई दी है। चन्नी ने कहा कि उन्होंने परीक्षा के दौरान किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उनका कहना है कि परीक्षा कक्ष में लिखते समय उनकी तस्वीर खींचना उनके नियंत्रण में नहीं था और वह पत्रकारों को तस्वीर लेने से रोक नहीं सकते थे।

चन्नी ने बताया कि उन्होंने 20 अगस्त को सार्वजनिक प्रशासन में एमए की परीक्षा दी थी। परीक्षा के दौरान अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर प्रश्नपत्र हल करते हुए उनकी तस्वीर सामने आई, जिसके बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। तस्वीर वायरल होने के बाद परीक्षा केंद्र में सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठाए गए।

चंडीगढ़ के पूर्व महापौर और पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेटर देवेश मोंगिल ने मामले की जांच की मांग की थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि परीक्षा कक्ष के भीतर तस्वीर कैसे खींची गई और क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति थी।

चन्नी ने कहा कि वह इससे पहले भी लगभग 20 बार परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन कभी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई। उनके अनुसार, इस बार कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल नहीं होने की जानकारी मीडिया को थी, इसलिए परीक्षा देते हुए उनकी तस्वीर सामने आ गई। उन्होंने दोहराया कि उन्होंने परीक्षा के दौरान सभी नियमों का पालन किया।

पंजाब विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. जगत भूषण ने भी मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि चन्नी की तस्वीर परीक्षा कक्ष के बाहर से ली गई थी। उनके सुरक्षाकर्मी भी परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद थे। विश्वविद्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक से इनकार किया है। विश्वविद्यालय के अनुसार संबंधित परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था।

चन्नी ने बताया कि यदि वह यह परीक्षा नहीं देते तो उनकी एमए की डिग्री पूरी होने में करीब एक वर्ष और लग सकता था। इसी शैक्षणिक प्रतिबद्धता के चलते उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के बजाय परीक्षा देना उचित समझा।

प्रमोशन में आरक्षण बहाली की मांग सीएम उमर से मिले भाजपा विधायक

सात भाजपा विधायकों ने सीएम उमर से आरक्षण बहाली की रखी मांग

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा के सात विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को श्रीनगर सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। विधायकों ने मुख्यमंत्री के समक्ष लंबे समय से लंबित इस मांग को रखा और आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के हित में जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल में कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण, बिश्नाह के डॉ. राजीव भगत, रामगढ़ के डॉ. देवेंद्र मन्याल, रामनगर के डॉ. सुनील भारद्वाज, सुचेतगढ़ के प्रो. गारू राम भगत, मढ़ के सुरिंदर कुमार और अखनूर के मोहन लाल शामिल रहे। विधायकों ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है और इसे लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में उचित अवसर और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उनका कहना था कि सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के हितों से जुड़े ऐसे मामलों का समयबद्ध समाधान होना जरूरी है।

> **विधायकों** ने उम्मीद जताई कि सरकार आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उनका कहना है कि पदोन्नति में आरक्षण बहाल होने से कर्मचारियों को सेवा में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। इस मुद्दे पर सरकार के स्तर पर विचार-विमर्श के बाद जल्द स्थिति स्पष्ट होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुना और न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित विषय पर आवश्यक पहल किए जाने की बात कही। बैठक के दौरान विधायकों ने कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की कोशिश की। पदोन्नति में आरक्षण बहाली का मामला जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों की ओर से समय-समय पर इसे बहाल करने की मांग उठाई जाती रही है। भाजपा विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा तेज होने की संभावना है। अब सभी की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई और इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पर है।

पदोन्नति आरक्षण बहाली की उम्मीद

विधायकों ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण बहाली से आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और उन्हें सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे। उन्होंने सरकार से इस मामले में कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर जल्द ठोस निर्णय लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लंबे समय से लंबित इस मांग के समाधान से कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी समस्याएं दूर होंगी। अब सरकार की ओर से होने वाली आगामी कार्रवाई पर सभी की नजर है। सरकार के निर्णय से कर्मचारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ईद मिलाद और रक्षा बंधन पर सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कड़ी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने आगामी ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षा बंधन और अन्य प्रमुख आयोजनों को लेकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कश्मीर पुलिस नियंत्रण कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा तैनाती, भीड़ प्रबंधन, निगरानी, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था पर चर्चा हुई। डीजीपी ने प्रमुख धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और विशेष रूप से दरगाह हजरतबल में पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और रणनीतिक स्थानों पर पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती के निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों पर यातायात प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार करने को कहा गया। बाजारों, मंदिरों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भी अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने सभी फील्ड इकाइयों को सतर्क और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त आकस्मिक व्यवस्था रखने को कहा।

यारवान जंगल में तलाशी के दौरान संदिग्ध हालत में पकड़े गए दोनों

पुलवामा में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई आतंकियों के दो सहयोगी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के दो कथित सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार राजपोरा के सीबी नाथ इलाके के यारवान जंगल में चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान दोनों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 12 राउंड गोलियां और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है।

पुलिस अधिकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों को क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी सहयोगियों की गतिविधियों के संबंध में खुफिया सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलवामा पुलिस ने सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 183वीं बटालियन के साथ मिलकर अभियान शुरू किया। संयुक्त टीम ने यारवान के जंगल और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने दो लोगों को जंगल वाले क्षेत्र से सीबी नाथ गांव की ओर संदिग्ध परिस्थितियों में आते देखा। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया और पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद होने की बात सामने आई। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान लस्सी डबन निवासी लतीफ अहमद दीदार पुत्र गुलाम मोहम्मद दीदार और बुन खा बमून निवासी एजाज अहमद बाजाद पुत्र नजीर अहमद बाजाद के रूप में हुई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि बरामद हथियार और गोला-बारूद उन्हें कहां से मिले तथा उनका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था।

पुलिस ने राजपोरा थाने में शस्त्र अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है। सुरक्षाबल गिरफ्तार आरोपितों के संभावित संपर्कों और गतिविधियों की भी पड़ताल कर रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में निगरानी और तलाशी अभियान बढ़ा दिया गया है।

श्रीनगर के लिए तीसरी वंदे भारत का एलान, फिर भी लोगों ने उठाए सवाल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी जरूरतों को लेकर सवाल उठाए हैं। नई ट्रेन उधमपुर होकर चलेगी और नवरात्र के दौरान सेवा शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय राज्य मंत्री और उधमपुर के सांसद जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के आधार पर इसकी जानकारी साझा की। नई वंदे भारत में उधमपुर को ठहराव मिलने से क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि केवल तेज गति की ट्रेनों से आम यात्रियों की सभी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए स्थानीय और सामान्य यात्री ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग भी उठाई है। लोगों ने मंत्री से पूछा कि नई सेवा का लाभ अधिक से अधिक स्थानीय यात्रियों तक कैसे पहुंचेगा।

सात साल से फरार दुष्कर्म आरोपी जम्मू से गिरफ्तार, फर्जी पहचान का कर रहा था इस्तेमाल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दुष्कर्म और अपहरण के मामले में करीब सात साल से फरार चल रहे आरोपी तौसीफ अहमद को जम्मू से गिरफ्तार कर लिया है। रियासी जिले का रहने वाला आरोपी वर्ष 2019 में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपनी पहचान छिपाता रहा और फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश और जांच के बाद उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई। इसके बाद विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे जम्मू से दबोच लिया।

विद्यार्थियों को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित

भारतेंदु संवाददाता, हीरानगर। जीएलडीएम राजकीय डिग्री कॉलेज हीरानगर में मिशन युवा के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उद्यमिता, स्वरोजगार, कौशल विकास और रोजगार के उपलब्ध अवसरों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में एसडीएम हीरानगर फूलैल सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार स्वरोजगार के विकल्प अपनाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कॉलेज की प्राचार्य डॉ. प्रज्ञा खन्ना ने भी विद्यार्थियों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

फारूक की रुहुल्ला को चुनौती इस्तीफा देकर फिर चुनाव लड़ें

रुहुल्ला के पार्टी विरोधी बयानों पर फारूक ने जताई नाराजगी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

नेशनल कान्फ्रेंस में जारी अंतर्कलह के बीच पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के बयानों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने रुहुल्ला को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतने का दावा करते हैं तो संसद की सदस्यता से इस्तीफा देकर दोबारा जनता के बीच जाएं। फारूक ने कहा कि तब पता चल जाएगा कि उनके साथ वास्तव में कितने लोग खड़े हैं।

फारूक अब्दुल्ला ने रुहुल्ला के उन दावों पर भी सवाल उठाए, जिनमें उन्होंने अपनी चुनावी जीत को व्यक्तिगत लोकप्रियता से जोड़ने की बात कही थी। उन्होंने पूछा कि क्या रुहुल्ला ने नेशनल कान्फ्रेंस के समर्थन के बिना चुनाव जीता था। फारूक ने कहा कि पार्टी और संगठन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने रुहुल्ला पर पार्टी की नीतियों और नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठाने का आरोप लगाया। साथ ही 1984 की घटना का उल्लेख करते हुए पार्टी के इतिहास और निष्ठा की याद दिलाई। उनके बयान से नेशनल कान्फ्रेंस के भीतर चल रही राजनीतिक खींचतान और तेज होने के संकेत मिले हैं। इसी बीच रुहुल्ला के समर्थकों ने भी अपनी बात रखने के संकेत दिए हैं, जिससे पार्टी में मतभेद और बढ़ने की आशंका है।

बिलावर में 9 ग्राम चिट्टे के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, बिलावर। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कठुआ पुलिस ने धर्मकोट क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब नौ ग्राम चिट्टा बरामद कर एक संदिग्ध नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा की देखरेख में की गई। पुलिस के अनुसार बिलावर थाना टीम को धर्मकोट क्षेत्र में नशीले पदार्थ की बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाका लगाया और संदिग्ध गतिविधियों में घूम रहे नीतन कपूर निवासी वार्ड नंबर चार, बिलावर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब नौ ग्राम चिट्टा और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने बरामद नशीले पदार्थ को कब्जे में लेकर आरोपित के खिलाफ थाना बिलावर में प्राथमिकी दर्ज की है।

जम्मू-कश्मीर के 714 स्कूलों में अब 12वीं तक होगी पढ़ाई

दूरदराज क्षेत्रों में विद्यार्थियों को घर के पास ही मिलेगी वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

714 स्कूल बनेंगे के-12 कंपोजिट, बढ़ेगा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा का दायरा।

जम्मू-कश्मीर में विद्यार्थियों को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। प्रदेश के 714 हाई स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से के-12 कंपोजिट स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। इसके तहत इन विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार का विशेष ध्यान दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों पर है, जहां 10वीं के बाद विद्यार्थियों को वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है। सरकार का मानना है कि नजदीक ही 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उपलब्ध होने से विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित नहीं होगी और स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आएगी। खासकर छात्राओं के लिए यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूर स्थित विद्यालयों में जाने की परेशानी कम होने से अधिक संख्या में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इसी क्रम में विद्यालयों में शिक्षकों और आवश्यक शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

ग्रामीण शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

इसके साथ ही विद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इससे दूरदराज इलाकों के छात्रों को अतिरिक्त यात्रा और आर्थिक खर्च से राहत मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार विद्यालयों के उन्नयन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच और मजबूत होगी।

विजयपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गिरा हिस्सा, एक की मौत

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

विजयपुर के जख इलाके में मंगलवार को दिल्ली-कटड़ा एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा अचानक गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना है, जबकि दो से तीन अन्य लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। फ्लाईओवर का हिस्सा गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया।

सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत-बचाव दल भी मौके पर पहुंचे। मलबे के नीचे किसी अन्य व्यक्ति के दबे होने की आशंका को देखते हुए राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन की ओर से घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर निर्माणाधीन ढांचे का एक हिस्सा अचानक गिरना हादसे की वजह माना जा रहा है। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया।

आतंकी की मां की संपत्ति नहीं होगी अटैच, जम्मू एनआईए कोर्ट का फैसला

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

आरोपी की मां की संपत्ति सुरक्षित

जम्मू की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने संपत्ति अटैच करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई संपत्ति आरोपित के नाम पर नहीं है और उसके स्वामित्व में नहीं है तो उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 33 के तहत अटैच नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने श्रीनगर के शाला कदल आतंकी मामले में आरोपित अरहान रसूल डार उर्फ टोटा की मां के नाम दर्ज मकान को अटैच करने की एनआईए की अर्जी खारिज कर दी। एनआईए की ओर से अदालत में आरोपित की मां के नाम दर्ज संपत्ति को अटैच करने की मांग की गई थी।

जांच एजेंसी का पक्ष था कि संपत्ति का मामले की कार्रवाई के तहत अटैच किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने संपत्ति के स्वामित्व से जुड़े तथ्यों और यूएपीए के प्रावधानों पर विचार करने के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने अपने फैसले में संपत्ति के वास्तविक स्वामित्व को महत्वपूर्ण आधार माना। कोर्ट ने कहा कि केवल किसी आरोपित से पारिवारिक संबंध होने के आधार पर उसके परिजन के नाम दर्ज संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सकता।

जम्मू-कश्मीर में सात युवा आईएफएस अफसरों की तैनाती

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के जंगलों की सुरक्षा और वन प्रबंधन को मजबूत करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विभाग ने 2024 बैच के एजीएमयूटी कैडर के सात युवा भारतीय वन सेवा अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों और वरिष्ठ कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह इन अधिकारियों की पहली फील्ड पोस्टिंग है।

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य वन क्षेत्रों की निगरानी, वन संपदा के संरक्षण और विभागीय कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों की तैनाती से जंगलों में अवैध कटान, अतिक्रमण और वन संसाधनों के दुरुपयोग पर निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है। इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन से जुड़े कार्यों को भी गति मिल सकती है।

युवा आईएफएस अधिकारियों को विभिन्न वन मंडलों में जिम्मेदारी मिलने से जमीनी स्तर पर वन विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिलने की संभावना है। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों और वन क्षेत्रों की चुनौतियों को समझते हुए संरक्षण तथा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। जम्मू-कश्मीर में वन क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन के साथ-साथ जल स्रोतों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में नई तैनाती को वन सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुभव और युवा ऊर्जा से विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद है। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर वनकर्मियों के साथ समन्वय बनाकर संरक्षण कार्यों को गति देने तथा पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर विशेष ध्यान देना होगा।

चार साल से किराया बकाया, जम्मू सब्जी मंडी की 46 दुकानें सील

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू

इंदिरा चौक स्थित सब्जी मंडी में चार साल से अधिक समय से किराया नहीं चुकाने वाले 46 दुकानदारों के खिलाफ जम्मू नगर निगम ने मंगलवार को कार्रवाई की। निगम की टीम ने बकाया किराए को लेकर कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर दुकानों पर नोटिस चिपकाए और ताले व सील लगा दी। कार्रवाई के बाद मंडी में कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण रही।

अधिकारियों के अनुसार दुकानदारों को पहले कई बार बकाया किराया जमा कराने के लिए कहा गया था। इसके बाद अंतिम नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद किराए का भुगतान नहीं किया गया। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि 46 आवंटियों पर चार साल से अधिक समय का किराया बकाया था। कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू नगर निगम के उपायुक्त उत्तर संजय बडियाल से मिला।

कार्रवाई शोपियां में दो ऑपरेशन, छह संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद

शोपियां में आतंकी नेटवर्क पर बड़ी चोट, छह संदिग्ध मददगार गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, शोपियां

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने आतंक के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग अभियानों में छह संदिग्ध आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षाबलों ने उनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड, एके-47 की मैगजीन, कारतूस और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए हैं।

पहली कार्रवाई हीरपोरा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान हुई। सुरक्षाबलों ने एक मोटरसाइकिल को रोककर उस पर सवार तीन लोगों को हिरासत में लिया। उनकी पहचान कुलगाम के चद्दर निवासी जुनैद मुजफ्फर डार, आमिर यूसुफ और मतलहामा निवासी जुनैद बशीर डार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से दो हैंड ग्रेनेड और आपत्तिजनक पोस्टर बरामद किए गए। इसके बाद सुरक्षाबलों ने दूसरे अभियान में तीन अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एके-47 की मैगजीन और कारतूस समेत अन्य सामग्री बरामद होने की जानकारी सामने आई है।

शोपियां में आतंक नेटवर्क पर कार्रवाई

मददगारों से पूछताछ जारी

सुरक्षाबलों के अनुसार बरामद हथियार और अन्य सामग्री के आधार पर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इनका संबंध किस आतंकी संगठन से था और हथियार व अन्य सामान कहां से प्राप्त किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इलाके में आतंकी गतिविधियों और उनके मददगारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

आरोपियों के संपर्कों की जांच

अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान सामने आने वाली जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों के संपर्कों और गतिविधियों की भी जांच कर रही हैं। साथ ही बरामद सामग्री की जांच कर उसके संभावित इस्तेमाल और स्रोत का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। आने वाले दिनों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी।

संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर

सुरक्षाबलों ने बताया कि अभियान के दौरान बरामद सामग्री को जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर गिरफ्तार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संभावित सहयोगियों तथा संपर्कों की भी जानकारी जुटा रही हैं। इसके अलावा इलाके में नाकों और गश्त को बढ़ाया गया है। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक समाजीकरण: डिजिटल युग में भारतीय लोकतंत्र की बदलती भूमिका

राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाओं, मूल्यों, विचारधाराओं, अधिकारों एवं कर्तव्यों को सीखता है तथा अपना राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित करता है। पारंपरिक रूप से परिवार, विद्यालय, मित्र-समूह, राजनीतिक दल, टेलीविजन और समाचार माध्यम इसके प्रमुख साधन रहे हैं, लेकिन डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को मौलिक रूप से बदल दिया है। अब राजनीति केवल संसद, चुनावी सभाओं और पार्टी कार्यालयों तक सीमित नहीं है - वह हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और व्हाट्सऐप राजनीतिक विचारों के निर्माण, प्रसार और विमर्श के केंद्रीय माध्यम बन गए हैं और यह परिवर्तन शहरों से गाँवों और जनजातीय क्षेत्रों तक फैल चुका है। सोशल मीडिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत में 109.28 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में 46.7 करोड़ सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं; इंस्टाग्राम पर 51.69 करोड़, फेसबुक पर 49.27 करोड़, व्हाट्सऐप पर 53.22 करोड़ और यूट्यूब पर 49.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। भारतीय उपयोगकर्ता प्रतिदिन औसतन 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जबकि 18-24 वर्ष के युवा इससे अधिक समय व्यतीत करते हैं; जेन-जी लगभग 40.7 करोड़ है और वह प्रतिदिन औसतन सात घंटे स्क्रीन पर बिताती है। इस व्यापक डिजिटल पहुँच ने राजनीतिक समाजीकरण की प्रकृति, गति और प्रभाव को गहराई से प्रभावित किया है।

राजनीतिक समाजीकरण की दृष्टि से सोशल मीडिया के तीन प्रमुख सकारात्मक प्रभाव हैं। प्रथम, यह राजनीतिक सूचना को लोकतांत्रिक बनाता है- अब नागरिक केवल समाचार सुनने-देखने वाला निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि सक्रिय सहभागी बन गया है, जो प्रतिक्रिया देता है, राय व्यक्त करता है और सूचना साझा करता है। किसी राजनीतिक निर्णय, सरकारी योजना, चुनावी घोषणा या सामाजिक मुद्दे पर नागरिक तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। इससे राजनीतिक संवाद अधिक व्यापक और त्वरित हुआ है। पहले राजनीतिक सूचना मुख्यत: समाचार पत्र, टेलीविजन और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से जनता तक पहुँचती थी, लेकिन अब नागरिक स्वयं भी सूचना के प्रसार का माध्यम बन गया है। इससे राजनीतिक विमर्श में उन वर्गों की भागीदारी बढ़ी है जिन्हें पारंपरिक माध्यमों में पर्याप्त स्थान नहीं मिलता था।

द्वितीय, सोशल मीडिया युवाओं के राजनीतिक समाजीकरण का प्रमुख साधन बन गया है- वे परिवार या शिक्षण संस्थानों की अपेक्षा सोशल मीडिया से अधिक राजनीतिक जानकारी प्राप्त करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020-21 का किसान आंदोलन, और हाल ही में जेन-जी का जंतर-मंतर तथा झारखंड आंदोलन इस बात के प्रमाण हैं कि

रतन नेगी
स्वतंत्र टिप्पणीकार, कुल्लू

सोशल मीडिया बिना किसी बड़े राजनीतिक संगठन के जनमत को आकार देने और वैश्विक पहुँच प्रदान करने की शक्ति रखता है। युवा वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक नेताओं, दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिक आंदोलनों से सीधे जुड़ सकता है। इससे उसकी राजनीतिक रुचि बढ़ती है और वह विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। तृतीय, इसने सामूहिक विरोध और नागरिक सहभागिता के लिए संगठनात्मक मंच उपलब्ध कराया है, जिससे आम नागरिक सशक्त हुआ है। ऑनलाइन अभियान, डिजिटल हस्ताक्षर, जनसमर्थन अभियान और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से संबंधित चर्चाएँ नागरिकों को अपनी आवाज उठाने का अवसर देती हैं।

तथापि, यह प्रक्रिया चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम उपयोगकर्ता की पूर्व-प्राथमिकताओं के अनुसार सामग्री क्यूरेट करके प्रतिध्वनि कक्ष यानी इको चैंबर और फ़िल्टर बुलबुले बनाते हैं, जिससे युवा केवल अपनी विचारधारा की पुष्टि करने वाली सूचनाओं तक सीमित हो जाते हैं, विरोधी विचारों का सामना कम होता है, और राजनीतिक ध्रुवीकरण गहराता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार अपनाना बहुत जरूरी

स्वस्थ जीवन के लिए केवल भरपेट भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित आहार लेना भी उतना ही आवश्यक है। संतुलित आहार वह भोजन है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व—कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रेशा (फाइबर) और पर्याप्त मात्रा में पानी, उचित अनुपात में शामिल हों। यही आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, रोगों से बचाता है और मानसिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की मात्रा के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में लोग अक्सर स्वाद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण फास्ट फूड, तली-भुनी चीजें और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ गया है। समय की कमी के कारण बहुत से लोग घर के पौष्टिक भोजन के बजाय बाहर का भोजन करना अधिक पसंद करते हैं। इसका परिणाम मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में सामने आता है। यदि हम अपने दैनिक भोजन में संतुलित आहार को शामिल करें तो इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है। स्वस्थ भोजन की आदतें शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायता करती हैं।

संतुलित आहार शरीर को पूरे दिन कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है। यह मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास, युवाओं की कार्यक्षमता तथा बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व होने से शरीर में कमजोरी और थकान कम होती है तथा व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को अधिक सक्रियता के साथ कर पाता है।

संतुलित आहार में हमें ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज जैसे गेहूं, जौ, बाजरा और ओट्स, दालें, राजमा, चना, सोयाबीन तथा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, दूध, दही, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पाद शामिल करने चाहियें। इसके अलावा सीमित मात्रा में स्वस्थ वसा जैसे मेवे, बीज और सरसों या मूंगफली का तेल, पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी को रोज़मर्रा के जीवन में नियमित रूप से शामिल करना चाहिये। अलग-अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर को विभिन्न पोषक तत्व आसानी से प्राप्त होते हैं। भोजन में मौसमी फल और सब्जियों को प्राथमिकता देना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।

संतुलित आहार अपनाने से जहां हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है, वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वजन नियंत्रित रहता है तथा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। हृदय, मधुमेह और मोटापे जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। मानसिक एकाग्रता और कार्यक्षमता बढ़ती है तथा त्वचा, बाल और हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। पर्याप्त पोषण मिलने से व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है और उसकी दैनिक गतिविधियों में सक्रियता बनी रहती है। संतुलित भोजन शरीर के साथ-साथ मन को भी स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतन्त्र लेखक ,गांव-कोटला, घुमारवीं

बच्चों के लिए संतुलित आहार का विशेष महत्व है, क्योंकि बढ़ती उम्र में शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। बच्चों के भोजन में दूध, दही, फल, सब्जियां, दालें और अनाज जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहियें। इसी प्रकार युवाओं को अपनी कार्यक्षमता और व्यस्त दिनचर्या के अनुसार पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। बुजुर्गों के लिए ऐसा भोजन अधिक उपयोगी होता है जो आसानी से पच सके और शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

स्वाइन फ्लू से बढ़ती चिंता

देश के कई हिस्सों में इन दिनों वायरल संक्रमण और फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, थकान और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को सामान्य मौसमी बीमारी मानकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। खासकर जब कुछ मरीजों में बुखार 103 से 104 डिग्री फॉरेनहाइट तक पहुंच रहा हो, तब स्वास्थ्य तंत्र के साथ-साथ आम लोगों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। बदलते मौसम में वायरल संक्रमण तेजी से फैल सकते हैं और कई बार इनके लक्षण शुरुआत में सामान्य सर्दी-जुकाम जैसे ही दिखाई देते हैं। यही वजह है कि बीमारी की गंभीरता को समझना और सही समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है।

बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ऐसे संक्रमण अधिक गंभीर रूप ले सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों में संक्रमण लंबे समय तक रह सकता है और कुछ मामलों में सांस से जुड़ी जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए परिवार में किसी सदस्य को लगातार तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो उसे सामान्य मौसमी बीमारी समझकर घर पर ही उपचार करते रहना उचित नहीं है।

एच1एन1 इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, जिसे आम बोलचाल में स्वाइन फ्लू कहा जाता है। हालांकि यह नाम पूरी तरह सटीक नहीं माना जाता। इन्फ्लुएंजा वायरस समय के साथ अपने स्वरूप में बदलाव करता रहता है। वायरस में होने वाले छोटे बदलावों को एंटीजेनिक ड्रिफ्ट और बड़े बदलावों को एंटीजेनिक शिफ्ट कहा जाता है। वायरस के स्वरूप में बदलाव के कारण संक्रमण के प्रसार और उससे बचाव की रणनीतियों में भी समय-समय पर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि इन्फ्लुएंजा के टीकों में भी समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि प्रचलित वायरस के प्रकार के खिलाफ सुरक्षा बेहतर हो सके।

इन्फ्लुएंजा को लेकर चिंता की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके लक्षण कई अन्य श्वसन संक्रमणों से मिलते-जुलते हो सकते हैं। कोविड सहित कई वायरल संक्रमणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान और शरीर में दर्द जैसी शिकायतें सामने आ सकती हैं। केवल लक्षणों के आधार पर इनके बीच अंतर करना हमेशा संभव नहीं होता। ऐसे में स्वयं बीमारी का अनुमान लगाकर दवा लेना उचित नहीं है। चिकित्सक की सलाह और आवश्यकता पड़ने पर जांच के आधार पर ही उपचार का निर्णय लिया जाना चाहिए।

विशेष रूप से एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। वायरल संक्रमण में एंटीबायोटिक हर स्थिति में उपयोगी नहीं होती। बिना चिकित्सकीय सलाह के एंटीबायोटिक लेने से शरीर पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है और भविष्य में दवाओं के प्रति प्रतिरोध की समस्या भी बढ़ सकती है। इसी तरह बुखार कम करने या अन्य लक्षणों से राहत पाने के लिए भी दवाओं का सेवन विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए।

गंभीर लक्षण सामने आने पर जांच और उपचार में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि तेज बुखार लंबे समय तक बना रहे, सांस लेने में परेशानी हो, सीने में दर्द महसूस हो, अत्यधिक कमजोरी हो, मरीज असामान्य रूप से सुस्त दिखाई दे या उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही हो तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना आवश्यक है। बच्चों और बुजुर्गों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनमें बीमारी की गंभीरता कभी-कभी तेजी से बढ़ सकती है।

सरकारों और स्वास्थ्य विभागों की जिम्मेदारी भी इस समय काफी बढ़ जाती है। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जांच केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें। जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही हो, वहां संक्रमण की निगरानी मजबूत की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभागों को स्थिति का नियमित आकलन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर समय रहते परामर्श और दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और अनावश्यक भय या अफवाहों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

अस्पतालों में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं, जांच सुविधाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा भी जरूरी है। गंभीर मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर और आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित करना स्वास्थ्य व्यवस्था की प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि लोगों को छोटी बीमारी के गंभीर रूप लेने का इंतजार न करना पड़े और उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सलाह मिल सके।

स्वास्थ्य विभागों को संक्रमण से जुड़े आंकड़ों की निगरानी भी प्रभावी तरीके से करनी चाहिए। अलग-अलग क्षेत्रों में मरीजों की संख्या, गंभीर मामलों और अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति का विश्लेषण करके संभावित वृद्धि का समय रहते पता लगाया जा सकता है। निगरानी मजबूत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था को जरूरत के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को भी बदलती स्थिति के अनुसार आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

-शिवांश धाकड़

कविता

नैरेटिव बन रहा है, कुछ तो जरूर होगा!

संजय एम तरानेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर-452011 (मध्य प्रदेश)

अब हवा में फिर सवाल तैर रहे हैं, गलियों में फिर
कयास ठहर रहे हैं। सरकार चुप है और चेहरे गंभीर हैं।
हमें तो ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ नए-नवेले
तीर तैयार हो रहे हैं। बैठक पर बैठक, चर्चा पर चर्चा,
खबरों में रहस्य, सियासत में गर्मी। यूं कभी सुरक्षा और
सीमाओं की बात, यारों, अब हर संकेत में ढूंढी जा रही है
किसी बहुत बड़े फैसले की आहट। कहते हैं—कुछ बड़ा
होने वाला है, वे यह भी कहते हैं—तैयारी पूरी है, मगर
आज सवाल यही है आखिर क्या?
वर्तमान में हर खामोशी को सनसनी का आयाम बनाना
जरूरी है? ये नैरेटिव भी आज अजीब चीज है, पहले
खबर बनती है और फिर माहौल, फिर माहौल से ही
उम्मीदें जगती हैं। और अंत में यहीं जनता पूछती है—अरे
बताओ आखिर में हुआ क्या?
कयासों की इस भीड़ में सच कहीं पीछे छूट जाता है।
हर बयान अपने साथ नया सवाल लाता है और हर चुप्पी
को लोग अपने-अपने अर्थ देने लगते हैं। ऐसे समय में
जरूरत है कि अफवाहों से ऊपर उठकर तथ्यों को समझा
जाए और किसी भी बड़े निष्कर्ष से पहले आधिकारिक
जानकारी का इंतजार किया जाए।
सवालों की इस धुंध में सच की रोशनी कहीं खो न
जाए, इसलिए जरूरी है कि हर खबर को परखा जाए।
वक्त बताएगा पर्दे के पीछे क्या है, और जनता को आखिर
मिलेगा जवाब।

चुटकी भर सिंदूर, रिश्तों में विश्वास और प्रेम की पहचान

भारतीय संस्कृति में विवाहिता महिला की मांग में सिंदूर न होना उसके सामने कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर देता है। शादीशुदा औरत के माथे पर लगा सिंदूर उसके यौवनावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक उसका सूचक होता है यानी उसकी खूबसूरती में अहम भूमिका होती है और यही हमारी संस्कृति, परंपरा, संस्कार और सभ्यता भी है, जो अमूल्य है। यही वजह है कि आज भी हमारी यह सांस्कृतिक परम्पराएं अपना विशेष एवं अक्षुण्ण महत्व रखती हैं। जहां तीज-त्योहारों में चाहे पुरुष हो अथवा महिला क्रमश: नए आकर्षक वस्त्र और साड़ी-सूट पहनकर तथा साजसज्जा व अन्य श्रृंगार से लकदक इनकी सुन्दरता-खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। विवाहिता महिलाएं वहीं बड़ी ही उत्सुकता से इन उत्सवों का इंतजार करती हैं और पारम्परिक तौर-तरीकों को अपनाते हुए विधिविधान के साथ इनका निर्वहन भी करती आ रही हैं।

विशेषकर वर्तमान समय में महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों, शादी-विवाह एवं महिलाओं के सर्वाधिक प्रिय तीज, करवा चौथ जैसे मंगल उत्सवों अथवा पार्टियों में शामिल होने के दौरान भरपूर श्रृंगार करती हैं। इसके लिए वह आधुनिक सौंदर्य केंद्रों में जाकर अपने सौंदर्य को निखारने और अपने चांद रूपी चेहरे को आकर्षक रूप देने का प्रयास करती हैं। महिलाओं के श्रृंगार में काजल, बिंदिया, लिपस्टिक, नेल्स पोलिश, मेहंदी और अपने सामर्थ्य अनुसार कानों-गले में क्रमश: अद्भुत डिजाइन से तराशे-निर्मित झुमके, हार-नेकलेस आदि भी पहने जाते हैं। यही नहीं, हाथों में कंगन-चूड़ियां, अंगुलियों में अनेक बनावट वाली अंगूठियां, पैरों में झंकृत करती पायल आदि गहने उनकी सुन्दरता में अतीव इजाफा करते हैं।

लेकिन शादीशुदा महिला जब तक अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर एवं गले में मंगलसूत्र और बाहों में लाल चूड़ा न पहन लें, तब तक उसका श्रृंगार हिन्दू परम्परा के अनुसार आधा-अधूरा सा लगता है और यही शादीशुदा स्त्री की वास्तविक पहचान व खूबसूरती भी इंगित करती है। विवाह में दूल्हा-दुल्हन परस्पर जहां वरमाला पहनाते हैं, वहीं सात फेरे लिए जाते हैं। दूसरी ओर, दूल्हा दुल्हन को गले में मंगलसूत्र पहनाकर विवाह की रस्म को अदा करता है, वहीं अगर दूल्हे राजा जब तक दुल्हन की मांग में चुटकी भर सिंदूर नहीं भर देता, तब तक विवाह की हिन्दू परम्परा सम्पन्न नहीं होती।

दुल्हन के माथे में लगाया गया चुटकी भर सिंदूर मात्र दुल्हन की शादीशुदा अथवा सुहागिन होने की एक निशानी ही नहीं, बल्कि अपने पति की अनवरत दीर्घायु, स्वस्थ रहने, समृद्धि तथा सुख-दुःख का प्रतीकात्मक चिन्ह भी है। सिंदूर सिर्फ विवाहित युगल के साथ रहने का प्रतीक ही नहीं, दोनों के बीच भावनात्मक एवं सामंजस्य मिलन का जीवन भर का सेतु पायदान भी है, जिस पर दोनों युगल जोड़े परस्पर अपनी

तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

यात्रा का शुभारंभ हमदम-हमसफर बनकर सफर तय करते हैं। हिन्दू धर्म में शादी दो आत्माओं का पवित्र बंधन माना जाता है और इसमें सिंदूर का अपना प्रमुख स्थान है।

हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार शादी के दौरान ही सिंदूर की रस्म को निभाया जाता है, तदुपरांत हिंदू धर्म की विवाहिता महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर निरन्तर लगाती रहती हैं। विवाहिता अगर सिंदूर न लगाये, तो हिंदू धर्म में इसे अशुभ माना जाता है। लेकिन हिन्दू धर्म की महिलाएं इस सिंदूर को क्यों लगाती हैं, यह जानना भी दिलचस्प है। हिंदू धर्म की विवाहित महिलाएं इसके महत्व को समझ सकती हैं और यह उनके लिए किसी अन्य वस्तु से बढ़कर नहीं है। विवाहित स्त्रियां सोलह श्रृंगार करती हैं तथा उनमें सिंदूर विवाहित स्त्री के पूर्ण रूप से सुहाग का प्रतीक माना गया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

राजनीति का चमकता सितारा

मेनका गांधी का जन्म 26 अगस्त 1956 को नई दिल्ली में हुआ। वह भारतीय राजनीतिज्ञ, पत्रकार, पर्यावरणविद् और पशु अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। उनका विवाह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और राजनेता संजय गांधी से हुआ था। संजय गांधी के निधन के बाद मेनका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और आगे चलकर भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।

मेनका गांधी
जन्म : 26 अगस्त 1956

मेनका गांधी कई बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही हैं और केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। वर्ष 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्य किया। इससे पहले भी वह केंद्र की विभिन्न सरकारों में मंत्री रह चुकी हैं।

राजनीति के अलावा मेनका गांधी पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए लंबे समय से सक्रिय रही हैं। उन्होंने पशुओं के अधिकारों और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। वह पशु कल्याण से संबंधित कई अभियानों और संस्थाओं से जुड़ी रही हैं।

मेनका गांधी ने लेखन के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। उन्होंने पशु कल्याण, कानून और शब्दों की उत्पत्ति जैसे विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय राजनीति और पशु अधिकार आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है।

मेनका गांधी ने पशु संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने पशुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा पर जोर दिया। उनके सामाजिक कार्यों ने देशभर में पशु कल्याण से जुड़े मुद्दों को व्यापक चर्चा का विषय बनाया।

भोलेनाथ की मणि के दर्शन से सफल मानी जाती है मणिमहेश यात्रा, श्रद्धालुओं में गहरी आस्था

मणिमहेश यात्रा हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक है, जिसका अपना एक विशेष महत्व है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधाष्टमी तक लगातार चलती है और प्रकृति आपदाओं के होते हुए भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा एवं आस्था लिए बिना अवरोध अपनी यात्रा जारी रखते हैं। परंतु प्रकृति आपदा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की तहसील भरमौर में यह प्रसिद्ध तीर्थ स्थान स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 13,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों के साथ-साथ प्रकृति के अद्भुत नजारों का भी अनुभव होता है।

मणिमहेश पर्वत पर भोर के समय यानी सुबह चार बजे एक ज्योति रूपी प्रकाश उभरता है। उसी को ही मणि के नाम से जाना जाता है, जिसके दर्शन हो जाना ही यात्रा का सफल होना माना जाता है। कभी-कभी तो यह प्रकाश सीधा पर्वत की गोद में बनी झील पर पड़ता है, जिसको स्थानीय भाषा में डल के नाम से भी जाना जाता है। यह इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बने आसन पर विराजमान हैं और यह जो अलौकिक प्रकाश है, वह उनके गले में विराजित नाग की मणि का प्रकाश है। इसी कारण इस स्थान को मणिमहेश के नाम से जाना जाता है।

श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लिए ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी और उबड़-खाबड़ रास्तों को बिना किसी झिझक के बीचों-बीच चलते हुए अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। सभी रमणीय घाटियों को पार करते हुए श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं। मणिमहेश पहुंचकर पर्वत की गोद में बनी झील को देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। यह झील अपने आप में एक दर्शनीय स्थल है और श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र भी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश में स्नान कर पूजा करते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर यहां लोहे का त्रिशूल, छड़ी और झंडा चढ़ाते हैं। कई श्रद्धालुओं को यहां जात्रा चढ़ाते हुए भी देखा जा सकता है।

राधाष्टमी वाले दिन जब बड़े नहौण में यात्री यहां स्नान करते हैं तो इस स्नान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि बड़े नहौण में स्नान करने से मनुष्य को कई रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस विशेष अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचते हैं और पवित्र डल झील में स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं। इस दौरान पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठता है और चारों ओर भक्तिमय वातावरण देखने को मिलता है।

मणिमहेश यात्रा का प्रथम पड़ाव चंबा का चौगान है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आकर चौगान में विश्राम करते हैं तथा उसके बाद अपनी अगली यात्रा प्रारंभ करते हैं। यानी मणिमहेश यात्रा चंबा से शुरू होकर राख, धरबाला जैसी प्रमुख जगहों से होते हुए अन्य कई स्थानों से गुजरते हुए भरमौर पहुंचती है। भरमौर स्थित चौरासी मंदिर में श्रद्धालु विश्राम करते हैं। इसके पश्चात सबसे प्रथम ब्रह्माणी देवी जी के मंदिर जाकर मणिमहेश यात्रा को प्रारंभ करने की अनुमति लेते हैं।

माता ब्रह्माणी के मंदिर की दूरी भरमौर से लगभग 6 किलोमीटर है, जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता है कि मणिमहेश यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है, जब यह यात्रा श्री ब्रह्माणी माता के मंदिर से प्रारंभ की जाए। चंबा से भरमौर लगभग 65 से 67 किलोमीटर दूर है। यहां चौरासी एक धार्मिक स्थल है, जो 84 सिद्धों की तपोस्थली माना जाता है। यहां विश्व का एकमात्र धर्मराज मंदिर भी बताया जाता है। श्रद्धालु यहां दर्शन करने के पश्चात अपनी यात्रा सड़क मार्ग से हड़सर तक पूरी करते हैं, जो भरमौर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है।

हड़सर के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू होती है और लगभग 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। श्रद्धालु चाहें तो घोड़ों के ऊपर भी यह सफर तय कर सकते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। रास्ते में पहला पड़ाव धनछौ आता है। इसके बाद बंदर घाटी से होते हुए आगे का पड़ाव गौरीकुंड आता है। इस पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं को पहाड़ों की सुंदरता, ऊंची चोटियों, घाटियों और प्राकृतिक वातावरण का अद्भुत अनुभव होता है।

आनंद स्वरूप धीमान
सेवानिवृत्त कोषाधिकारी, पंचरुखी, जिला कांगड़ा

मणिमहेश की डल झील श्री महादेव जी की तपोस्थली मानी जाती है। इसलिए यात्री मणिमहेश के दर्शन करने के उपरांत यहां झील की परिक्रमा कर पुण्य का फल कमाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और आत्मिक शांति प्राप्त करने का माध्यम भी है। कठिन रास्ते, ऊंची चढ़ाई और प्रकृति की चुनौतियां भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पातीं। भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा उन्हें हर कठिनाई को पार करने का साहस देती है। मणिमहेश यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की व्यवस्था की जाती है। प्रकृति आपदा की आशंका को देखते हुए यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

सहारनपुर में चार साल में 478 बेटियों ने छोड़ा घर

एजेंसी, सहारनपुर

सहारनपुर जिले में नाबालिग और युवतियों के घर छोड़ने के बढ़ते मामलों ने परिवारों के साथ पुलिस-प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पिछले चार वर्षों में 478 लड़कियों के घर छोड़ने के मामले सामने आए हैं। इनमें नाबालिग किशोरियों के साथ युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में ऑनलाइन दोस्ती, प्रेम प्रसंग और इंटरनेट के माध्यम से बने संबंध प्रमुख कारण के रूप में सामने आए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण किशोरियों और युवतियों की अनजान लोगों से बातचीत बढ़ी है। कई मामलों में ऑनलाइन संपर्क के बाद दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई और इसके बाद युवतियां परिवार को बिना बताए घर से निकल गईं। कुछ मामलों में युवकों की ओर से शादी या बेहतर भविष्य के झूठे वादे किए जाने की बात भी सामने आई है।

पुलिस का मानना है कि पारिवारिक संवाद की कमी भी इस समस्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। किशोरियों की गतिविधियों और उनकी परेशानियों पर परिवार की नजर नहीं होने से कई बार स्थिति गंभीर हो जाती है। पुलिस ऐसे मामलों में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू करती है और बरामदगी के बाद संबंधित परिस्थितियों की जांच करती है। अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर जागरूक रहें। साथ ही किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क, संदिग्ध बातचीत या अचानक व्यवहार में बदलाव दिखाई देने पर गंभीरता से ध्यान दें। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और परिवार में बेहतर संवाद से ऐसे मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

न्यूज ब्रीफ

फिरोजाबाद में हत्यारोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

एजेंसी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस ने हत्या के मामले में वांछित आरोपी आकाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घेराबंदी के दौरान आरोपी ने टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 23 अगस्त को नगला गुलरिया स्थित निर्माणाधीन मकान में कमल का शव मिला था। मृतक के पिता की तहरीर पर आकाश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 22 अगस्त की रात लिफ्ट देने के बाद उसने कमल के साथ कुकर्म का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उसने ईंट से सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, मृतक का मोबाइल, कपड़े और घटना में प्रयुक्त लोडर टिर्री बरामद की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर लगातार घटा, सभी तटबंध सुरक्षित

एजेंसी, प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट आने से बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। जिला प्रशासन की मंगलवार सुबह जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब पांच मीटर नीचे है। पिछले 24 घंटे में गंगा और यमुना के जलस्तर में 38 से 42 सेंटीमीटर तक कमी दर्ज की गई। नैनी में यमुना का जलस्तर 79.74 मीटर रहा, जबकि फाफामऊ में गंगा 80.69 मीटर पर दर्ज हुई। छतनाग में गंगा का जलस्तर 79.28 मीटर रहा। एसटीपी-बक्सी बांध पर जलस्तर 79.90 मीटर दर्ज किया गया। प्रशासन के अनुसार जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। नदी किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है।

मुरादाबाद सपा में फिर गुटबाजी तेज एसटी हसन-रुचि वीरा आमने-सामने

एजेंसी, मुरादाबाद। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आती दिख रही है। अजीमुश्शान जलसा-ए-आम के निमंत्रण पत्र में मौजूदा सांसद रुचि वीरा का नाम शामिल नहीं होने से उनके समर्थकों में नाराजगी है। कार्यक्रम की जिम्मेदारी पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन के नेतृत्व वाली कमेटी के पास है। वहीं जलसे में भाजपा एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त समेत अन्य लोगों को मुख्य अतिथि बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के समय से चली आ रही दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक खींचतान इस घटनाक्रम से फिर चर्चा में आ गई है। सांसद समर्थक इसे पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी के रूप में देख रहे हैं।

अंबेडकरनगर में ट्रक और स्कूल बस की टक्कर, 20 बच्चे सुरक्षित

एजेंसी, अंबेडकरनगर। अंबेडकरनगर में मालीपुर थाना क्षेत्र के सुरुहूरपुर के पास मंगलवार सुबह चीनी लदे ट्रक और स्कूल बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए। बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए पहुंच गए। सूचना मिलते ही मालीपुर पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बस में फंसे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हादसे में सभी बच्चे बाल-बाल बच गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बदली राना परिवार की सियासी कहानी

एजेंसी, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के सुजडू का राना परिवार कभी कारोबार और सियासत दोनों में मजबूत पहचान रखता था। खेती और स्क्रैप कारोबार से शुरुआत करने वाला परिवार आगे चलकर स्टील उद्योग में बड़ा नाम बना। इसके बाद परिवार के कई सदस्य नगरपालिका से लेकर विधानसभा और संसद तक पहुंचे। हालांकि समय के साथ परिवार पर कई गंभीर आरोप लगते रहे और विवाद बढ़ते गए। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद परिवार की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर होती गई। अब फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में पूर्व सांसद कादिर राना, पूर्व विधायक शाहनवाज राना और पूर्व विधायक नूर सलीम राना जांच के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने परिवार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर तलाशी ली है। ईडी की कार्रवाई से राना परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। कारोबार से सियासत तक पहुंचा परिवार अब कानूनी जांच और पुराने विवादों के बीच घिरा नजर आ रहा है।

योगी ने कहा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को बिना भेदभाव मिल रहे अवसर

छह माह में एक लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी: मुख्यमंत्री योगी

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उनकी सरकार ने नौ लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। इससे युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला था। विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को लंबे समय तक परिणाम का इंतजार करना पड़ता था।

कई मामलों में न्यायालय से रोक लग जाती थी और युवाओं का समय बर्बाद होता था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने नकल माफिया और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने माफिया की संपत्तियां जब्त करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया है। मंगलवार को कृषि तकनीकी सहायक और मंडी सचिवों समेत 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और अगले छह महीने में एक लाख युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है।

योगी ने परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में तेजी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षाओं और परिणामों में काफी समय लग जाता था। उनकी सरकार ने व्यवस्था में सुधार करते हुए परीक्षा और परिणाम की अवधि को काफी कम किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा युवाओं को परेशान करने का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा का आकलन करने का जरिया होना चाहिए। परीक्षा व्यवस्था को सरल और सहज बनाने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। युवाओं के पलायन, किसानों की समस्याओं, सुरक्षा व्यवस्था और बिजली संकट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी नौकरियों और बेहतर व्यवस्थाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। योगी ने बिजली व्यवस्था में सुधार का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को सीमित समय तक बिजली मिलती थी, जबकि अब सरकारी नलकूपों के लिए बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख और प्रमुख सचिव रविंद्र कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खतरे के निशान पर पहुंचा गंगा का जल स्तर, बाढ़ चौकिया अलर्ट

एजेंसी, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर मंगलवार को खतरे के निशान 137.10 मीटर पर पहुंच गया। इसके साथ ही करीब 100 ग्राम सभाएं बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। कई गांवों में पानी घरों और सड़कों तक पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार छतों और सड़क किनारे पॉलिथीन तानकर रहने को मजबूर हैं।

गंगा पार राजेपुर क्षेत्र में बाढ़ का असर सबसे अधिक दिखाई दे रहा है। राजेपुर की सड़कों पर पानी बह रहा है, जबकि तहसील, ब्लॉक कार्यालय और स्कूल भी जलमग्न हो गए हैं। मंझा की मड़ैया, चाचूपुर और लड़काताक समेत कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को सांप और जहरीले जीव-जंतुओं का डर सता रहा है। बाढ़ के कारण खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आजीविका खेती पर निर्भर है और फसल बर्बाद होने से बच्चों की पढ़ाई तथा शादी-विवाह पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने गंगा और रामगंगा की बाढ़ को हर वर्ष बड़ी समस्या बताया।

जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। जरूरत वाले गांवों में नाव भेजी जा रही हैं। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को भोजन, दवाएं और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अधिकारियों की टीमें गांवों में पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। वहीं नावों के माध्यम से लोगों को निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है।

लखनऊ-बहराइच हाईवे पर भीषण हादसा, डंपर की टक्कर से चार की मौत

एजेंसी, बाराबंकी

लखनऊ-बहराइच हाईवे पर मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार मौरंग लदे डंपर ने ऑल्टो कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

जानकारी के अनुसार, हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बिरौली में सुबह करीब 11 बजे हुआ। ऑल्टो कार में सवार लोग सड़क किनारे रुककर किसी से रास्ते की जानकारी ले रहे थे। इसके बाद चालक कार को बहराइच की ओर मोड़ रहा था। इसी दौरान लखनऊ की ओर से तेज गति से आ रहे मौरंग लदे डंपर ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए।

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कार में दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चे सवार थे। इनमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने घायल बच्ची को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ से फिरोजाबाद के कांच कारोबार पर संकट

एजेंसी, फिरोजाबाद

अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं पर सितंबर से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाने की तैयारी ने फिरोजाबाद के कांच उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका को बड़ी मात्रा में कांच के सजावटी और हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात करने वाले कारोबारियों को आशंका है कि शुल्क बढ़ने के बाद भारतीय उत्पाद वहां महंगे हो जाएंगे। इससे विदेशी खरीदारों की मांग प्रभावित हो सकती है और निर्यात में भारी गिरावट आने की संभावना है।

फिरोजाबाद देश-दुनिया में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां बड़ी संख्या में कारखानों और इकाइयों में कांच के सजावटी सामान, हस्तशिल्प उत्पाद, दीपक, झूमर, सजावटी वस्तुएं और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इन उत्पादों की विदेशों में अच्छी मांग रही है।

अमेरिका भी फिरोजाबाद के कांच कारोबार के प्रमुख बाजारों में शामिल है। ऐसे में वहां आयात शुल्क बढ़ने की खबर से निर्यातकों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि निर्यात पहले से ही कई तरह की चुनौतियों से प्रभावित है। कच्चे माल की कीमत, ऊर्जा लागत, परिवहन खर्च और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच यदि अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया जाता है तो कारोबारियों के लिए कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना मुश्किल होगा। अमेरिकी खरीदार अधिक शुल्क का बोझ उठाने के बजाय दूसरे देशों से सस्ते उत्पाद खरीदने का विकल्प चुन सकते हैं। निर्यातकों के अनुसार इसका सीधा असर उत्पादन और रोजगार पर भी पड़ सकता है। यदि अमेरिका से मिलने वाले आर्डर कम हुए तो कई इकाइयों को उत्पादन घटाना पड़ सकता है।

इसका प्रभाव कांच कारखानों में काम करने वाले मजदूरों, कारीगरों, पैकिंग कर्मचारियों और परिवहन से जुड़े लोगों पर पड़ने की आशंका है। कांच हस्तशिल्प से जुड़े छोटे कारोबारियों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को इस स्थिति में निर्यातकों को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के साथ व्यापारिक स्तर पर बातचीत कर शुल्क के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

◆ **कारोबारियों** ने सरकार से निर्यातकों को राहत देने के साथ वैकल्पिक विदेशी बाजारों में पहुंच बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम उठाए गए तो कांच उद्योग को संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है और हजारों लोगों के रोजगार पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सकेगा।

एसएन मेडिकल कॉलेज में पहला गुर्दा प्रत्यारोपण, पत्नी ने पति को दिया गुर्दा

एजेंसी, आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए पहले गुर्दा प्रत्यारोपण के दौरान पत्नी मीना ने अपने पति महेंद्र को गुर्दा दान कर वैवाहिक रिश्ते की मिसाल पेश की। परिवार की ओर से विरोध और पति के मना करने के बावजूद मीना अपने फैसले पर अडिग रहीं। उनका कहना था कि शादी केवल सुख के समय साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी एक-दूसरे का सहारा बनने का वचन है।

मीना ने कहा कि जीवन गुड्डे-गुड़िया का खेल नहीं है और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं। सुख-दुख जीवन का हिस्सा हैं। ऐसे में पति-पत्नी को कठिन समय में एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए गुर्दा दान करने का निर्णय लिया।

एसएन मेडिकल कॉलेज में यह पहला गुर्दा प्रत्यारोपण बताया गया है। प्रत्यारोपण के बाद मीना और महेंद्र दोनों चिकित्सकों की निगरानी में हैं। अस्पताल की किडनी प्रत्यारोपण इकाई में भर्ती महेंद्र से मीना ने बातचीत भी की। दोनों की स्थिति पर चिकित्सक लगातार नजर रख रहे हैं। मीना के इस फैसले ने वैवाहिक रिश्ते में त्याग और समर्पण की मिसाल पेश की है।

यूपी में 28 लाख टन चीनी का भंडार, संकट की खबरें खारिज

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी और संभावित संकट की खबरों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 28 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है, जो प्रदेश की जरूरत के हिसाब से लगभग सात महीने के लिए पर्याप्त है। मुख्यमंत्री ने लोगों से चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी तरह की चिंता न करने की अपील की। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हर महीने करीब चार लाख टन चीनी की खपत होती है। इसके बावजूद वर्तमान भंडार इतना है कि आने वाले कई महीनों तक आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी जरूरत पूरी करने के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों में भी चीनी उपलब्ध कराने की क्षमता रखता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर में प्रदेश की चीनी मिलों का नया पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद है। मिलों के दोबारा चालू होने के बाद करीब 90 लाख टन अतिरिक्त चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता और बढ़ेगी तथा आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी और संभावित कमी को लेकर चर्चा के बीच मुख्यमंत्री का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

मोहसिन रजा ने बीसीसीआई से की मांग, उत्तर प्रदेश को मिलें कम से कम चार क्रिकेट टीमें

◆ **बड़ी आबादी और प्रतिभाओं के बीच सीमित अवसरों पर उठे सवाल।**

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री और पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रजा ने प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं को अधिक अवसर देने के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कम से कम चार क्रिकेट टीमों का प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रतिभाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे में इतने बड़े प्रदेश के लिए केवल एक प्रमुख टीम का होना खिलाड़ियों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराता।

मोहसिन रजा ने कहा कि रणजी ट्रॉफी के अलावा अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 आयु वर्गों में भी उत्तर प्रदेश की कम से कम चार टीमें बनाई जानी चाहिए। इससे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता साबित करने का अधिक अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रतिभा होने के बावजूद सीमित अवसरों के कारण कई खिलाड़ी राज्य स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते।

टीमों की संख्या बढ़ने से उन्हें उच्च स्तर पर खेलने का मंच मिलेगा और आईपीएल तथा भारतीय टीम तक पहुंचने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। पूर्व रणजी क्रिकेटर के अनुसार अधिक टीमों के गठन से खिलाड़ियों का दूसरे राज्यों और संस्थानों की ओर पलायन भी कम होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी, भौगोलिक विस्तार और क्रिकेट प्रतिभाओं को देखते हुए प्रदेश के क्रिकेट ढांचे का विस्तार जरूरी है।

स्मार्टमीटर 35,345 आवेदन मिले, 25,452 घरों में सौर संयंत्र स्थापित; 22,363 लाभार्थियों को मिली सब्सिडी

पीएम सूर्य घर योजना को गति देने में जुटा प्रयागराज, 25,452 सौर संयंत्र स्थापित

एजेंसी, प्रयागराज

प्रयागराज में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। योजना के तहत जिले में अब तक 35,345 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 25,452 लाभार्थियों के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, 22,363 लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी की धनराशि भी भेजी जा चुकी है। इससे बड़ी संख्या में परिवारों को बिजली की लागत कम करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का अवसर मिल रहा है।

हालांकि, पिछले करीब 20 दिनों से स्मार्ट मीटर की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण योजना के क्रियान्वयन पर कुछ असर पड़ा है। स्मार्ट मीटर नहीं मिलने के कारण कई स्थानों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इससे लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ने की आशंका है और योजना की गति प्रभावित हो सकती है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को स्मार्ट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि मीटर की समस्या जल्द दूर हो और लंबित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके। अतिरिक्त सौंदर्य ऊर्जा, नेडा की नोडल अधिकारी कोमिल द्विवेदी ने बताया कि योजना के तहत जिन वेंडरों को कार्यादेश मिले हैं, वे अपनी क्षमता के अनुसार तेजी से काम कर रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं और पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता होते ही स्थापना से जुड़े लंबित कार्यों में तेजी आएगी। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ना है। इससे घरेलू स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ेगा और लोगों को अपेक्षाकृत सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होगा। प्रशासन और संबंधित विभाग योजना की प्रगति पर लगातार नजर रख रहे हैं। स्मार्ट मीटर की उपलब्धता होते ही लंबित सौर संयंत्रों की स्थापना में तेजी आने की उम्मीद है।

स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता कदम

विभागीय अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर की आपूर्ति बहाल होते ही लंबित आवेदनों पर तेजी से काम किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि पात्र परिवारों को जल्द योजना का लाभ मिले और सौर ऊर्जा उत्पादन में जिले की हिस्सेदारी लगातार बढ़े। अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट मीटर की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद सौर संयंत्रों की स्थापना में तेजी आएगी। लंबित आवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ना है। इससे घरेलू बिजली खर्च में कमी आएगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

वाराणसी में भारी बारिश से मकान की दीवार गिरी, पति-पत्नी की मौत

एजेंसी, वाराणसी

◆ **वाराणसी में भारी बारिश के बीच मकान की दीवार गिरने से दंपती की मौत।**

वाराणसी में रात हुई भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। मंडुवाडीह थाना क्षेत्र के चांदपुर इंडस्ट्रियल इलाके में मंगलवार तड़के एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे दबकर पति-पत्नी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रविन्द्र मिश्र (62) और उनकी पत्नी प्रतिभा देवी (55) के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार दंपती मूल रूप से झारखंड के गढ़वा जिले के डुमरिया गांव के रहने वाले थे। दोनों पिछले कई वर्षों से चांदपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रहकर मजदूरी करते थे और इसी से परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। उनका बेटा आनंद भी चांदपुर की एक कंपनी में काम करता है। बताया गया कि सोमवार रात आनंद की नाइट ड्यूटी थी। मंगलवार सुबह ड्यूटी पूरी करने के बाद वह बारिश के बीच घर पहुंचा। वहां मकान की दीवार गिरी देखकर वह घबरा गया।

घर के अंदर जाने पर उसने माता-पिता को मलबे में दबा देखा और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की भी मदद ली गई।

काफी प्रयास के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

1996 की तकनीकी त्रुटि से अटकी 64 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज

12 कॉलोनियां नियमित, अब यमुनानगर की 64 कच्ची कॉलोनियों पर सरकार की नजर

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर

यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में लंबे समय से अनअप्रूव्ड श्रेणी में शामिल 64 कच्ची कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने इन कॉलोनियों की सीमाएं निर्धारित करने और नियमितीकरण से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इससे इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भविष्य में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।

नगर निगम आयुक्त ने नियमितीकरण और सीमा निर्धारण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सहायक नगर योजनाकार, भवन निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आयुक्त ने 64 कॉलोनियों के सीमा निर्धारण के

लिए चल रहे सर्वे की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने अधिकारियों को सर्वे कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के तहत जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 1996 में जारी अधिसूचना के तहत यमुनानगर-जगाधरी क्षेत्र में कुल 76 कॉलोनियां अनअप्रूव्ड श्रेणी में शामिल थीं। इनमें 54 कॉलोनियां जगाधरी क्षेत्र और 22 कॉलोनियां यमुनानगर क्षेत्र में थीं। इनमें से 12 कॉलोनियों को पहले ही नियमित किया जा चुका है।

अब शेष 64 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नगर निगम के सामने फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम इन कॉलोनियों की वास्तविक सीमाएं निर्धारित करना है। इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। अधिकारियों को पुराने दस्तावेजों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर कॉलोनियों की स्थिति और सीमाओं का आकलन करना होगा। वर्ष 1996 से पहले के दस्तावेजों को भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को कई स्तरों पर लाभ मिल सकता है। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमित होने से क्षेत्र में विकास कार्यों को नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सड़क, नाली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को भी बेहतर ढंग से संचालित किए जाने की संभावना है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करने में भी आसानी होगी।

अंबाला में सांड का आतंक, स्कूल जा रही छात्रा पर किया हमला

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

अंबाला के लालकुर्ती इलाके में सोमवार सुबह बेसहारा सांड के हमले में 10वीं कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। खालसा स्कूल-टू में पढ़ने वाली छात्रा खुशी रोज की तरह सुबह करीब 7:15 बजे बैग लेकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान सड़क किनारे खड़े एक बेसहारा सांड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सांड ने छात्रा को सींगों से उठाकर करीब सात फीट ऊपर उछाल दिया और फिर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद भी सांड नहीं रुका और उसने छात्रा को कई बार पटककर घायल कर दिया।

हमले के दौरान छात्रा के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह सांड को वहां से हटाया और छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने उसके माथे पर आए गंभीर घाव पर आठ टांके लगाए। घटना के बाद छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और उसकी स्थिति की जानकारी ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में बेसहारा पशुओं की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सड़कों और गलियों में घूमने वाले सांडों के कारण लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। खासकर सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों में भय बना रहता है।

छात्रा पर हुए हमले के बाद लोगों ने प्रशासन से बेसहारा पशुओं को पकड़ने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से अभियान चलाकर सांडों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की मांग की है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की अपील की है।

न्यूज ब्रीफ

बारिश से गुरुग्राम बेहाल, सड़क में धंसा ट्रक; सोनीपत में अंडरपास डूबा

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार। हरियाणा के गुरुग्राम और सोनीपत में मंगलवार सुबह हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। गुरुग्राम में जलभराव के कारण कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहा। सेक्टर-9 में पानी भरने से एक ट्रक सड़क में धंस गया। हालात को देखते हुए गुरुग्राम में कर्मचारियों को घर से काम करने की सलाह दी गई, जबकि कई स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गईं। सोनीपत में करीब दो घंटे हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सांदल खुर्द गांव में सरकारी ट्रैक्टर अंडरपास में पानी भरने के कारण डूब गया। इससे प्रशासनिक अमले को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेवाड़ी में भी सुबह बूंदाबांदी दर्ज की गई। बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया और लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर बनाए रखी।

कैथल में पुलिस वाहन हादसा, शराब की बोतल मिलने से बढ़ा विवाद

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। कैथल में डायल-112 की गाड़ी मकान के गेट से टकराने के बाद विवाद खड़ा हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस वाहन के अंदर शराब की बोतल पड़ी देखी और पुलिसकर्मियों के नशे में होने का आरोप लगाया। इसके बाद लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया। मौके पर हंगामा बढ़ने पर पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचे। बताया गया कि शराब की बोतल के बारे में पूछे जाने पर एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर कहा कि तो क्या हो गया। लोगों के विरोध के बाद एसएचओ ने दोनों पुलिसकर्मियों को धक्के देकर पीसीआर वाहन में बैठाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। घटना के बाद डायल-112 कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

कुरुक्षेत्र हत्याकांड में बड़ा खुलासा, पत्नी ने तीन चाकुओं से किए वार

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पति की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी विमला ने पति राजेश पर तीन अलग-अलग चाकुओं से हमला किया था। जांच में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। बताया गया कि एक बड़े चाकू से सीने के नीचे से लेकर शरीर के निचले हिस्से तक लंबा चीरा लगाया गया था। इसके अलावा दो अन्य स्थानों पर भी गहरे घाव मिले। 22 अगस्त को हुई वारदात के बाद विमला छत से कूद गई थी। उसे भी चोटें आई थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वारदात के पीछे की वजह तथा घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नारनौल में मालगाड़ी की चपेट में आया आरपीएसएफ जवान, मौत

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। हरियाणा के नारनौल में न्यू अटेली रेलवे स्टेशन के पास डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से रेलवे पुलिस स्पेशल फोर्स के जवान की मौत हो गई। मृतक की पहचान रेवाड़ी निवासी जवान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अपने घर पर बिना बताए न्यू अटेली आया था। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। शुरुआती जांच में हादसा ट्रेन की चपेट में आने से होना बताया जा रहा है। हालांकि जवान रेलवे लाइन तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।

हरियाणा में कमजोर पड़ा मानसून, पलवल में 98 एमएम वर्षा से बदला मौसम

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों में सोमवार को अच्छी वर्षा दर्ज की गई, लेकिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम बादलवाही तक सीमित रहा। पलवल में सबसे अधिक 98 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा फरीदाबाद में 58 मिलीमीटर, मेवात में 48.5 मिलीमीटर, गुरुग्राम में 38 मिलीमीटर और रेवाड़ी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई।

बारिश के बाद दक्षिणी जिलों में मौसम सुहावना हुआ, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां सीमित रहीं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन के अनुसार हरियाणा में दक्षिण-पश्चिमी हवाएं तेज हो रही हैं, लेकिन मानसून फिलहाल कमजोर स्थिति में है।

पलवल में 98 एमएम बारिश, दक्षिणी हरियाणा में मानसून सक्रिय।

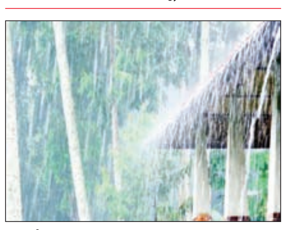

इसके चलते आने वाले दिनों में दक्षिणी हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद हरियाणा से मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मानसून कमजोर होने के साथ ही दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

कुरुक्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, कश्मीरी ट्रक चालक की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में दिल्ली-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मारकंडा कॉलोनी के पास हुए सड़क हादसे में जम्मू-कश्मीर निवासी ट्रक चालक जहांगीर अहमद रेशी की मौत हो गई। हादसे में उसका साथी मुस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि ट्रक में लोहे के सरिए लदे हुए थे। इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में लदे सरिए खिसककर चालक और उसके साथी के ऊपर जा गिरे। दोनों सरियों के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया। जहांगीर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल पांच साल में 17वीं बार जेल से बाहर

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मिल गई है। इसके साथ ही वह पिछले पांच वर्षों में 17वीं बार जेल से बाहर आएगा। यौन शोषण के मामले में 20 वर्ष की सजा काट रहा राम रहीम वर्तमान में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। पैरोल अवधि के दौरान उसके सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा पहुंचने की जानकारी सामने आई है।

इससे पहले मई 2026 में भी गुरमीत राम रहीम को 23 दिन की पैरोल मिली थी। अब एक बार फिर पैरोल मिलने के बाद उसके समर्थकों और डेरा अनुयायियों के बीच हलचल बढ़ गई है। पैरोल के दौरान उसे निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। जेल प्रशासन और संबंधित अधिकारी उसकी रिहाई से जुड़ी

औपचारिकताएं पूरी करेंगे।

गुरमीत राम रहीम को वर्ष 2017 में साध्वियों से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। 25 अगस्त 2017 को सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे दोनों मामलों में दोषी करार दिया था। इसके बाद 28 अगस्त 2017 को अदालत ने प्रत्येक मामले में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई थी। दोनों सजाओं को मिलाकर उसे कुल 20 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी है। राम रहीम की पैरोल को लेकर पहले भी कई बार चर्चा होती रही है। प्रत्येक बार उसकी अस्थायी रिहाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती रही हैं। इस बार भी 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद यह मामला चर्चा में है।

पैरोल मिलने के बाद अब जेल से बाहर आने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रोहतक से बाहर निकलने के बाद उसके सिरसा जाने की बात कही गई है। प्रशासन की ओर से पैरोल के दौरान लागू शर्तों की निगरानी की जाएगी। पांच वर्षों में 17वीं बार पैरोल मिलने के कारण यह घटनाक्रम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पैरोल के दौरान राम रहीम को निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा। प्रशासन उसकी गतिविधियों पर नजर रखेगा और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जा सकती है।

पानीपत की बाथमेट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत

शहर के जाटल रोड स्थित कश्यप कॉलोनी में मंगलवार सुबह बाथमेट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह करीब सात बजे फैक्ट्री से धुआं निकलता और आग की लपटें उठती देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना फैक्ट्री कर्मचारियों और दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में आग ने फैक्ट्री के भीतर रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।

सूचना मिलने के बाद सहायक अग्निशमन अधिकारी अमित गोस्वामी के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया। फैक्ट्री में बाथमेट बनाने के लिए रखा कच्चा माल और तैयार उत्पाद बड़ी मात्रा में मौजूद था। आग तेजी से फैलने के कारण राहत एवं बचाव दल को इसे नियंत्रित करने में काफी

सुबह सात बजे फैक्ट्री में भड़की आग, साढ़े आठ बजे दमकल ने पाया काबू।

मशक्कत करनी पड़ी। करीब डेढ़ घंटे की लगातार कोशिश के बाद सुबह साढ़े आठ बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

दमकल कर्मियों ने आग को फैक्ट्री के आसपास के हिस्सों में फैलने से भी रोक लिया। इससे आसपास स्थित अन्य प्रतिष्ठानों और भवनों को संभावित नुकसान से बचाया जा सका। आग बुझाने के दौरान क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई थी, जिसके कारण कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। आग की इस घटना में फैक्ट्री में रखा तैयार माल और कच्चा माल जलकर राख हो गया। इससे संचालक को लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि नुकसान का वास्तविक आकलन आग पूरी तरह शांत होने और फैक्ट्री के सामान की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और शॉर्ट सर्किट की संभावना को प्रमुख वजह माना जा रहा है।

घटना के बाद फैक्ट्री संचालक और कर्मचारियों ने नुकसान का जायजा लेना शुरू किया। आग से प्रभावित हिस्से में रखे सामान को काफी नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को आसपास की फैक्ट्रियों और भवनों तक फैलने से रोक लिया गया। अधिकारियों के अनुसार घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

होली के झगड़े की रंजिश में फतेहाबाद में व्यक्ति की हत्या, तलवार से हमला

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

होली के दौरान हुए झगड़े की पुरानी रंजिश में फतेहाबाद में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोमवार रात काम से बाइक पर घर लौट रहे 40 वर्षीय व्यक्ति को गांव में रास्ते में कुछ युवकों ने घेर लिया। इसके बाद आरोपितों ने लाठी-डंडों और तलवार से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे होली के दौरान हुआ पुराना विवाद कारण माना जा रहा है। पुलिस ने मामले में आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इधर, वारदात के बाद एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक कथित तौर पर हत्या की जिम्मेदारी लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में युवकों की ओर से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जा रहा है। पुलिस वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे युवकों की पहचान की जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश, हमले में शामिल लोगों और वायरल वीडियो के संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा है।हर्ष की हत्या से गांव में तनाव, पुलिस ने आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज की; वायरल वीडियो की भी हो रही जांच, पुरानी रंजिश को माना जा रहा वारदात का कारण।

हरियाणा में नकली पनीर और घी की बिक्री पर रोक, उल्लंघन करने वालों को होगी जेल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने आम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले नकली और नॉन-डेयरी खाद्य उत्पादों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में वनस्पति तेल, स्टार्च और विभिन्न रसायनों से तैयार किए जाने वाले नकली पनीर और घी के उत्पादन व बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नए नियम मंगलवार से प्रभावी हो गए हैं। सरकार के इस फैसले का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर जेल की सजा भी हो सकती है।

सरकार के अनुसार बाजार में दूध से बने असली उत्पादों के नाम पर एनालॉग या नॉन-डेयरी पनीर, घी और अन्य खाद्य पदार्थ बेचे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ढाबों, होटलों और मिठाई की दुकानों में मक्खन और देसी घी के नाम पर वनस्पति तेल तथा पाम आयल के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर उन्हें

नकली पनीर और घी पर हरियाणा सरकार का कड़ा प्रहार।

जब्त कर नष्ट किया जाएगा। नकली पनीर और घी की बढ़ती बिक्री को लेकर सरकार गंभीर है, क्योंकि इनके सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग अब बाजार में जांच अभियान तेज करेगा और संदिग्ध उत्पादों के नमूने लेकर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट या असली डेयरी उत्पादों के नाम पर नकली सामान बेचने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है।

खाद्य सुरक्षा विभाग दुकानों, डेयरियों, होटलों और ढाबों में विशेष जांच अभियान चलाएगा। अधिकारियों ने कारोबारियों को चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित नॉन-डेयरी उत्पादों का निर्माण, भंडारण और बिक्री तत्काल बंद करें। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित सामान जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सख्ती से मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार पर रोक लगेगी और लोगों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

नन्हे हाथों से बनी राखियों ने जीता एसपी का दिल, बोले- यह विश्वास का धागा

हांसी के बच्चों ने हस्तनिर्मित राखियों और संदेशों से सुरक्षा प्रहरियों के प्रति जताया सम्मान

भारतेन्दु संवाददाता, हांसी

रक्षाबंधन के पर्व को राष्ट्र रक्षा के संकल्प से जोड़ने वाले दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व अभियान के तहत हांसी के बच्चों ने सुरक्षा प्रहरियों के प्रति अपने सम्मान और कृतज्ञता का अनूठा संदेश दिया। बच्चों के नन्हे हाथों से तैयार की गई रंग-बिरंगी राखियां और उनके साथ लिखे भावनात्मक संदेश सोमवार को हांसी स्थित एसपी कार्यालय पहुंचे। राखियों को देखकर एसपी विनोद कुमार भावुक हो गए और उन्होंने बच्चों की भावनाओं की सराहना की।

बच्चों ने अपनी कल्पना और रचनात्मकता से अलग-अलग तरह की राखियां तैयार की थीं। किसी राखी में तिरंगे के रंगों की सुंदरता दिखाई दे रही थी तो किसी को मोतियों, सितारों और रंग-बिरंगे धागों से सजाया गया था। इन राखियों की विशेषता केवल उनकी सजावट नहीं थी, बल्कि उनके साथ लिखे गए संदेश भी थे। बच्चों ने कागज पर सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मियों और जवानों के प्रति धन्यवाद, सम्मान और शुभकामनाएं व्यक्त की थीं। जब ये राखियां एसपी विनोद कुमार के कार्यालय पहुंचीं तो उन्होंने बच्चों द्वारा तैयार प्रत्येक राखी और संदेश को ध्यानपूर्वक देखा। संदेश पढ़ते समय उनके

चेहरे पर बच्चों के प्रति स्नेह और सम्मान साफ नजर आया।

किसी बच्चे ने पुलिसकर्मियों को सुरक्षित समाज के लिए धन्यवाद दिया था तो किसी ने त्योहार के अवसर पर भी अपने कर्तव्य पर तैनात रहने वाले सुरक्षा प्रहरियों के प्रति सम्मान जताया था। एसपी विनोद कुमार ने कहा कि राखी केवल एक धागा नहीं है, बल्कि बच्चों की ओर से जताया गया विश्वास है। इस विश्वास के साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। बच्चों का स्नेह पुलिसकर्मियों को यह याद दिलाता है कि समाज और विशेषकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर वर्दी से बड़ी अपेक्षाएं जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा पुलिस की सबसे बड़ी ताकत है और इस भरोसे को कायम रखना प्रत्येक पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि वे शिक्षा, अनुशासन और अच्छे संस्कारों को जीवन का आधार बनाएं। देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ें।

उन्होंने बच्चों द्वारा भेजी गई राखियों को सहेजकर रखने की बात भी कही। दैनिक जागरण का भारत रक्षा पर्व पिछले दो दशकों से राष्ट्रभक्ति और जनसहभागिता को समर्पित अभियान के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य रक्षाबंधन के पारंपरिक पर्व को देश की सुरक्षा में तैनात जवानों और सुरक्षा प्रहरियों के प्रति सम्मान तथा कृतज्ञता से जोड़ना है। अभियान के माध्यम से बच्चों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सुरक्षा बलों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इस अभियान के तहत देशभर के स्कूलों, महाविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और नागरिकों को हस्तनिर्मित राखियां, शुभकामना संदेश और पत्र तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन राखियों और संदेशों के माध्यम से सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों तक लोगों की भावनाएं पहुंचाई जाती हैं।

हांसी के बच्चों ने भी इसी भावना के साथ राखियां तैयार कीं। उन्होंने अपने हाथों से राखियां बनाने के साथ उनमें देशप्रेम और सुरक्षा प्रहरियों के प्रति सम्मान की भावनाएं पिरोईं। बच्चों के संदेशों में यह भावना प्रमुख थी कि सुरक्षा में तैनात जवानों और पुलिसकर्मियों के कारण ही आम नागरिक सुरक्षित जीवन जी पा रहे हैं। इस तरह बच्चों की बनाई राखियां केवल रक्षाबंधन की रस्म तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने समाज और सुरक्षा प्रहरियों के बीच विश्वास और आत्मीयता का रिश्ता मजबूत किया। एसपी कार्यालय पहुंची इन राखियों ने यह संदेश दिया कि देश की सुरक्षा में जुटे जवानों और पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान केवल किसी एक दिन की भावना नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है।

करनाल में हर्ष एनकाउंटर के विरोध में उमड़ा रोड़ समाज, 30 तक कार्रवाई की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल

हर्ष एनकाउंटर मामले की जांच की मांग को लेकर सोमवार को रोड़ समाज के हजारों लोगों ने करनाल में जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोग सुबह करीब 10 बजे रोड़ धर्मशाला में एकत्रित हुए। करनाल के अलावा कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत समेत आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रोड़ धर्मशाला में बैठक के बाद रोड़ महासभा के प्रधान बलकार पुंडरी की अगुवाई में लोगों ने शहर में पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी हर्ष एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। यहां लोगों ने धरना दिया और सरकार से मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग उठाई।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर समाज में रोष है और उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। समाज की ओर से सरकार को तीन प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए 30 अगस्त तक का समय दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 30 अगस्त को तरावड़ी में मुख्यमंत्री की प्रस्तावित रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने रैली स्थल के सामने अपना तंबू लगाने की भी चेतावनी दी। इससे

प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बढ़ सकती है। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की मांग की।

डीसी डा. आनंद शर्मा ज्ञापन लेने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर उन्होंने जमीन पर बैठकर ज्ञापन लिया। उन्होंने लोगों को मामले में जांच का आश्वासन दिया और उनकी मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पुलिसकर्मी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मुख्य मांग हर्ष एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच है। समाज के लोगों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रखने की रणनीति बनाई जाएगी। प्रदर्शन के कारण करनाल में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी मामला चर्चा का विषय बना रहा।

नोएडा-गाजियाबाद सफर होगा आसान शाहबेरी सड़क की चौड़ाई 15 मीटर होगी

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद से नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने-जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। एनएच-9 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को शाहबेरी से जोड़ने वाली सड़क को जल्द ही दोगुने से अधिक चौड़ा किया जाएगा। इससे क्रॉसिंग रिपब्लिक समेत आसपास की दर्जनों सोसाइटियों में रहने वाले लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद दो से तीन महीने में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। सड़क की चौड़ाई सात मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर की जाएगी। इससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी और सड़क पर बनने वाले जाम से राहत मिलेगी।

एनएच-9 से शाहबेरी जाने वाले मार्ग पर क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी स्थित है। इस सोसाइटी में करीब 15 हजार फ्लैट हैं, जिनमें लगभग 60 से 70 हजार लोग रहते हैं। यहां से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम की ओर नौकरी तथा कारोबार के लिए रोजाना आते-जाते हैं। वर्तमान में सड़क संकरी होने के कारण सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। स्कूल और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के वाहन भी जाम में फंसते हैं। शाहबेरी पुलिया से आगे ग्रेटर नोएडा की ओर सड़क पर जाम शुरू हो जाता है।

दिल्ली में पानी की समस्या होगी दूर, 2.15 लाख नए कनेक्शन देने की तैयारी

पश्चिमी-दक्षिणी दिल्ली में बदलेगी जलापूर्ति व्यवस्था, करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं पर भारी निवेश का प्रस्ताव है, जिससे पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। योजनाओं के तहत नए जल वितरण नेटवर्क, भूमिगत जलाशयों और घरेलू पानी के कनेक्शन का विस्तार किया जाएगा। वजीराबाद जल उपचार संयंत्र के कमांड क्षेत्र में एशियाई विकास बैंक की सहायता से 1,741 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

इनके तहत 43.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 836 किलोमीटर लंबा जल वितरण नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही सात भूमिगत जलाशयों का सुधार भी किया जाएगा। इससे जलापूर्ति व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने और लोगों तक पानी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत 2.15 लाख घरेलू जल कनेक्शन दिए जाएंगे और सभी कनेक्शनों पर मीटर लगाए जाएंगे। योजना का लक्ष्य लोगों को चौबीसों घंटे पर्याप्त दबाव के साथ पानी उपलब्ध कराना है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा गैर-राजस्व जल की मात्रा घटाकर 15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इससे पानी की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी।

पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली में जल ढांचे के व्यापक कायाकल्प के लिए 11,427 करोड़ रुपये के निवेश को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। दोनों परियोजनाएं करीब 363.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 20 भूमिगत जलाशय कमांड क्षेत्रों को कवर करेंगी। इनके पूरा होने के बाद पश्चिमी दिल्ली के 14.16 लाख और दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के 22.23 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 36 लाख से अधिक लोग इन योजनाओं से सीधे लाभान्वित होंगे।

शकूर बस्ती के हर्ष विहार में 55.21 करोड़ रुपये की लागत से 18 एमएलडी क्षमता का नया भूमिगत जलाशय बनाया जाएगा। वहीं ओखला के बाटला हाउस और अबुल फजल एन्क्लेव में 74 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में पानी का दबाव और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर करना है। जलापूर्ति सुधार के साथ उपचारित सीवेज के दोबारा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जा रहा है।

सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोर्ट का फैसला टला, 3 सितंबर को होगी सुनवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) टेंडर से जुड़े कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह अब तीन सितंबर को जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुनाएंगे। सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन स्वयं अदालत में मौजूद रहे। मामला दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आरोप लगाया है कि निविदा प्रक्रिया में तकनीकी शर्तों और मानकों में कथित तौर पर बदलाव किए गए, जिससे एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की स्थिति बनी। जांच एजेंसी के अनुसार, निविदा तैयार करने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण शर्तों और तकनीकी प्रावधानों को लेकर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच एजेंसी ने अदालत में सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे हैं। एजेंसी का कहना है कि मामले में कथित धन के लेनदेन और उससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों के बीच हुई बातचीत और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से निविदा प्रक्रिया को प्रभावित करने की कथित कोशिशों के संकेत मिले हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अदालत ने पिछले सप्ताह सत्येंद्र जैन समेत पांच आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन, करीब 200 मकानों को मिली आपूर्ति

एजेंसी, नई दिल्ली

गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों के निर्माण और विस्तार पर रोक लगाने के सरकारी दावों के बीच बिजली कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ओर प्रशासन और संबंधित विभाग अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन क्षेत्रों में बिजली का जाल फैलता जा रहा है। जानकारी के अनुसार, बदली हुई व्यवस्था के तहत पिछले वर्ष से अविकसित और अविद्युतीकृत कॉलोनियों में एक मकान होने पर भी बिजली कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत जिले में अब तक करीब 200 बिजली कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

इससे उन इलाकों में भी बिजली की सुविधा पहुंच रही है, जिन्हें अब तक अविकसित या अविद्युतीकृत क्षेत्र माना जाता रहा है। स्थानीय स्तर पर इस व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

सवाल उठ रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के निर्माण और विस्तार पर रोक है, तो वहां बने मकानों को बिजली कनेक्शन मिलने से क्या ऐसे निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि बिजली कनेक्शन मिलने के बाद इन इलाकों में नए निर्माण और आबादी बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। वहीं, बदली व्यवस्था के तहत एक मकान को भी कनेक्शन दिए जाने से बिजली विभाग की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। अधिकारियों की ओर से कनेक्शन देने के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, अवैध कॉलोनियों के विस्तार को रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाले विभागों और बिजली आपूर्ति व्यवस्था के बीच तालमेल को लेकर सवाल बने हुए हैं। करीब 200 कनेक्शन दिए जाने के बाद यह मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के अपने दावों के साथ बिजली कनेक्शन की इस व्यवस्था को किस तरह संतुलित करता है।

रक्षाबंधन पर दिल्ली-मेरठ यात्रियों को राहत, हर 8 मिनट में मिलेगी नमो भारत

एजेंसी, नई दिल्ली

रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की ओर से 27 और 28 अगस्त को कुल 47 अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं संचालित की जाएंगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है। अतिरिक्त ट्रिप्स शुरू होने के बाद नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों को हर आठ मिनट में ट्रेन उपलब्ध होगी। इससे स्टेशनों पर भीड़ कम करने और यात्रियों को कम समय तक ट्रेन का इंतजार कराने में मदद मिलेगी।

रक्षाबंधन पर नमो भारत की 47 अतिरिक्त ट्रेनें

रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन पर यात्रियों का दबाव सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए यह विशेष व्यवस्था की है। अधिकारियों के अनुसार, अतिरिक्त ट्रिप्स के जरिए त्योहार के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को व्यवस्थित तरीके से संभालने में मदद मिलेगी।

यात्रियों को अधिक विकल्प मिलने से यात्रा आसान होने की उम्मीद है। दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए संचालन व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अतिरिक्त सेवाओं से दिल्ली और मेरठ के बीच सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ न करें। त्योहार के दौरान अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी।

न्यूज ब्रीफ

पलवल में साइबर ठगी का नया तरीका, क्रेडिट कार्ड धारक से 1.80 लाख ठगे

एजेंसी ,नई दिल्ली पलवल में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जहां ठगों ने क्रेडिट कार्ड पर लगे अंतरराष्ट्रीय शुल्क हटाने और रिफंड दिलाने का झांसा देकर एक व्यक्ति के खाते से 1.80 लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित की शिकायत पर पलवल साइबर अपराध थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, साइबर ठगों ने पीड़ित से संपर्क कर उसके क्रेडिट कार्ड पर लगे अंतरराष्ट्रीय शुल्क हटाने की बात कही। ठगों ने उसे विश्वास में लेकर रिफंड दिलाने का भी झांसा दिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित के मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी। बताया जा रहा है कि इसके बाद ठगों ने उसे ईमेल के जरिए एक लिंक भी भेजा। पीड़ित ने ठगों की बातों पर भरोसा करते हुए उनके बताए तरीके का पालन किया। इसी दौरान साइबर ठगों ने उसके खाते से अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कुल 1.80 लाख रुपये निकाल लिए। खाते से रकम निकलने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित को ठगी का पता चला।इसके बाद उसने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी और साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई।

प्रयागराज में चीनी के दाम में 25 रुपये तक उछाल, रक्षाबंधन पर और महंगी होने का डर

एजेंसी, नई दिल्ली प्रयागराज में पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में करीब 25 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार में इस समय चीनी 68 से 80 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। अचानक बढ़े दामों से आम उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो रक्षाबंधन तक चीनी के दाम और बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने चीनी की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है। उनका कहना है कि जिले में चीनी का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने चीनी की कमी या दाम बढ़ने को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बताया गया कि तीन दिन पहले भी प्रशासन की ओर से चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होने की बात कही गई थी। इसके बावजूद बाजार में चीनी के दाम करीब पांच रुपये प्रति किलो और बढ़ गए। इससे प्रशासन के दावों और बाजार में वास्तविक कीमतों के बीच अंतर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अधिकारी जमाखोरी और कालाबाजारी पर नजर रखने की बात कह रहे हैं। प्रशासन ने संकेत दिया है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने या चीनी की जमाखोरी करने की पुष्टि होती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सितंबर में होगी डीएलएड परीक्षा, 68 जिलों में 4.86 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

एजेंसी, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की सितंबर में होने वाली परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरठ समेत प्रदेश के 68 जिलों में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में करीब 4.86 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरती जाएगी। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को परीक्षा केंद्र के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी परीक्षा केंद्र पर तंबू या कनात लगाकर परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित क्षमता के अनुसार पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था होना अनिवार्य होगा। केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय, पेयजल और बिजली की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए जनरेटर समेत अन्य आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

आगरा में 7.77 करोड़ की फर्जी आइटीसी का खेल, कारोबारी पर मुकदमा

एजेंसी, नई दिल्ली आगरा में बोगस फर्म से कागजी आपूर्ति दिखाकर 7.77 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में मैसर्स स्टार ट्रेडर्स के पवन सिंह नेगी के खिलाफ लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, अलीगढ़ की मैसर्स शिव ट्रेडिंग नामक फर्म से 43.16 करोड़ रुपये की आंतरिक आपूर्ति दिखाकर 7.77 करोड़ रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया। प्राप्त आइटीसी को बाह्य आपूर्ति की करदेयता में समायोजित कर लिया गया। एसजीएसटी विभाग की जांच में अलीगढ़ स्थित शिव ट्रेडिंग फर्म बोगस पाई गई। जांच के दौरान विभाग को संदेह हुआ कि फर्म के जरिए वास्तविक वस्तुओं की आपूर्ति किए बिना केवल कागजी बिलों के आधार पर लेनदेन दिखाया गया। इसी आधार पर आइटीसी के दावे और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। विभागीय जांच में अनियमितता सामने आने के बाद संबंधित कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है।

राष्ट्रगान अपमान के आरोप में सतीश महाना के खिलाफ 11 थानों में तहरीर

एजेंसी, नई दिल्ली अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए जिले के 11 थानों में तहरीर दी है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्नाव में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने के समय सतीश महाना वहां से जाते हुए दिखाई दिए। इसी घटना से जुड़े एक वीडियो को आधार बनाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की है। कांग्रेसियों का कहना है कि राष्ट्रगान देश की गरिमा और सम्मान से जुड़ा विषय है। उनके अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान निर्धारित मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अमरोहा जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दी गई तहरीर के बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वीडियो में दिखाई दे रही घटना राष्ट्रगान के सम्मान से जुड़े नियमों और भावनाओं के विपरीत है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, पूरे मामले में पुलिस की ओर से तहरीर के आधार पर जांच की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वीडियो की सत्यता, कार्यक्रम की परिस्थितियों और उसमें दिखाई दे रहे घटनाक्रम की भी जांच की जा सकती है।

महिला वकीलों ने उठाई आवाज, बार चुनाव में प्रमुख पदों पर आरक्षण की मांग

एजेंसी, नई दिल्ली

गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष और महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी आरक्षण लागू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में महिला वकीलों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया है। मामले में बुधवार को सुनवाई प्रस्तावित है। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि बार एसोसिएशन में आरक्षण की व्यवस्था केवल ऐसे पदों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, जिनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो।

उनका तर्क है कि यदि महिलाओं को वास्तव में नेतृत्व के समान अवसर देने हैं, तो अध्यक्ष, महासचिव और अन्य प्रमुख पदों को भी रोटेशनल आरक्षण व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण का उद्देश्य उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया और संगठन के शीर्ष नेतृत्व में उचित प्रतिनिधित्व देना है। केवल सीमित या कम प्रभाव वाले पदों पर आरक्षण देने से यह उद्देश्य पूरी तरह हासिल नहीं हो सकता।

महिला वकीलों ने अदालत से मांग की है कि आगामी जिला बार चुनावों में अध्यक्ष और महासचिव जैसे प्रमुख पदों पर भी महिला आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उनका कहना है कि इससे महिला अधिवक्ताओं को नेतृत्व करने और बार के प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की बुधवार को होने वाली सुनवाई पर हैं। अदालत के फैसले से गुरुग्राम बार चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व और आरक्षण की व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय हो सकती है। जिला बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं ने अध्यक्ष-महासचिव जैसे प्रमुख पदों पर आरक्षण की मांग की। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका पर बुधवार सुनवाई होगी।

बिजली निगम पर लापरवाही का आरोप, खंभे पर काम करते युवक की मौत

एजेंसी, नई दिल्ली

नूंह जिले के पुन्हाना क्षेत्र में बिजली निगम की कथित लापरवाही के कारण 22 वर्षीय युवक दिलशाद की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब वह बिजली के खंभे पर काम करने के लिए चढ़ा था। अचानक करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिलशाद की शादी करीब ढाई महीने पहले ही हुई थी। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार का कहना है कि बिजली निगम की लापरवाही के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। उनका आरोप है कि खंभे पर काम करते समय बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं की गई, जिसके चलते दिलशाद करंट की चपेट में आ गया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।

रेवाड़ी में मंत्री का सख्त रुख, लापरवाही पर एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई

एजेंसी, नई दिल्ली

रेवाड़ी के बाल भवन में सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर सिंह गंगवा ने की। बैठक में जिले से जुड़ी विभिन्न शिकायतों और जनसमस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीवर कार्य में लापरवाही का मामला सामने आने पर मंत्री ने नगर परिषद के एसडीओ को चार्जशीट करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में अधिकारी गंभीरता से काम करें।

बैठक के दौरान कुल 12 मामलों को रखा गया, जिनमें से पांच मामलों की जांच एसडीएम और एडीसी को सौंपने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए, ताकि शिकायतों का उचित समाधान हो सके। रणवीर सिंह गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शहर में पानी निकासी से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान अधिकारियों को अपने स्तर पर ही करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी शिकायतों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे मौके पर जाकर समस्याओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई करने और शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।

300 फीट नीचे गई एअर इंडिया की फ्लाइट, टर्बुलेंस की जांच में सामने आएंगे अहम तथ्य

फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे की जांच तेज, टर्बुलेंस की रिपोर्ट एक हफ्ते में

एजेंसी, नई दिल्ली

एअर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जा रही उड़ान में 4 अगस्त को हुई गंभीर टर्बुलेंस की घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इस घटना से जुड़ी प्रारंभिक रिपोर्ट करीब एक सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में विमान के अचानक नीचे जाने, उस समय की परिस्थितियों और यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों को लगी चोटों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार, एअर इंडिया की उड़ान एआई-2379 फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के दौरान विमान क्रूजिंग ऊंचाई पर था, तभी उसे अचानक तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा।

टर्बुलेंस के कारण विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट तक कम हो गई। इस अचानक हुए बदलाव से विमान के भीतर मौजूद यात्रियों और क्रू सदस्यों को झटका लगा। घटना में कुल 24 लोग घायल हुए। इनमें 20 यात्री और चार क्रू सदस्य शामिल हैं। हादसे के बाद विमान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। घटना के बाद विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और संबंधित एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक रिपोर्ट में जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्बुलेंस किस प्रकार का था और विमान के अचानक 300 फीट नीचे जाने के पीछे मुख्य कारण क्या रहा।

इसके साथ ही उड़ान के दौरान मौसम की स्थिति, विमान की ऊंचाई, गति, पायलटों की कार्रवाई और उस समय विमान में सीट बेल्ट से जुड़े निर्देशों का भी अध्ययन किया जा सकता है। जांच के दौरान विमान के तकनीकी रिकॉर्ड और उड़ान से संबंधित आंकड़ों की भी समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञ यह भी देखेंगे कि घटना के समय विमान के सिस्टम ने किस तरह प्रतिक्रिया दी और पायलटों ने स्थिति को संभालने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए। टर्बुलेंस विमानन क्षेत्र में आम घटना है, लेकिन तेज टर्बुलेंस कभी-कभी यात्रियों और चालक दल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

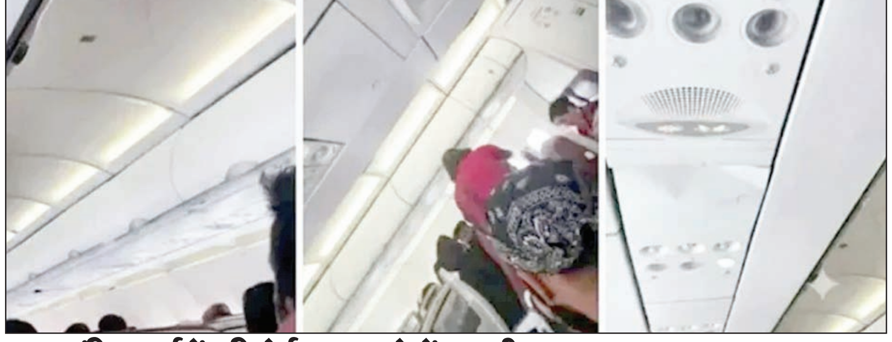

एअर इंडिया टर्बुलेंस रिपोर्ट एक हफ्ते में आएगी

खासतौर पर जब यात्री सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं, तब अचानक विमान के ऊपर-नीचे होने से चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है। एअर इंडिया की इस उड़ान की घटना ने एक बार फिर उड़ान के दौरान सीट बेल्ट बांधे रखने और चालक दल के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के महत्व को सामने ला दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद घटना की परिस्थितियों को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है। हालांकि, रिपोर्ट आने तक टर्बुलेंस के सटीक कारण को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विमानन अधिकारियों की ओर से भी घटना की निगरानी की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद यदि किसी अतिरिक्त जांच या कार्रवाई की जरूरत महसूस होती है, तो संबंधित एजेंसियां आगे के कदम उठा सकती हैं। फिलहाल सभी की नजरें रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि फुकेट-दिल्ली उड़ान के दौरान आखिर विमान अचानक 300 फीट नीचे क्यों गया और इस घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या थी।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचीं शिल्पा शेट्टी, वायरल हुआ वीडियो

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिल्पा शेट्टी एयरपोर्ट के टर्मिनल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों ने अभिनेत्री को देखते ही अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। जानकारी के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी बीते शनिवार को मुंबई से विमान के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची थीं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वह सड़क मार्ग से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गईं। इस दौरान उन्हें देखने के लिए आसपास मौजूद लोगों में उत्सुकता दिखाई दी। गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई समेत 15 शहरों के लिए उड़ानें संचालित हो रही हैं। एयरपोर्ट का संचालन शुरू हुए दो महीने से अधिक समय हो चुका है। इसके शुभारंभ के दिन भी एक अभिनेत्री ने लखनऊ से जेवर तक विमान से यात्रा की थी।

हिमाचल में 18 सरकारी विभागों में नहीं लग रही बायोमेट्रिक हाजिरी

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। सरकार के अनुसार इसके पीछे फील्ड कर्मचारियों की ड्यूटी का स्वरूप, दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट और नेटवर्क की कमी, बिजली की समस्या तथा कई कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध नहीं होना प्रमुख कारण हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के लिखित जवाब में मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 विभागों के तहत आने वाले बोर्डों, निगमों के कार्यालयों और संस्थानों में कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं लग रही है। इनमें निर्वाचन विभाग, कृषि, गृह, उद्यान, आवास, जल शक्ति, भाषा एवं कला संस्कृति, लोक निर्माण, सैनिक कल्याण, पर्यटन, जनजातीय विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वित्त, वन, सामान्य प्रशासन, आयुष, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।

पुलिस व अग्निशमन के फील्ड स्टाफ के लिए अलग स्थिति

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में फील्ड स्टाफ के पुलिस कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन और ऑनलाइन माध्यम से नहीं लग रही है। वहीं कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन और ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा रही है। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग और अग्निशमन सेवाएं विभाग के फील्ड स्टाफ 24 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। उन्हें किसी भी समय हादसे की जगह पर तत्काल पहुंचना पड़ सकता है। ऐसे में इन कर्मचारियों को निर्धारित कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित रहकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना संभव नहीं होता। सरकार ने इसे फील्ड स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने में व्यवहारिक समस्या बताया है। जिलों के थानों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार इन थानों में अभी तक बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं की गई हैं।

जहां मशीन लगी, वहां फील्ड स्टाफ भी लगा रहा हाजिरी

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित कर दी गई हैं, वहां तैनात फील्ड स्टाफ भी बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से हाजिरी लगा रहा है। कृषि विभाग के कृषि विकास और प्रसार केंद्र अनुभागों में बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इसका कारण बताया कि प्रत्येक अनुभाग में केवल एक या दो अधिकारी या कर्मचारी ही कार्यरत हैं। भाषा एवं कला संस्कृति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक आधार पर लगाई जा रही है। केवल जिला भाषा अधिकारी कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांगपिओ में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लग रही है।

फील्ड कर्मचारियों के लिए एक जगह हाजिरी लगाना मुश्किल

सरकार ने बताया कि जल शक्ति विभाग के फील्ड कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से दर्ज नहीं की जा रही है। इसका कारण यह है कि बायोमेट्रिक मशीन सामान्य तौर पर किसी एक निश्चित स्थान पर लगाई जाती है, जबकि फील्ड कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र अलग-अलग स्थानों पर होता है। ऐसे कर्मचारियों के लिए फिलहाल बायोमेट्रिक या ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने की कोई व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है। इनकी उपस्थिति विभागीय नियमों के अनुसार उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा, वन, पशुपालन, गृह, उद्यान, लोक निर्माण, पर्यटन, परिवहन, युवा सेवाएं एवं खेल, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, वित्त, ग्रामीण विकास और राजस्व सहित कई विभागों में फील्ड स्टाफ की बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लग रही है। इन विभागों में फील्ड कर्मचारियों के सामने अलग-अलग तरह की दिक्कतें हैं। कई जगह फील्ड में तैनात कर्मचारी के लिए कार्यालय पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना व्यवहारिक नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं होने, कनेक्टिविटी की कमी तथा तकनीकी समस्याओं के कारण भी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती।

हाईकोर्ट द्वारा सभी विभागों में व्यवस्था अनिवार्य करने के आदेश

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के पारित आदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने के लिए 18 नवंबर 2022 को आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी की ओर से सामान्य कार्यालय समय के अतिरिक्त, यानी कार्यालय समय शुरू होने से पहले या समाप्त होने के बाद ड्यूटी करने के लिए विधिवत निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी वास्तविक अतिरिक्त ड्यूटी के बदले नियमानुसार प्रतिपूरक अवकाश देने का प्रावधान है।

कई कार्यालयों में मशीन ही नहीं लगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारी विभाग के जिला कार्यालयों के तहत आने वाले विभिन्न विकास खंड स्तर के कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं की गई हैं। ऐसे कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी उपस्थिति पंजिका में दर्ज की जाती है। मत्स्य विभाग के कुछ अधीनस्थ जिला स्तरीय और मंडलीय कार्यालयों तथा मत्स्य फार्मों में भी बायोमेट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं। इस कारण वहां कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी बायोमेट्रिक माध्यम से दर्ज नहीं हो रही है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग के पांगी और काजा स्थित कार्यालयों में इंटरनेट और बिजली की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण कर्मचारियों की दैनिक हाजिरी आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से सुचारू रूप से दर्ज नहीं हो पा रही है।

राष्ट्रगीत के अपमान का झूठा आरोप लगाकर मुख्यमंत्री ने सदन व प्रदेश की जनता को किया गुमराह : परमार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने राष्ट्रगीत को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विपक्ष पर लगाए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा और प्रदेश की जनता के सामने गलत तथ्य रखे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है, इसलिए मुख्यमंत्री को विपक्ष से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। परमार ने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राष्ट्रगान होने पर विपक्ष के सभी विधायक सम्मानपूर्वक खड़े हुए थे। इसके बाद विपक्ष ने नियमों और हाल में जारी प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए राष्ट्रगीत को भी सम्मान के साथ गाए जाने की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान की बात करना किसी भी तरह गलत नहीं है।

उन्होंने दावा किया कि 15 अगस्त को देश और प्रदेश में राष्ट्रगीत पूरे सम्मान के साथ गाया गया। ऐसे में विधायकों पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप निराधार है। वीडियो से भी यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष ने किसी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान नहीं किया। परमार ने कहा कि विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखी और उनके निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सदन में खड़े होकर विपक्षी विधायकों पर लगाए आरोपों के लिए माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान प्रत्येक भारतीय का दायित्व है। संविधान और संवैधानिक परंपराएं किसी भी राजनीतिक दल के निर्णय से ऊपर हैं।

न्यूज ब्रीफ

10 साल से खैर कटान की अनुमति नहीं, ग्रामीणों में रोष

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 वर्षों से खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति न मिलने से ग्रामीणों में रोष बढ़ता जा रहा है। लोगों के अनुसार सलोआ, बड़ोह और कोट बीट में करीब 11 वर्ष पहले खैर कटान हुआ था। इसके बाद निर्धारित अवधि में दोबारा कटान की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खैर उनके लिए जंगल की संपदा ही नहीं, बल्कि आय का महत्वपूर्ण साधन भी है। खैर से होने वाली आमदनी से परिवार बच्चों की पढ़ाई, शादी-ब्याह, मकान निर्माण और उपचार जैसी जरूरतें पूरी करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार भारी बारिश के कारण मलकीयत भूमि में खड़े कई खैर के पेड़ सूख रहे हैं। समय पर कटान की अनुमति न मिलने से उनकी आर्थिक उपयोगिता प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांग सरकारी वन भूमि से पेड़ काटने की नहीं, बल्कि मलकीयत भूमि में खड़े खैर के पेड़ों के नियमानुसार कटान और बिक्री की अनुमति देने की है। उन्होंने सरकार और वन विभाग से जल्द निर्णय लेने की मांग की।

गैस आपूर्ति एजेंसियां लोगों के घरों तक गैस का आवंटन करें सुनिश्चित : डॉ. अंजलि गर्ग

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। एसडीएम कांगड़ा डॉ. अंजलि गर्ग ने कांगड़ा में गैस की सप्लाई करने वाली समस्त एजेंसियों को यह निर्देश जारी किए हैं कि लोगों के घर द्वार गैस का आवंटन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा गैस एजेंसियों के कार्य बारे निरंतर शिकायतें मिल रही हैं अधिकतर गैस एजेंसियां गैस आवंटन के लिए लोगों के घर तक छोटे वाहनों का प्रयोग ना करके बड़े वाहनों से आवंटन कार्य कर रही हैं, जिसके कारण उनके बड़े वाहन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं परिणाम स्वरूप लोगों को नियम के अनुसार घर द्वार गैस का आबंटन नहीं हो पा रहा। एसडीएम कांगड़ा ने सभी गैस एजेंसियों को इस कार्य को गंभीरता से लेने और गैस के आवंटन के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग करके लोगों के घर द्वार गैस का आवंटन करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा यदि इन निर्देशों की कोई अवहेलना करता है और नियमों के अनुसार गैस का आवंटन नहीं करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मारपीट के आरोप में सीआईएसएफ जवान का तबादला, एफआईआर की मांग पर धरना समाप्त

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पंडोह बांध की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवान और पार्टटाइम वर्कर के बीच कथित मारपीट के मामले में मंगलवार को बीबीएमबी कार्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पार्टटाइम वर्करों ने आरोपी जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वर्कर्स का कहना था कि एक दिन पहले दोनों पक्षों की आमने-सामने वार्ता करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन मंगलवार को उन्हें वार्ता के बजाय आरोपी जवान के तबादले की जानकारी दी गई। अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता चंद्रमणि शर्मा ने बताया कि जवान का तबादला कर कार्रवाई की जा चुकी है और वर्करों से काम पर लौटने को कहा गया। इस पर वर्करों ने विरोध जताते हुए कहा कि केवल तबादले से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कार्यालय परिसर में माहौल गर्मा गया। बाद में मामले को शांत करने के लिए अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने उपमंडल अधिकारी टाउनशिप को पंडोह पुलिस चौकी में आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के मौखिक निर्देश दिए। इसके बाद वर्करों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। आरोपी जवान का तबादला भी कर दिया गया है।

बिलासपुर के कई क्षेत्रों में आज 5 घंटे बंद रहेगी बिजली

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिजली उपमंडल-2 के सहायक अभियंता ई. रविंद्र चौधरी ने बताया कि 26 अगस्त को रौड़ा अनुभाग के अंतर्गत आवश्यक बिजली लाइनों की मरम्मत, पेड़ों की कटाई-छंटाई तथा जीओ स्विच के पार्ट बदलने का कार्य किया जाएगा। इसके चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि रौड़ा अनुभाग के अंतर्गत दनोह, एचआरटीसी कॉलोनी, रौड़ा सेक्टर-3 के कुछ स्थानों तथा आसपास के क्षेत्रों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि निर्धारित समय के दौरान विभाग के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मरम्मत और रखरखाव कार्य आवश्यक हैं, ताकि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें। मौसम अथवा तकनीकी कारणों से कार्य की अवधि में बदलाव संभव है।

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 117 उम्मीदवारों का चयन

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए पोस्ट कोड-26032 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इन पदों के लिए कुल 2581 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2021 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी थी और इस परीक्षा में 293 उम्मीदवारों का चयन दस्तावेजों की जांच के लिए किया गया था। 13 और 17 अगस्त को दस्तावेजों की जांच के बाद 117 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद खाली रह गया है।

35 लीटर कच्ची शराब और 12 बोतलें बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी और घरेलू हिंसा के मामलों में कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थानों में तीन मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने दो आरोपियों के कब्जे से 35 लीटर कच्ची शराब और 12 बोतल अवैध देसी शराब बरामद की है। पुलिस थाना कोट कहलूर की टीम ने गश्त के दौरान घड़ौवाल में दबिश देकर तरसेम लाल के कब्जे से 35 लीटर अवैध शराब बरामद की। वहीं, सदर बिलासपुर पुलिस ने धमणा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सिहड़ा निवासी दीपक राज से 12 बोतल अवैध देसी शराब जब्त की। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एक अन्य मामले में घुमारवीं पुलिस ने चलैहली निवासी सोनिया की शिकायत पर उसके पति अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पत्नी और बेटी से मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर ने मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी मामलों में नियमानुसार आगामी जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

लोक सेवा आयोग का परीक्षा शुल्क कम नहीं करेगी सरकार, पहले 400 व अब 600 रुपए परीक्षा शुल्क

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग की ओर से लिए जा रहे परीक्षा शुल्क को कम करने का फिलहाल कोई विचार नहीं किया है।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 मार्च 2024 को पहले लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क में बदलाव किया था। इसके तहत परीक्षा शुल्क 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया था। इसके बाद 31 मार्च 2026 को प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग की तर्ज पर लोक सेवा आयोग को परीक्षा शुल्क की संरचना तय करने के लिए अधिकृत किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समय अभ्यर्थियों से सामान्य श्रेणी के लिए 360 रुपए और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से 120 रुपए परीक्षा शुल्क लिया जाता था। उस समय परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में पेपर और पेन के माध्यम से करवाई जाती थीं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 14 मई 2025 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को परीक्षाओं के संचालन से जुड़े प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए परीक्षा शुल्क की संरचना तय करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद परीक्षा शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया। इसके अलावा कंप्यूटर आधारित परीक्षा करवाने के लिए चयनित एजेंसी पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए 700 रुपए प्रसंस्करण शुल्क निर्धारित किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित माध्यम से करवाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का लोक सेवा आयोग के मौजूदा परीक्षा शुल्क को कम करने का कोई विचार नहीं है।

लारजी में आपदा से 54 पेयजल व सिंचाई योजनाएं क्षतिग्रस्त

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्राकृतिक आपदा के कारण जलशक्ति मंडल लारजी के तहत वर्ष 2023 और 2025 में कुल 54 उठाऊ पेयजल और सिंचाई योजनाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। इन योजनाओं को हुए नुकसान का अनुमान 2350.97 लाख रुपए लगाया गया है। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के आपदा से जलशक्ति मंडल लारजी में क्षतिग्रस्त योजनाओं से संबंधित सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में प्राकृतिक आपदा के दौरान जलशक्ति मंडल लारजी के तहत 23 उठाऊ पेयजल योजनाएं और 14 उठाऊ सिंचाई योजनाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थीं। वर्ष 2025 में 17 उठाऊ पेयजल योजनाएं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुईं। इस दौरान कोई भी उठाऊ सिंचाई योजना क्षतिग्रस्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इन क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत, पुनर्बहाली और पुनर्निर्माण के लिए 718.67 लाख रुपए की धनराशि मंजूर कर जारी की गई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में जलशक्ति मंडल लारजी में कोई नई उठाऊ पेयजल योजना और सिंचाई योजना मंजूर नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पांच उठाऊ पेयजल योजनाओं का काम प्रगति पर है। इन योजनाओं पर 4259.58 लाख रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है।

रोहड़ू सीवरेज प्लांट का नहीं होगा स्थानांतरण, क्षमता बढ़ाने की तैयारी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। रोहड़ू नगर परिषद में मौजूदा सीवरेज प्लांट का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। रोहड़ू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा के सवाल के लिखित जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में रोहड़ू नगर परिषद में 1.745 एमएलडी क्षमता का सीवरेज प्लांट काम कर रहा है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे वित्त पोषण के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सीवरेज प्लांट के स्थानांतरण का कोई विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से 1,400 घरों को सीवरेज कनेक्शन देने का प्रावधान था। इन सभी घरों को पूरी तरह जोड़ लिया गया है। एसटीपी अपनी प्रस्तावित क्षमता के अनुसार काम कर रहा है। प्लांट को अपग्रेड किए बिना इसमें अतिरिक्त कनेक्शन जोड़ना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के तहत चिड़गांव नगर पंचायत में सीवरेज योजना बनाई जानी प्रस्तावित है। विभाग ने इस योजना के लिए 51.02 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार कर इसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत स्वीकृति के लिए भेजा था। उन्होंने बताया कि यह प्राक्कलन कुछ आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया। आपत्ति यह थी कि प्राक्कलन वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत तैयार किया गया था। उस समय पब्बर नदी प्राथमिकता प्राप्त नदी खंड के रूप में सूची में थी। उपमुख्यमंत्री के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2025 की आकलन रिपोर्ट में पब्बर नदी को प्राथमिकता प्राप्त नदी खंड की सूची से बाहर कर दिया गया है। अब चिड़गांव की सीवरेज योजना की डीपीआर को किसी अन्य मद के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। इसके अनुसार डीपीआर में संशोधन कर उसे दोबारा प्रस्तुत किया जाएगा।

एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के स्टूडेंट्स ने एमएससी फिजिक्स में लहराया परचम

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा एमएससी फिजिक्स चौथे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा का परिणाम बेहद शानदार रहा। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेरिट में शीर्ष तीन स्थानों पर कब्जा जमाया। परीक्षा में स्नेहा ने 8.44 सीजीपीए अंक हासिल कर कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया और ओवरऑल टॉपर बनीं। वहीं मुस्कान ने 8.42 सीजीपीए के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। शाइनी चौधरी ने 8.22 सीजीपीए अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। छात्राओं की इस उपलब्धि से कॉलेज परिसर सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। छात्राओं की इस शानदार उपलब्धि पर एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने खुशी व्यक्त करते हुए तीनों छात्राओं को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्राओं के अभिभावकों तथा भौतिक विज्ञान विभाग के सभी प्राध्यापकों को भी इस सफलता के लिए बधाई दी। डॉ. पटियाल ने कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि कॉलेज की ये होनहार छात्राएं उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में आगे बढ़कर भविष्य में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी और देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

कल पंजाब महाबंद के लिए पठानकोट में तैयारियां पूरी

लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी-पेंशनर्स हुए लामबंद, डीसी को सौंपा मांग-पत्र

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पंजाब के मुलाजिमों और पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर 27 अगस्त को प्रस्तावित पंजाब महाबंद को सफल बनाने के लिए पठानकोट में तैयारियां तेज हो गई हैं।

विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने महाबंद को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में पीएसएमएसयू, सांझा फ्रंट और सांझी तालमेल कमेटी की आपात बैठक डीएसी कॉम्प्लेक्स मलिकपुर के मीटिंग हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता पीएसएमएसयू पठानकोट के प्रधान विशालवीर सिंह, स्टेट पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट के नरेश कुमार, पुलिस पेंशनर गुरदियाल सिंह सैनी, महासचिव हितेश शर्मा और चेयरमैन गुरनाम सिंह ने की। बैठक में महाबंद को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार कर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गईं। कर्मचारियों को 27 अगस्त की सामूहिक छुट्टी के लिए फार्म भी वितरित किए गए। जत्थेबंदियों ने कहा कि महाबंद के दौरान स्कूलों, कॉलेजों, एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, राजस्व विभाग, पटवार केंद्रों, सरकारी अस्पतालों, लोक निर्माण विभाग और डीएसी सहित अन्य सरकारी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहेगा।

बैठक के बाद कर्मचारी-पेंशनर प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त पठानकोट पल्लवी को मांग-पत्र सौंपा। इसमें लंबे समय से लंबित मांगों का जल्द समाधान करने की मांग की गई। इसके बाद पंजाब सरकार का पुतला फूंककर जोरदार प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। पीएसएमएसयू प्रधान विशालवीर सिंह ने कहा कि 27 अगस्त का महाबंद सरकार के लिए स्पष्ट चेतावनी होगा। यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पेंशनरों से सामूहिक छुट्टी लेकर महाबंद को सफल बनाने की अपील की। 27 अगस्त के पंजाब महाबंद के लिए पठानकोट में तैयारियां पूरीइस अवसर पर विभिन्न कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर और अन्य संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

पठानकोट में हाई-वोल्टेज बिजली पोल पर चढ़े 2 बुजुर्ग

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट में दो बुजुर्ग हाई वोल्टेज बिजली के 200 फुट ऊंचे पोल पर चढ़ गए। बैराज विस्थापितों ने लिफाफे में मांगपत्र टावर से नीचे फेंका। इसमें शाहपुरकंडी बैराज प्रोजेक्ट में 32 कर्मचारियों की नियुक्ति और बाद में उनकी बहाली का मामला उठाया गया है। बुजुर्गों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर फैसला नहीं लिया जाता, वे नीचे नहीं उतरेंगे। डैम बैराज औसती संघर्ष कमेटी जैनी जुगियाल के सदस्य कुलविंदर सिंह (81) और शर्म सिंह (85) पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश के पास स्थित बिजली के खंभे पर जाकर बैठ गए। संघर्ष कमेटी के सदस्यों का कहना है कि हर बार प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बाद में उनकी मांगों का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। मांग पत्र के अनुसार, अधीक्षण अभियंता अमृतसर जगदीश राज, जिन्हें शाहपुरकंडी बैराज प्रोजेक्ट का नोडल अधिकारी बनाया गया था, उन्होंने मामले की जांच की थी। जांच में 32 कर्मचारियों को कथित तौर पर गलत तरीके से नौकरी हासिल करने का दोषी पाया गया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इसके बाद अरविंद कुमार ने दोबारा जांच की, जिसमें बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया गया। मांग पत्र में इस बहाली में चीफ इंजीनियर शेर सिंह की कथित मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन; दो माह का अल्टीमेटम, नीति बनाने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बीच मंगलवार को विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे कर्मचारी बारिश के बीच छाते लेकर प्रदर्शन में डटे रहे। कर्मचारियों ने सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, नौकरी की सुरक्षा देने और कम मानदेय की समस्या दूर करने की मांग उठाई।

प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना था कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 25 हजार कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कई कर्मचारी 15 से 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इतने लंबे समय तक सरकारी विभागों में सेवाएं देने के बाद भी उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जब चाहे उन्हें नौकरी से बाहर कर सकती है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के संयोजक अश्वनी शर्मा ने कहा कि अधिकांश आउटसोर्स कर्मचारियों को करीब 12 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। मौजूदा महंगाई में इतनी कम आय में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कम मानदेय और नौकरी की असुरक्षा के कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनी हुई है। अश्वनी शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी पिछले करीब एक दशक से अपने लिए स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी कर्मचारियों ने नीति की मांग को लेकर लंबा आंदोलन किया था, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। अब मौजूदा सरकार के सामने भी कर्मचारियों ने यही मांग रखी है। चौड़ा मैदान में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए दो महीने का अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों ने कहा कि इस अवधि में उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो आउटसोर्स कर्मचारी संघ आंदोलन शुरू करेगा। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि वे अपने भविष्य की सुरक्षा और नीति की मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। अश्वनी शर्मा ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शोषित वर्ग के लिए अच्छे फैसले ले रहे हैं और इसी वजह से आउटसोर्स कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि सरकार उनके लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का समाधान करेगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द नीति बनाने और उनकी नौकरी व भविष्य को सुरक्षित करने की मांग दोहराई।

सिरमौर में 7.54 ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर पुलिस की एस आई यू टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबन के समीप एक युवक को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया कि एसआईयू की टीम गश्त पर राजबन के समीप मौजूद थी। इसी दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल में चिट्टा छिपाकर ले जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में पुलिस थाना पुरुवाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान पियुष ठाकुर निवासी सतौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। एसपी सिरमौर ने बताया कि मामले में आगामी जांच जारी है। जांच के दौरान नशे की खेप के स्रोत और इसकी सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।

रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती को दें बढ़ावा : डीसी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। डीसी अपूर्व देवगन ने कृषि में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने तथा प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों के बारे में जागरूक कर अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए।

वे धरती माता बचाओ निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में चिन्हित 100 ग्राम पंचायतों पर विशेष फोकस किया जाए। इन पंचायतों में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं कम उपयोग तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि जो प्रगतिशील किसान पहले से ही प्राकृतिक अथवा जैविक खेती कर रहे हैं, उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया जाना चाहिए, ताकि उनके सफल अनुभवों को अन्य किसानों तक पहुंचाया जा सके। इससे अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित होंगे और धरती की उर्वरा शक्ति तथा पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। डीसी ने परियोजना निदेशक (आत्मा) तथा कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चिन्हित पंचायतों में किसानों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों में प्राकृतिक खेती की तकनीकों, जैविक खाद के उपयोग, मृदा स्वास्थ्य तथा रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने भी महत्वपूर्ण सुझाव रखे। कृषि उपनिदेशक राम चंद्र चौधरी ने जिला में अभियान के तहत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में जिला कृषि अधिकारी गोपाल चंद, सोनल गुप्ता, डीपीडी आत्मा, ओम चंद वर्मा, जिला अंकेक्षक अधिकारी, इफको के एरिया मैनेजर रोहित ग्लोटिया सहित धरती माता बचाओ निगरानी समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

1.78 करोड़ से 24,162 करोड़ लेन देन तक पहुंचा यूपीआई : अनुराग

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र में आई क्रांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा की।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में यूपीआई ने भारत की तकनीकी क्षमता, नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने यूपीआई की शुरुआत की 10वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि एक दशक पहले शुरू हुआ यह स्वदेशी डिजिटल भुगतान माध्यम आज दुनिया के प्रमुख फिनटेक नवाचारों में शामिल हो चुका है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीआई ने करोड़ों भारतीयों के दैनिक जीवन को आसान बनाने के साथ भारत को वैश्विक फिनटेक क्षेत्र में अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यह आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम भारत का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यूपीआई की सफलता इसके आंकड़ों से स्पष्ट होती है। वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के माध्यम से 1.78 करोड़ लेन-देन हुए थे, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर करीब 24,162 करोड़ हो गए। इसी अवधि में लेन-देन का कुल मूल्य लगभग 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 314 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह वृद्धि डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों और व्यापारिक समुदाय के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यूपीआई की सफलता भारत तक सीमित नहीं रही। यह व्यवस्था अब 11 देशों में संचालित हो रही है। वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती स्वीकार्यता भारत की मजबूत डिजिटल आधारभूत संरचना और तकनीकी क्षमता का प्रमाण है। ठाकुर ने कहा कि यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत को दुनिया के सामने एक सफल और आत्मनिर्भर मॉडल प्रस्तुत किया है।

पीरनिगाह के पास हरियाणा के श्रद्धालुओं से भरा ट्रक खाई में गिरा, 45 घायल

तीन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर, मां नयना देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालु

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। पीरनिगाह मंदिर के पास मंगलवार सुबह श्रद्धालुओं से भरा 16 टायर वाला ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में करीब 45 श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। इनमें तीन श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र से 50 से अधिक श्रद्धालुओं का जत्था करीब तीन दिन पहले पीरनिगाह पहुंचा था। श्रद्धालुओं ने यहां मंदिर में दर्शन किए और भंडारे का आयोजन भी किया। मंगलवार सुबह पीरनिगाह में माथा टेकने के बाद श्रद्धालु मां नयना देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। पीरनिगाह मंदिर से करीब दो किलोमीटर आगे उतराई वाले हिस्से में पहुंचते ही ट्रक चालक अचानक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते ट्रक सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। वाहन के खाई में गिरते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और श्रद्धालुओं की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने का काम शुरू किया।

पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। इनमें करीब 45 लोगों को चोटें आई हैं, जबकि चार-पांच श्रद्धालुओं को चोट नहीं लगी। सभी घायल हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

चालक के नियंत्रण खोने की आशंका

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू की। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। इसके साथ ही घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसा उतराई में चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ बताया जा रहा है। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

राष्ट्रीय मंच पर चमके घुमारवीं कॉलेज के एनएसएस स्वयंसेवक, प्राचार्य ने दी बधाई

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के एनएसएस स्वयंसेवकों ने अगस्त 2026 में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया।

4 से 7 अगस्त तक स्वयंसेवक निखिल और आरती बंसल ने देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के साथ 'नेतृत्व एवं व्यक्तित्व विकास' प्रशिक्षण में भाग लिया। वहीं, 17 से 20 अगस्त तक दो अन्य स्वयंसेवकों ने 'युवा रोजगार कौशल क्षमता निर्माण' कार्यक्रम के तहत ग्रुप डिस्कशन और व्यावहारिक अभ्यासों के माध्यम से अपने कौशल एवं पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाया। इसके अलावा, 18 अगस्त को स्वयंसेवकों ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत नारा लेखन और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर समाज को नशामुक्त बनाने का संदेश दिया। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर के मंच पर विद्यार्थियों का अनुशासन और प्रदर्शन गर्व का विषय है। ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, संचार कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी प्रो. रमेश चंद और प्रो. पूजा ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और कार्यशैली को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी समाजसेवा और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद जताई।

न्यूज ब्रीफ

बिलासपुर कला मंच की बैठक में आय-व्यय की समीक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला मुख्यालय में भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में बिलासपुर कला मंच की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर के संचालन, व्यवस्थाओं और पिछले वर्षों के आय-व्यय की समीक्षा की गई। परिसर को सुविधाजनक बनाने और आय-सृजन का प्रभावी केंद्र बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में डॉरमेट्री में बेहतर साफ-सफाई, स्थायी जलापूर्ति के लिए बोरवेल तथा बिजली खर्च कम करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं मजबूत करने और आवश्यक कार्य प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सरकार ने परिसर के संचालन के लिए 40 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने विभिन्न वर्षों की आय-व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने सरकारी और निजी संस्थाओं के कार्यक्रमों के लिए समान शुल्क व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ-सफाई, नियमित रखरखाव और आय बढ़ाने के नए अवसर तलाशने पर भी जोर दिया।

घुमारवीं कॉलेज में शुरू हुआ संभाषण शिविर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में संस्कृत सप्ताह के तहत दस दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में प्रो. शक्ति, प्रो. वासुदेव, संस्कृत विभाग की प्राध्यापिका डॉ. अंजना कुमारी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। संस्कृत भारती के सहयोग से आयोजित शिविर का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का व्यावहारिक ज्ञान देना और इसे दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित करना है। शिविर का संचालन श्री सरोज शास्त्री कर रहे हैं। डंगार महाविद्यालय से आए छात्र-छात्राएं भी विभिन्न गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। उद्घाटन अवसर पर प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने कहा कि संस्कृत ज्ञान और भारतीय परंपरा की समृद्ध भाषा है। विद्यार्थियों को इसे रुचिपूर्वक सीखकर अन्य लोगों को भी इससे जोड़ना चाहिए। डॉ. अंजना कुमारी ने संस्कृत को भारतीय ज्ञान एवं सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण आधार बताया। शिविर में 50 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। आगामी दस दिनों तक उन्हें सरल एवं व्यावहारिक संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

'अपना परिवार सुखी परिवार' योजना के नौवें चरण में छूटे परिवारों को एक और मौका

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल सरकार की 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के नौवें चरण में पात्र और पूर्व चरणों में छूटे परिवारों को योजना का लाभ लेने का एक और अवसर दिया गया है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने सभी विकास खंड अधिकारियों को आवेदन, चयन और सत्यापन प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि नौवें चरण में पात्रता के मानदंड पूर्ववत रहेंगे। पात्र परिवारों की सुविधा के लिए 31 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की अवधि के आय प्रमाण-पत्र भी मान्य होंगे। पात्र परिवार अपने आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय या उपमंडलाधिकारी (नागरिक) कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया 20 सितंबर 2026 तक पूरी की जाए। इसके बाद अंतिम सूची समयबद्ध रूप से जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाई जाए और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पात्र परिवारों से समय पर आवेदन करने की अपील की।

20 अगस्त के लाठीचार्ज पर प्रशासन से मांगा जवाब

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। अभाविप जिला संयोजक करण ठाकुर ने पुलिस प्रशासन पर कथित दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए 20 अगस्त को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि परिषद के कार्यकर्ता छात्र हितों की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। करण ठाकुर ने कहा कि करीब दो महीने पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किए जाने पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान सख्ती और पुतला दहन के मामलों में नरमी क्यों बरती गई। उन्होंने प्रशासन से कानून-व्यवस्था के मामलों में सभी के साथ समान व्यवहार करने की मांग की। एबीवीपी जिला संयोजक ने कहा कि प्रशासन 20 अगस्त की पुलिस कार्रवाई पर स्थिति स्पष्ट करे और भविष्य में शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग न करने को सुनिश्चित करे।

युवाओं की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा भाजयुमो

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मंडी में प्रदर्शन कर युवाओं से किए गए रोजगार संबंधी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां देने सहित रोजगार की कई गारंटियां दी थीं, लेकिन सरकार इन वादों को पूरा करने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष योगराज डोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादों और गारंटियों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की जनता और युवा वर्ग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा युवाओं के हितों की आवाज लगातार उठाता रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में भी संगठन सरकार के खिलाफ विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन जारी रखेगा।

सिकंदर ने गडकरी से की नादौन-होशियारपुर व कोहली-भगेड़ फोरलेन के निर्माण की अपील

हिमाचल के हाईवे प्रोजेक्ट्स को रफ्तार देने की मांग

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राज्यसभा सांसद व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. (डॉ.) सिकंदर कुमार ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र एवं इसके सीमावर्ती इलाकों में लंबित दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जनहित और क्षेत्र के आर्थिक-सामाजिक विकास को गति देने के लिए नादौन-होशियारपुर और कोहली-भगेड़ फोरलेन खंड की औपचारिकताओं को जल्द पूरा कर धरातल पर निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आग्रह किया है।

सांसद द्वारा केंद्रीय मंत्री से पत्र के माध्यम से आग्रह किया गया कि नादौन से पंजाब बॉर्डर (होशियारपुर) राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी की एलाइनमेंट लगभग तय हो चुकी है। करीब तीन माह पूर्व नादौन के समीप दर्ज आपत्तियों का निवारण कर संशोधित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित की जा चुकी है। उस समय 15 दिनों के भीतर एलाइनमेंट को अंतिम स्वीकृति देने का आश्वासन मिला था, लेकिन वर्तमान में यह फाइल मंत्रालय में लंबित है और आधिकारिक पोर्टल पर भी इसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है।

इससे संबंधित मंत्री महोदय के माध्यम से अधिकारियों को त्वरित स्वीकृति प्रदान करने और पोर्टल अद्यतन करने के निर्देश देने की मांग की है लगभग 40 किलोमीटर का यह हिस्सा हमीरपुर क्षेत्र की जीवन रेखा है। यह न केवल हमीरपुर को चंडीगढ़ व दिल्ली से सबसे कम दूरी के मार्ग से जोड़ता है, बल्कि पालमपुर, जोगिंदर नगर, सरकाघाट व संधोल की ओर जाने वाले व्यापक ट्रैफिक के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। डॉ. कुमार ने अवगत कराया कि शिमला-मटौर फोरलेन के अन्य पैकेज प्रगति पर हैं, किंतु इस खंड की तीन अलग-अलग डीपीआर तैयार होने के बावजूद अंतिम निर्णय लंबित होने से परियोजना अनावश्यक रूप से विलंबित हो रही है। उन्होंने तीनों डीपीआर में से श्रेष्ठ एवं व्यावहारिक एलाइनमेंट पर शीघ्र निर्णय लेकर इसे तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करने का आग्रह किया है। डॉ. सिकंदर ने केंद्रीय मंत्री के कुशल नेतृत्व में देश भर में हुए आधारभूत ढांचे के ऐतिहासिक विस्तार की सराहना की। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि हिमाचल प्रदेश की इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को मंत्रालय की ओर से विशेष प्राथमिकता प्राप्त होगी और सभी शेष औपचारिकताओं को समयबद्ध सीमा में पूरा करवाकर निर्माण कार्य अतिशीघ्र शुरू किया जाएगा।

शाहतलाई में चरणगंगा स्थल का होगा कायाकल्प
75 लाख रुपए से मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। शाहतलाई स्थित बाबा बालक नाथ जी की तपोभूमि में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े पवित्र चरणगंगा स्थल का व्यापक सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा।

मंदिर न्यास करीब 75 लाख रुपए की लागत से यहां श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करेगा। योजना में विशेष रूप से महिला श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी गई है। सोमवार देर शाम उपायुक्त एवं मंदिर न्यास आयुक्त राहुल कुमार ने मंदिर न्यास अध्यक्ष एवं एसडीएम झंडूता आर्शिया शर्मा, मंदिर न्यास प्रभारी एवं सहायक अभियंता विजय ठाकुर तथा संबंधित अधिकारियों के साथ चरणगंगा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रस्तावित निर्माण कार्यों और सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए चैत्र मास मेले से पहले निर्माण कार्य पूरा किया जाए, ताकि देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सके। योजना के तहत चरणगंगा स्थल पर 50 हजार लीटर क्षमता का पानी का टैंक बनाया जाएगा और जलापूर्ति के लिए करीब पांच इंच व्यास की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग स्नान एवं कपड़े बदलने की व्यवस्था होगी। पुरुष श्रद्धालुओं के लिए स्नान और हाथ-मुंह धोने की सुविधा के लिए स्वच्छ पानी का तालाब विकसित किया जाएगा परिसर को सुरक्षित और आकर्षक बनाने के लिए स्नानघर के दोनों ओर साइड वॉल तथा 16 सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। उपायुक्त ने कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने पर अर्निका ठाकुर सम्मानित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। समीरपुर क्षेत्र के संगरोह गांव की प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी अर्निका ठाकुर ने राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार उपलब्धि पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अर्निका ठाकुर को सम्मानित कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। अर्निका की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश की युवा प्रतिभाएं विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर हिमाचल का गौरव बढ़ा रही हैं। अर्निका ने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अन्य युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया है।

श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बीएड दूसरे सेमेस्टर का शानदार रहा परिणाम

अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। श्री साई कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बधानी, पठानकोट कैंपस के बीएड दूसरे सेमेस्टर का परिणाम शानदार रहा। विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ग्रुप के चेयरमैन एसके पुंज, एमडी तृप्ता पुंज और सीएमडी कंवर तुषार पुंज ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नवदीप सांवल ने बताया कि बीएड दूसरे सेमेस्टर के परिणाम में अमिता देवी ने 8.30 एसजीपीए प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। शबनम और पल्लवी देवी ने 8.00 एसजीपीए के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जबकि श्रुति, विषैली सैनी, निताशा सैनी और जानवी ने 7.90 एसजीपीए के साथ तृतीय स्थान हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया। इस अवसर पर एमडी तृप्ता पुंज ने सभी विद्यार्थियों व उनके माता-पिता को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, लगन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉ. नवदीप सांवल, डॉ. जसवंत कौर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट तथा कॉलेज का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

हिंदी पखवाड़े में 9 सितंबर को होंगी भाषण व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से हिंदी पखवाड़े के तहत स्कूली विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय हिंदी भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने बताया कि हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार और उन्नयन के उद्देश्य से हर वर्ष ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर को सुबह 10 बजे संस्कृति सदन, कांगणीधार में प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें जिला मंडी के सरकारी और गैरसरकारी स्कूलों से दो-दो प्रतिभागी भाग लेंगे। भाषण प्रतियोगिता का विषय 'जनभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी की दशा और दिशा' रहेगा। इसके लिए तीन से पांच मिनट का समय निर्धारित है। निबंध लेखन का विषय 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका-हिंदी भाषा के संदर्भ में' रहेगा। निबंध की शब्द सीमा 500 से 700 शब्द और समय सीमा डेढ़ घंटा होगी।

श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित प्रसंग देता है कलियुग में सावधान रहने का संदेश: साध्वी भाग्य श्री भारती

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शाहपुर के अभिनंदन मैरिज पैलेस में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस कथा व्यास साध्वी भाग्यश्री भारती ने कथा का माहात्म्य बताते हुए कहा कि हमारे वेद ग्रंथ एक अमूल्य निधि है और वेद व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ही अनुपम ग्रंथ है।

भीष्म पितामह प्रसंग सुनाते हुए साध्वी ने बताया कि भीष्म पितामह ने परमात्मा का ध्यान करते हुए अपनी देह का परित्याग किया व परमगति को प्राप्त किया। यह प्रसंग हमे संदेश देता है कि मृत्यु तो हर एक इंसान को आनी है, लेकिन मृत्यु वही सफल है, जिसके आने पर जीवन भी सफल हो जाए, इसलिए इंसान को चाहिए कि समय रहते उस ईश्वर को जान ले तभी उसका जीवन व मृत्यु दोनो सफल हो सकते हैं।

परीक्षित प्रसंग सुनाते हुए साध्वी जी ने बताया कि उस समय तो कलिकाल का अभी प्रारंभ ही था, फिर भी राजा परीक्षित से इतना बड़ा अपराध हो गया। आज तो कलिकाल अपनी चरम सीमा पर है, तो क्या इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा, आज समाज की हालत देखें, हर व अधर्म, अनाचार, पापाचार का बोलबाला है। हर मानव घृणा, द्वेष नफरत की आग में जल रहा है, ऐसे में आवश्यकता है, एक ऐसे पथ प्रदर्शक की जो मानव को सही राह दिखा, उसके जीवन को सही दिशा दे सके और कथा के दौरान यजमान पुजन भी किया जाता है और ज्योति जलाने की रस्म भी निभाई जाती है। कथा के उपरांत ज्योति जलाने कि रस्म में, जितेंद्र सोंधी, गोकुल सोंधी वीपी शर्मा, राजेश महाजन, रेणु शर्मा ने ज्योति प्रज्वलित कर और सभी भक्तों ने आरती कि और प्रसाद को ग्रहण किया।

सम्मेलन भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाए जाएंगे सभी मुद्दे

सहकारी सभाओं के हितों की रक्षा करेगी सरकार: बिट्टू

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ (हिमकोफेड) ने मंगलवार को बचत भवन में जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की।

इस अवसर पर जिले भर की सहकारी सभाओं के प्रबंधक मंडल के सदस्यों, सचिवों, हिमकोफेड के पदाधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि सहकारी सभाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं और ये सभाएं प्रत्यक्ष रूप से आम लोगों से जुड़ी होती हैं। ये सभाएं अरबों रुपए का कारोबार कर रही हैं। इसलिए, इनकी समस्याओं का समाधान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पौने चार वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं। सहकारी सभाओं के हितों की रक्षा के लिए भी वह आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि सहकारी सभाओं को बैंकों से अधिक ब्याज दिलवाने तथा इससे संबंधित मुद्दों को भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखने, एचआर पॉलिसी और कंप्यूटरीकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना से संबंधित सभी मुद्दों को प्रदेश सरकार प्रमुखता से उठाएगी, ताकि सहकारी सभाओं के हितों की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हमीरपुर में ही करवाने का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।

सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिला हमीरपुर को मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज, नर्सिंग कालेज, प्रदेश का पहला अलाइड हेल्थ कालेज, डेडिकेटड साइंस कालेज और आयुर्वेदिक एम्स जैसे बड़े संस्थान मंजूर किए हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा भी हमीरपुर में बन रहा है। इनके अलावा हमीरपुर में कई अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के कार्य भी चल रहे हैं। यह प्रत्येक हमीरपुरवासी के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर सहायक पंजीयक रवि कुमार ने जिला की सहकारी सभाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिला में इस 368 सहकारी सभाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके सदस्यों की संख्या दो लाख से भी अधिक है। जिला सहकारी विकास संघ के अध्यक्ष यशवीर पटियाल, हिमकोफेड के पूर्व सदस्य आरसी डोगरा, हिमकोफेड के अधिकारी गौरव कुमार और अशोक शर्मा, सहकारी सभा कर्मचारी संघ के जिला महासचिव अशोक कुमार ने भी अपने विचार एवं सुझाव रखे। हिमकोफेड के बीओडी मैंबर राजेश ठाकुर व संतोष शर्मा ने मुख्यातिथि तथा अन्य अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, हिमकोफेड के अधिकारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश आनंद, मनोज शर्मा, प्रवेश ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

डीएवी कॉलेज कांगड़ा में एनसीसी भर्ती को लेकर युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह, 35 कैडेट्स का होगा चयन

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। शिक्षा व अनुशासन के प्रमुख केंद्र डीएवी कॉलेज कांगड़ा में राष्ट्र सेवा के प्रति युवाओं का उत्साह देखने को मिला। कॉलेज परिसर में 5 एचपी बटालियन के तत्वावधान में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की नई विंग के गठन के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई।

इसमें देशसेवा का जज्बा रखने वाले करीब 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी व निष्पक्ष बनाने के लिए सैन्य मानकों के अनुरूप विभिन्न चरण निर्धारित किए गए थे। प्रतिभागियों की लंबाई व वजन की जांच के बाद उनकी तार्किक क्षमता व सामान्य ज्ञान को परखने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। युवाओं ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ सभी चरणों में हिस्सा लिया। चयन प्रक्रिया 5 एचपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जेके जोसेफ के दिशा-निर्देश में संपन्न हुई। पीआई स्टाफ के पूर्व सैनिक राजिंदर कुमार ने अनुशासन एवं भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. बलजीत सिंह पटियाल व एनसीसी इंचार्ज लेफ्टिनेंट सुमित पठानिया की मौजूदगी व मार्गदर्शन से आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कॉलेज प्रबंधन ने विद्यार्थियों को एनसीसी के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। दिनभर चली कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मेरिट के आधार पर 35 योग्य छात्र-छात्राओं का एनसीसी कैडेट के रूप में चयन किया जाएगा। बटालियन प्रबंधन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा।

एलिसा शिमट जर्मनी की खूबसूरत एथलीट

एलिसा शिमट जर्मनी की प्रसिद्ध धाविका हैं, जो 400 मीटर और रिले दौड़ में विशेषज्ञता रखती हैं। उन्होंने कम उम्र में ही एथलेटिक्स में पहचान बनाई। खेल उपलब्धियों के साथ सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के कारण भी वह दुनिया भर में चर्चित हैं।

प्रीमियर लीग: पहले सप्ताह में बने कई रिकॉर्ड, आर्टेटा ने दर्ज की 150वीं जीत

चेल्सी ने 31 सेकेंड में गोल कर रचा इतिहास, प्रमोटेड टीमों ने भी दिखाया दम

एजेंसी, लंदन

इंग्लिश प्रीमियर लीग के 2026–27 सत्र के पहले गेमवीक ने ही नए सीजन के रोमांचक होने के संकेत दे दिए हैं। शुरुआती सप्ताह में आर्सेनल ने जीत से अभियान शुरू किया, हुल सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर बड़ा उलटफेर किया, जबकि चेल्सी ने सबसे तेज गोल का नया रिकॉर्ड बनाया।

आर्सेनल की शानदार शुरुआत: आर्सेनल ने प्रमोट होकर आई कोवेंट्री सिटी को 3–0 से हराया। इस जीत के साथ मैनेजर मिकेल आर्टेटा ने 249 मैचों में 150 प्रीमियर लीग जीत पूरी कर लीं। आर्सेनल का प्रमोटेड टीमों के खिलाफ घरेलू मैदान पर दबदबा भी कायम है। टीम ऐसी क्लबों के खिलाफ लगातार 46 घरेलू मैचों से अजेय है, जिसमें 41 जीत और पांच ड्रॉ शामिल हैं।

हुल सिटी का बड़ा उलटफेर: गेमवीक का सबसे बड़ा नतीजा हुल सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुकाबले में आया। प्रमोट होकर आई हुल सिटी ने यूनाइटेड को 2–0 से हराया। यूनाइटेड के पास 71.6 प्रतिशत गेंद का कब्जा था, लेकिन इसके बावजूद वह गोल नहीं कर सका। लीग इतिहास में यह पहली बार है जब यूनाइटेड को सीजन के शुरुआती मुकाबले में किसी प्रमोटेड टीम से हार मिली।

प्रीमियर लीग गेमवीक–1 के बड़े रिकॉर्ड

- आर्टेटा: 249 मैचों में 150 लीग जीत
- हुल सिटी: यूनाइटेड पर 2-0 की ऐतिहासिक जीत
- लिवरपूल: लगातार 14 सत्र से शुरुआती मैच में अजेय
- जोआओ पेड्रो: 31 सकेंड में सबसे तेज शुरुआती गोल
- तीन प्रमोटेड टीमों में से दो ने पहला मैच जीता

लिवरपूल का रिकॉर्ड कायम: नए मैनेजर एंडोनी इराओला के नेतृत्व में लिवरपूल ने न्यूकैसल से 2–2 का ड्रॉ खेला। इसके साथ टीम का शुरुआती मुकाबले में अजेय रहने का सिलसिला लगातार 14 सत्र तक पहुंच गया। न्यूकैसल के खिलाफ डोमिनिक स्जोबोस्लाई ने 98 मिनट और छह सेकंड पर पेनल्टी को गोल में बदलकर लिवरपूल को एक अंक दिलाया।

अन्य मुकाबले: इप्सविच टाउन ने सुंदरलैंड को 2–1 से हराकर 1993–94 के बाद पहली बार शुरुआती मुकाबला जीता। जैक क्लार्क ने 90वें मिनट में विजयी गोल किया। ब्रेंटफोर्ड ने टॉटेनहम को 3–0 से हराकर शीर्ष स्तर पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। एवर्टन ने क्रिस्टल पैलेस को 2–0 और लीड्स यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1–0 से हराया।

चेल्सी का रिकॉर्ड: गेमवीक के आखिरी मुकाबले में चेल्सी ने फुलहम को 3–1 से मात दी। जोआओ पेड्रो ने केवल 31 सेकंड में गोल कर सीजन के शुरुआती मुकाबले में सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड बनाया। चेल्सी की शुरुआती एकादश की औसत उम्र 24 साल 43 दिन रही, जो पहले गेमवीक में सबसे युवा थी।

बारिश ने रोका श्रीलंका का संघर्ष तीसरे दिन 8 विकेट पर 265 रन

एजेंसी, कोलंबो

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन मगंलवार (25 अगस्त) का अंतिम सत्र बारिश से प्रभावित हुआ और खेल जल्दी समाप्त। तीसरे दिन 257 रन बने और 6 विकेट गिरे। श्रीलंका ने 83.4 ओवर में 8 विकेट पर 265 रन बनाए। भारत 238 रनों से आगे है। श्रीलंका को फॉलोऑन बचाने के लिए 39 रन चाहिए। लहिरू कुमारा 8 और सोनल दिनुशा 85 रन बनाकर क्रीज पर। 35 रनों की साझेदारी हुई।

चायकाल के बाद के सत्र में केशारा नुवंथा 18 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने दूसरे सत्र में 3 विकेट लिए थे और 86 रन बनाए थे। दूसरे दिन भारत ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी। तीसरे दिन

श्रीलंका फॉलोऑन के संकट में, भारत से अब भी 238 रन पीछे

की शुरुआत श्रीलंका के लिए कामिल मिशारा और पसिंदू सूरियाबंदारा ने सकारात्मक की, लेकिन दिन के सातवें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने मिशारा को आउट कर मेजबानों को तीसरा झटका दिया। इसके बाद पसिंदू सूरियाबंदारा ने कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर पारी को संभाला। पसिंदू ने करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया। दूसरे दिन के अंत तक श्रीलंका ने 8 रन पर दो विकेट गंवा दिए थे। गॉल टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया सीरीज में 1–0 से आगे है और कोलंबो में उसकी नजरें सीरीज कब्जाने पर होंगी।

स्पोर्ट्स विंडो

जोआओ फोंसेका पेट की चोट के कारण अमेरिकी ओपन से बाहर

एजेंसी, न्यूयॉर्क। ब्राजील के युवा टेनिस खिलाड़ी जोआओ फोंसेका पेट की चोट के कारण अमेरिकी ओपन 2026 से बाहर हो गए हैं। दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। 20 वर्षीय फोंसेका इस साल शानदार प्रदर्शन के बाद अमेरिकी ओपन में खिताब के दावेदारों में शामिल थे। उन्होंने फ्रेंच ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था, जहां उन्होंने दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को भी हराया था। फोंसेका ने कहा कि पेट की चोट को लेकर जांच और उपचार शुरू होने के बाद उन्हें और उनकी टीम को लगा कि पूरी तरह फिट होने के लिए उन्हें अभी और समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ओपन उनके लिए बेहद खास टूर्नामेंट है और इससे हटने का फैसला आसान नहीं था। फोंसेका ने कहा कि वह जल्द से जल्द वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे। फोंसेका अमेरिकी ओपन से हटने वाले प्रमुख पुरुष खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं। इससे पहले जैनिक सिनर, होल्गर रूने और जैक ड्रेपर भी चोटों के कारण टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले चुके हैं।

जीसीटी ग्रैंड फिनाले: फाइनल में पहुंचे प्रज्ञाननंदा, कारुआना से होगा मुकाबला

एजेंसी, सेंट लुई (अमेरिका)। भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंदा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रैंड शतरंज टूर (जीसीटी) के ग्रैंड फिनाले के फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। प्रज्ञाननंदा ने दूसरे क्लासिकल मुकाबले में जीत के बाद छह अंकों की बढ़त बनाई। इसके बाद लगातार दो रैपिड मुकाबले जीतकर उन्होंने 17-3 की अजेय बढ़त हासिल कर फाइनल में प्रवेश पक्का किया। ब्लिट्ज के पहले गेम में जीत से उनका स्कोर 19 अंक हो गया। कीमर ने अंतिम तीन ब्लिट्ज गेम जीतकर अंतर जरूर कम किया, लेकिन प्रज्ञाननंदा की जीत नहीं रोक सके। फाइनल में प्रज्ञाननंदा का सामना मौजूदा चैंपियन और खिताब के प्रबल दावेदार अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। कारुआना ने हमवतन वेस्ली सो को 18-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। जीसीटी फाइनल की कुल पुरस्कार राशि 4.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। विजेता को 2 लाख डॉलर और उपविजेता को 1.25 लाख डॉलर मिलेंगे। तीसरे स्थान के प्लेऑफ में कीमर और वेस्ली सो आमने-सामने होंगे।

मुरलीधरन और वेटोरी से मिली सीख ने मेरी गेंदबाजी निखारी: जीशान अंसारी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत के युवा लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने कहा कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ रहते हुए महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन और डेनियल वेटोरी से मिली सीख ने उनकी गेंदबाजी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। 26 वर्षीय जीशान ने कहा कि मुरलीधरन और वेटोरी ने उन्हें गेंदबाजी से जुड़ी कई ऐसी बारीकियां सिखाईं, जिनके बारे में उन्हें पहले जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों दिग्गजों से मिली सीख पर लगातार अमल करने से उनका खेल आगे और बेहतर होगा। जीशान अंसारी 2016 में भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम का हिस्सा थे, जिसमें ईशान किशन, ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे। आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा चुने जाने के बाद उनके करियर को नई दिशा मिली। अंसारी ने बताया कि यूपी टी20 लीग में पूर्व भारतीय स्पिनर पीयूष चावला भी उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं। चावला ने उनकी गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, जिनसे वह लगातार सीख रहे हैं।

प्रतीति और मयंक एशियाई जूनियर शतरंज में खिताब के करीब

एजेंसी, मुंबई। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रतीति बोरदोलोई और मयंक चक्रवर्ती मंगलवार को यहां आठवें दौर में जीत हासिल करके एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में खिताब के करीब पहुंच गए। प्रतीति ने प्रिशिता गुप्ता को हराकर अपने अंको की संख्या संभावित आठ में से सात पर पहुंचा दी है। वह अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी तुर्कमेनिस्तान की महिला कैंडिडेट मास्टर शोहरादोवा लैला से एक अंक आगे है जिन्होंने दक्षिता कुमावत के साथ बाजी ड्रॉ खेली। उनके छह अंक हैं। कजाकिस्तान की मारिया खोल्यावको और भारत की श्राव्याश्री भीमरसेट्टी ने भी जीत दर्ज करके अपना स्कोर छह पर पहुंचा दिया है। ओपन चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने दक्ष गोयल को हराकर खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। उनके अब सात अंक हैं और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी रूस के इंटरनेशनल मास्टर आर्टेम पिंगिन से आधा अंक आगे हैं। रूस के खिलाड़ी ने भारत के इंटरनेशनल मास्टर विग्नेश अद्वैत वेमुला को हराकर अपने अंकों की संख्या 6.5 पर पहुंचा दी है। शर्नार्थी वीरेश को अपूर्व कांबले ने ड्रॉ पर रोका। इससे उनके छह अंक हो गए हैं।

महिला डीपीएल: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हराया

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के महिला वर्ग में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल दिल्ली क्वींस को 11 रन से हरा दिया। बारिश के कारण आठ ओवरों तक सीमित रहे इस मुकाबले में साउथ दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 68 रन बनाए, जिसके जवाब में सेंट्रल दिल्ली की टीम 5 विकेट पर 57 रन ही बना सकी।

अरुण जेटली स्टेडियम में साउथ दिल्ली की कप्तान श्वेता सहरावत ने 21 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 26 रन बनाकर टीम की पारी को संभाला। तनिषा सिंह ने भी 13 गेंदों पर 19 रन का उपयोगी योगदान दिया। इससे पहले प्रिया पुनिया ने तेज शुरुआत करते हुए चार गेंदों में नौ रन बनाए।

सेंट्रल दिल्ली की ओर से सुमिति सोनी और मेधावी बिधूड़ी ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। 69 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट्रल दिल्ली क्वींस की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम ने पहली ही गेंद पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। इसके बाद दीक्षा शर्मा ने 16 गेंदों में चार चौकों की मदद से 22 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन छठे ओवर में उनके रन आउट होने के बाद टीम की मुश्किलें बढ़ गईं।

अरुषि गोयल ने 14 और मोनिका ने नौ रन बनाए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह पर्याप्त नहीं रहा। साउथ दिल्ली की ओर से रूपाली विश्व मोहन, दिशा नागर और एकता भदाना ने एक-एक विकेट लिया। अनुशासित गेंदबाजी और चुस्त क्षेत्ररक्षण के दम पर साउथ दिल्ली ने मुकाबला 11 रन से अपने नाम कर लिया।

भारत के लिए डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह बनाना नहीं होगा आसान: द्रविड़

एजेंसी, मुंबई। भारत के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहुंचना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा। भारत इस समय अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है और फाइनल में जगह बनाने के लिए उसे अपने बाकी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करना होगा। द्रविड़ ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ भारत ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी असली परीक्षा होगी। अक्टूबर में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे पर भारत दो टेस्ट मैच खेलेगा।

द्रविड़ के मुताबिक न्यूजीलैंड की परिस्थितियां भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी, खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए, जिन्हें वहां खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की कमी भी महसूस होने की बात कही। द्रविड़ ने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर धैर्य रखने की सलाह दी और कहा कि लाल गेंद के घरेलू क्रिकेट में अनुभव हासिल करने से वह भविष्य में टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं।

एशियन गेम्स के लिए हिमाचल की 4 बेटियों को भारतीय महिला कबड्डी टीम में जगह

अनंत ज्ञान

एसपी जैरथ, नाहन। एशियन गेम्स के लिए चयनित भारतीय महिला कबड्डी टीम में हिमाचल प्रदेश की चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप राणा ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। टीम में सिरमौर की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं पूर्व भारतीय कप्तान रितु नेगी, हिमाचल महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा, सोलन की ज्योति ठाकुर और मंडी की भावना ठाकुर शामिल हैं। इनके अलावा संजू देवी, पूजा कजला, रितु शेरोंन, पिंकी राय, मनीषा कुमारी, राजरानी और नीतिका कुमारी भी टीम का हिस्सा हैं।

सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शरोग गांव की रितु नेगी ने आठवीं कक्षा से कबड्डी का सफर शुरू किया। वर्ष 2006 में उनका चयन स्पोर्ट्स हॉस्टल बिलासपुर के लिए हुआ, जहां उन्होंने आठ वर्ष प्रशिक्षण लिया। रितु ने एशियन गेम्स 2018 में रजत और हांगझोऊ एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वह 2025 महिला कबड्डी विश्व कप में भी भारतीय टीम की स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा रहीं। उन्हें 2018 एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ राइट कॉर्नर डिफेंडर चुना गया था। वर्तमान में वह भारतीय रेलवे में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। शिलाई के मिल्लाह गांव की पुष्पा राणा भी भारतीय कबड्डी में हिमाचल का प्रमुख नाम हैं। 11 जनवरी 1998 को जन्मीं पुष्पा ने पिता जयपाल और भाई संजीव से कबड्डी की शुरुआती बारीकियां सीखीं। राइट रेडर के रूप में खेलने वाली पुष्पा की कप्तानी में हिमाचल ने नेशनल गेम्स में लगातार तीन स्वर्ण पदक जीते हैं। वह 2025 महिला कबड्डी विश्व कप, 2023 एशियन गेम्स, 2025 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप और 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीमों का हिस्सा रही हैं। प्रदेश की चार खिलाड़ियों का एशियन गेम्स टीम में चयन हिमाचल में कबड्डी प्रतिभाओं की मजबूत मौजूदगी को दर्शाता है।

मुथैया मुरलीधरन, डेनियल विटोरी ने मेरी गेंदबाजी को निखारने में मदद की: जीशान

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत के युवा लेग स्पिनर जीशान अंसारी ने कहा कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिग्गज स्पिनरों मुथैया मुरलीधरन और डेनियल वेटोरी से मिले सबक से उन्हें अपने खेल को निखारने में मदद मिली। ईशान किशन, ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ियों के साथ भारत की अंडर-19 विश्व कप 2016 टीम का हिस्सा रहे जीशान के करियर में तब नया मोड़ आया जब आईपीएल 2025 के लिए सनराइजर्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया।

अंसारी ने पीटीआई वीडियोज से कहा कि जब मैं सनराइजर्स में था, तब मुझे मुथैया मुरलीधरन और डेनियल वेटोरी से काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने मुझे गेंदबाजी के बारे में कई ऐसी बातें बताईं जो मुझे पता नहीं थीं। उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा है, उससे मुझे बहुत मदद मिली है। अगर मैं उनसे मिली सीख पर अमल करता रहूंगा तो मेरा खेल बेहतर होता जाएगा। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी को यूपी टी20 लीग के दौरान पूर्व भारतीय स्पिनर पीयूष चावला के मार्गदर्शन से भी फायदा मिल रहा है।

चीन ने बनाया हवा से हवा में वार करने वाला हाइपरसोनिक व्हीकल

एजेंसी, बीजिंग

चीनी सेना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल विकसित किए हैं जो हवा से हवा में मार करने वाले हथियार दाग सकते हैं। इसका मकसद हजारों मील दूर मौजूद कमांड-एंड-कंट्रोल एयरक्राफ्ट जैसे अहम लक्ष्यों को निशाना बनाना है।

इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, यह कामयाबी चीन की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वह अपने मिसाइल भंडार का इस्तेमाल लगभग हर तरह के मिलिट्री काम के लिए करना चाहता है। चीन के पास 3,150 से ज्यादा बैलिस्टिक हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ छह महीने की लड़ाई के बाद अमेरिका को एयर डिफेंस मिसाइलों और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की सप्लाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। **अमेरिका के लिए गंभीर खतरा:** टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एक व्यक्ति के हवाले से बताया गया कि चीन ने कुछ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने की क्षमता भी जोड़ी है और कई तरह की मिसाइलों में एंटी-शिप क्षमताएं भी शामिल की हैं। चीन के साथ संघर्ष के दौरान ऐसे हथियार अमेरिकी हवाई अभियानों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। टैंकर, हवाई चेतावनी और नियंत्रण वाले विमान और यहां तक कि ई-4बी नाइटवॉच जैसे फ्लाइंग कमांड पोस्ट जैसे सपोर्ट एयरक्राफ्ट का मकसद लड़ाई के क्षेत्र से दूर रहकर काम करना होता है।

अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटाया

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिका ने सीरिया को आधिकारिक रूप से अपनी 'स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म' (आतंकवाद प्रायोजक देश) की सूची से हटा दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के बाद विदेश विभाग का यह फैसला प्रभावी हो गया। यह कदम पहले की गई घोषणा और उसके बाद कांग्रेस में हुई समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद उठाया गया है। इस फैसले के साथ सीरिया पर उस विशेष श्रेणी से जुड़े कई कानूनी प्रतिबंधों का असर समाप्त हो जाएगा, जिनमें अमेरिकी सहायता, रक्षा संबंधी निर्यात और कुछ वित्तीय लेनदेन पर पाबंदियां शामिल थीं। अमेरिकी प्रशासन का यह निर्णय सीरिया के प्रति वॉशिंगटन की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने भी नियमों में संशोधन कर सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों से संबंधित नियामकीय प्रावधानों से हटाने की पुष्टि की है।

ऑपरेशन सिंदूर का असर अब भी जारी पूर्व सीडीएस ने समझाया रणनीतिक महत्व

एजेंसी, नई दिल्ली

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिक प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राजनीति और युद्ध को एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सैन्य शक्ति राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही विस्तार होती है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के बीच गहरे संबंध को भी रेखांकित किया।

जनरल चौहान के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर की मुख्य सैन्य कार्रवाई समाप्त हुए करीब 15 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके रणनीतिक प्रभाव अभी भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत और विदेशों में रणनीतिक विशेषज्ञों के लिए लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर को पिछली सैन्य कार्रवाइयों से अलग बताते हुए कहा कि इसमें रणनीति को लेकर किसी तरह की अनिश्चितता या हिचकिचाहट नहीं थी।

उन्होंने उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद किए गए हवाई हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रणनीतिक सोच और सैन्य कार्रवाई के नए स्वरूप को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अभियान ने भारत की रणनीतिक सोच को नया आयाम दिया और सैन्य कार्रवाई के प्रभावों पर विशेषज्ञों की रुचि लगातार बनी हुई है।

बसपा अपने बलबूते पर लड़ेगी पंजाब विधानसभा का चुनाव: मायावती

एजेंसी, लखनऊ

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि पंजाब विधानसभा का चुनाव बसपा अकेले दम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन और चुनावी समझौतों से उनकी पार्टी को नुकसान होता है। अपने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि विरोधियों के सभी हथकंडों का डटकर सामाना करते हुए बेहतर रिजल्ट की तैयारी रखनी है। बसपा प्रमुख ने मंगलवार को लखनऊ स्थित बसपा के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब के पार्टी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे।

बैठक के बाद मायावती ने घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि पार्टी कर्मठ, ईमानदार लोगों को उम्मीदवार बनाएगी। मायावती ने कहा कि बसपा पंजाब विधानसभा का चुनाव भी यूपी और उत्तराखंड की तरह बिना किसी गठबंधन और समझौता के अपने बलबूते लड़ेगी। इसकी खास वजह चुनावी गठबंधन से बसपा को सीट व वोट दोनों में होने वाले नुकसान से बचाना है। पार्टी के लोगों के मनोबल को गिरने से बचाना है। इसके अलावा बसपा प्रमुख ने पार्टी संस्थापक कांशीराम की 9 अक्टूबर को होने वाली पुण्यतिथि कार्यक्रम की तैयारी और इसे सफल बनाने का निर्देश दिया है।

पाकिस्तान में फिर फैल रहा लश्कर का नेटवर्क, भारत में घुसपैठ की साजिश

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय खुफिया एजेंसियों की हालिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिंध प्रांत में पिछले एक साल के दौरान संगठन ने सात नए मरकज और मस्जिदें बनाई हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह गतिविधियां चिंता का विषय बनी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन निर्माणों और कथित आतंकी सुविधाओं के लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता मिलने की बात सामने आई है। इसके अलावा संगठन चैरिटी की आड़ में विदेशों से भी बड़े पैमाने पर चंदा जुटाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि पाकिस्तान में संगठन के बढ़ते नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार गतिविधियों और संदिग्ध नेटवर्क पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खुफिया एजेंसियां सीमा पार आतंकी नेटवर्क पर नजर रख रही हैं। सिंध में लश्कर के विस्तार और फंडिंग के खुलासे ने भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

सोना 190 रुपए बढ़कर 1.62 लाख पर पहुंचा चांदी 1,945 सस्ती होकर 2.43 लाख पर आई

एजेंसी, मुबई

सोने की कीमतों में 25 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए बढ़कर 1.62 लाख रुपए हो गया है। वहीं एक किलो चांदी की कीमत 1,945 रुपए कम होकर 2.43 लाख रुपए आ गई।

इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 29 हजार रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को 10ग्र सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.62 लाख रुपए पर पहुंच गया है।

वहीं, चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.43 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था। कोटक सिक्युरिटीज के सीनियर वीपी एंड कमोडिटी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी कहते हैं कि सोने को आम निवेशकों के साथ ही दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों जैसे आरबीआई का भी सपोर्ट हासिल है, जो लगातार सोना खरीद रहे हैं।

आगे मुश्किल हालात में भी सोने में तेजी बनी रहेगी। यदि हालात सुधरे तो चांदी में भी उछाल दिख सकता है। अभी जो भावी हालात नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक दिसंबर तक सोने की कीमत 1.70 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। चांदी की कीमत भी 3 लाख रुपए तक जा सकती है।

सेंसेक्स में 100 अंक की बढ़त और निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा

एजेंसी, मुबई। शेयर बाजार में मंगलवार को को बढ़त है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 77,500 पर कारोबार कर रहा हैं। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की तेजी है, ये 24,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

मीडिया और फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी है। अन्नू प्रोजेक्ट्स का आईपीओ आज से ओपन हो गया है। कंपनी इसके जरिए 175.06 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इन आईपीओ में 28 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे।